R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 18
16 से 30 जून 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

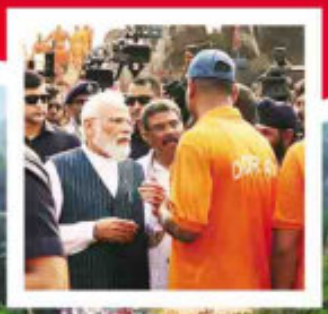

ओडिशा ट्रेन हादसा
गड़बड़ी या साजिश ?

कहां है रेल हादसों को 'शून्य' करने का वादा और दावा करने वाले

लोको पायलट से लेकर रनिंग स्टाफ और ट्रैकमैन भारी दबाव में

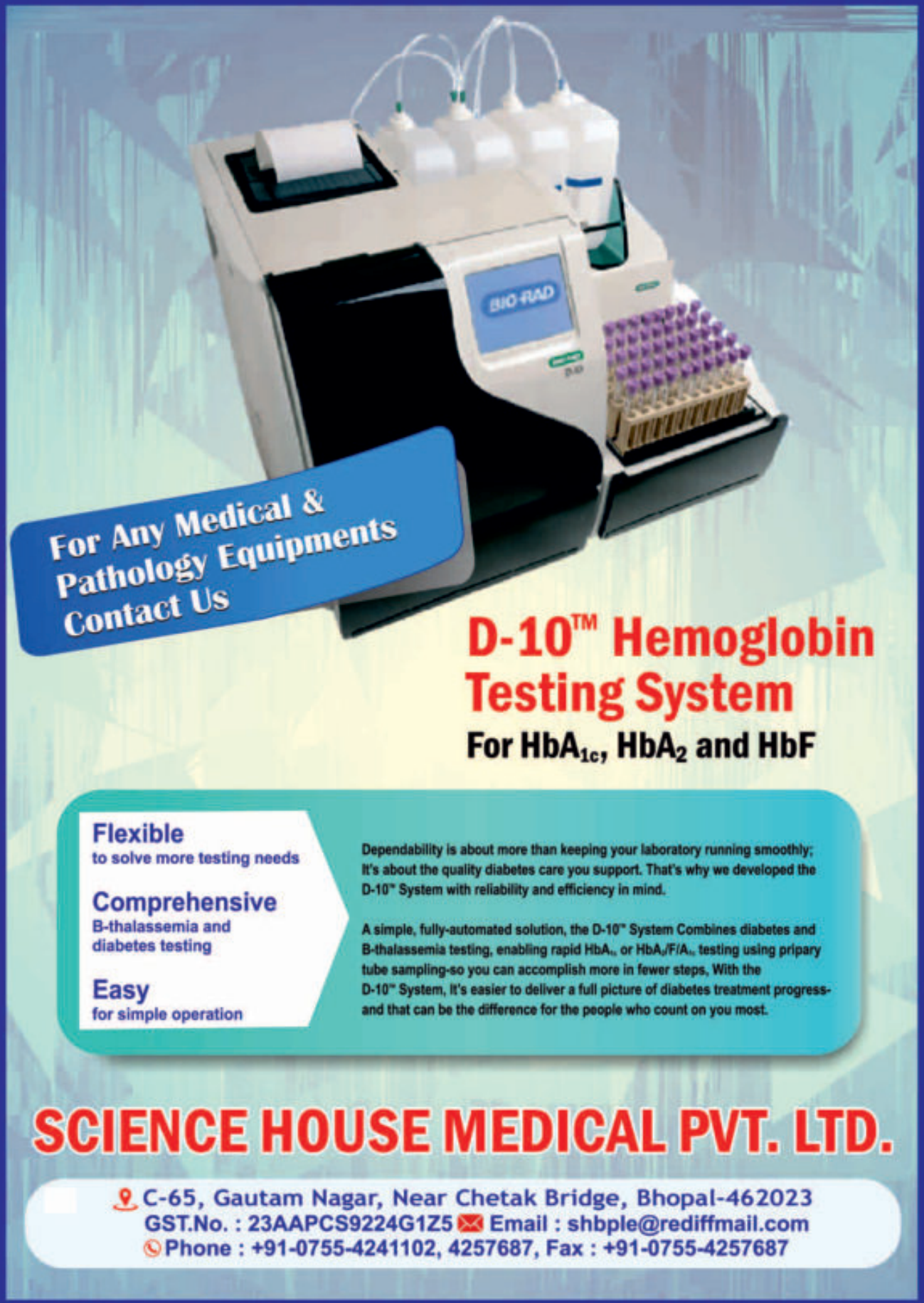

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

वल्लभगाथा

9 | पुरुषोत्तम शर्मा को नहीं...

मप्र कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अफसर व स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने राज्य सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है। शर्मा ने वीआरएस का आवेदन जरूर दिया है, लेकिन उस पर पेंच फंस सकता है।

राजपथ

10-11 | महिलाओं के हाथ जीत की पतवार

मप्र के विधानसभा चुनावों में लगभग 5 महीनों का समय ही बचा है। ये समय आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसने राजनेताओं की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। आंख खुलने से लेकर बिस्तर पर गिरने और फिर शायद...

चर्चा में

15 | चीतों की मौत ने गिराए...

मप्र के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाने के साथ ही आसपास के इलाकों में जमीन के दाम भी चीतों की रफ्तार की तरह बढ़ने लगे थे। कुछ ही महीनों में दाम पांच गुना तक बढ़ गए थे। अब एक के बाद एक 6 चीतों की मौत से इस प्रोजेक्ट को लेकर कई उलझनें...

लापरवाही

18 | आठ हजार जल स्त्रोत सूखे

एक तरफ प्रदेश में पानी का संकट बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर 50 फीसदी ऐसे जल स्त्रोत हैं, जिनका प्रदेश में उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। अगर इन सभी स्त्रोतों का उपयोग किया जाए तो प्रदेश में जल संकट काफी हद तक समाप्त हो सकता है। प्रदेश में इसको लेकर क्या स्थिति है...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारतीय रेल इस विशाल देश की जीवनरेखा है। रोजाना ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने वाली यह रेल प्रणाली कितनी कमजोर है, इसका ताजा प्रमाण ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना है। इस दुर्घटना में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 289 लोगों की मौत हुई है जबकि कुछ एजेंसियों द्वारा 1000 से अधिक की मौत का दावा किया जा रहा है। यह हादसा रेलवे की गड़बड़ी है या किसी की साजिश इसकी जांच सीबीआई कर रही है।

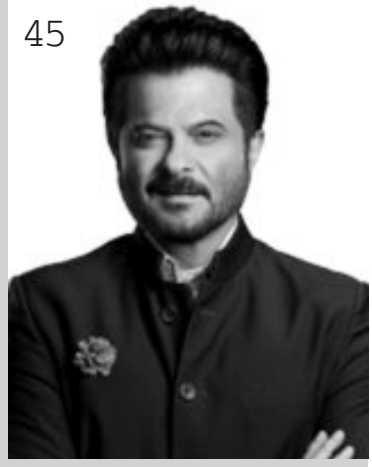

राजनीति

30-31 | मिशन 2024 की तैयारी...

दिल्ली में कांग्रेस की मंथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के सामने इस समय तीन बड़े मुद्दे हैं, जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। पहला- विपक्षी एकता के टेढ़े सवालों को सुलझाना। दूसरा- केजरीवाल को विपक्षी एकता में शामिल करने या नहीं करने पर फैसला लेना। तीसरा-राजस्थान...

राजस्थान

35 | लड़ाई का अंजाम क्या होगा ?

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ने सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि दोनों के बीच कोई समस्या नहीं है, लगभग उतनी ही बार, जितनी बार उन्होंने एक-दूसरे को निशाना बनाया है। पिछले इतिहास को खंगाला जाए तो 200 सदस्यीय...

बिहार

37 | नीतीश पर विश्वास नहीं

क्या 2024 के आम चुनावों में मोदी विरोधी मुहिम की अगुवाई नीतीश कुमार को मिलने में पेच फंसने लगा है? मोदी के खिलाफ विपक्षी गोलबंदी की अगुवाई को लेकर क्या गतिरोध पैदा हो गए हैं? क्या कांग्रेस विपक्षी गोलबंदी में खुद की अगुवाई का संदेश...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

हिंदुत्व अब चुनावी मुद्दा नहीं...

शा*यर बशीर बद्र का एक शेर है...*

सात संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें
आज इंसां को मोहब्बत की जरूरत है बहुत

कुछ इसी तर्ज पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भाजपा को नसीहत दी है कि देश में समस्याओं की भरमार है, अतः सरकार उस ओर ध्यान दे। हिंदुत्व अब कारगर नहीं होगा, इसलिए पार्टी और सरकार इसको दरकिनार कर अब विकास पर फोकस करे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने यह नसीहत अपने मुखपत्र ऑर्गनाइजर के जरिए दी है। ऑर्गनाइजर ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भाजपा को आगे भी चुनाव जीतते रहना है तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफी नहीं होगा। भाजपा के विषय में यह चर्चा है कि 2014 से ही पूरी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के आसपास केंद्रित हो गई है। अनजानी रणनीति के अंतर्गत पार्टी ने राज्यों में प्रभावी नेतृत्व विकसित नहीं किया और पार्टी का पूरा चुनावी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास सिमटा रहा। उप्र, उत्तराखंड, हरियाणा सहित कई राज्यों में पार्टी का यह दांव सफल साबित हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जमकर वोट पड़े और इन राज्यों में अभूतपूर्व बहुमत से भाजपा की सरकारें बनीं। लेकिन कुछ समय बाद ही कुछ राज्यों में यह कार्ड अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका और पार्टी को पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आक्रामक चुनाव प्रचार भी विपक्षी दलों के मजबूत स्थानीय नेतृत्व के क्षेत्रीय करिश्मे के सामने ढह गया। कर्नाटक में तो पार्टी ने जैसे अपनी हार सुनिश्चित करने की रणनीति ही बना ली थी। राज्य के मतदाताओं का स्वभाव ऐसा है कि उन्होंने हमेशा से राष्ट्रीय नेतृत्व की बजाय स्थानीय नेतृत्व को ही प्राथमिकता दी है। इस सच को जानते हुए भी लगातार लिंगायत नेता येदियुरप्पा को दरकिनार किया गया, उन्हें अपने बेटे के लिए एक सीट पाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे जिताऊ और जमीनी नेताओं का टिकट काटकर उन्हें उपहार के तौर पर कांग्रेस की झोली में डाल दिया गया। पार्टी के इन कार्यों का वही परिणाम होना था जो हुआ, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि भाजपा ने इस तरह की आत्मघाती रणनीति क्यों अपनाई? चर्चा है कि स्थानीय नेतृत्व की गहरी उपेक्षा से संघ नाराज है क्योंकि कर्नाटक में उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। कर्नाटक की हार केवल एक राज्य की हार तक सीमित नहीं है। इसके जरिए आरएसएस संघ की जिस विचारधारा को दक्षिण में धार देना चाहता था, वह इस चुनावी हार से वह लंबे अरसे के लिए कुंद पड़ती दिखाई दे रही है। हिंदुत्व का मुद्दा संघ और भाजपा के वैचारिक विस्तार का सबसे सशक्त दांव सिद्ध हुआ है। आज भी भाजपा अपने इसी कोर एजेंडे के सहारे विभिन्न राज्यों में आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में इसका पूरा उपयोग करने के बाद भी चुनावी सफलता नहीं हासिल की जा सकी, इसकी सीमा को लेकर चर्चा होने लगी है। भाजपा के एक नेता इस बात से इनकार करते हैं कि हिंदुत्व या ब्रांड मोदी पर कोई सवाल खड़ा हुआ है। वे कहते हैं कि कर्नाटक में राज्य सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के कारण ही पार्टी एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। यदि प्रधानमंत्री प्रचार न करते तो यह आंकड़ा 40 के आसपास जाकर ही रुक जाता। अब देखना यह है कि भाजपा संघ की नसीहत को कितनी गंभीरता से लेती है। **– राजेन्द्र आगाल**

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 18, पृष्ठ-48, 16 से 30 जून, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

नशाखोरी पर रोक कब?

प्रदेश सहित देशभर में नशा चरम पर पहुंच रहा है। शहर में भी नशा युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब कोई न कोई परिजन अपने बच्चों की इस ड्रग्स की नशाखोरी से दुखी होकर पुलिस तक नहीं जाता। इसको लेकर सरकार कड़े कदम उठाए।

● **धर्मेंद्र सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

रिझा रहीं चुनावी पार्टियां

चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस में घोषणाओं की एक दौड़ सी लगी है और चुनाव से पहले का समय घोषणाकाल जैसा नजर आ रहा है। वोटरों को रिझाने के लिए सत्ता में काबिज भाजपा सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है।

● **पूनम मिश्रा,** भोपाल (म.प्र.)

तनाव में हेल्थकर्मी

कोरोना की लहर के दौरान कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टॉफ में तनाव का स्तर काफी बढ़ गया था। वह समय हेल्थकर्मियों के लिए बहुत ही तनाव भरा था। काफी मशक्कत के बाद आज भी वे इस तनाव से उबर नहीं पा रहे हैं।

● **देवांश वर्मा,** ग्वालियर (म.प्र.)

चुनावी तैयारियां जोरों पर

मप्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के साथ-साथ पार्टियों में दलबदल का दौर भी शुरू हो चुका है और आने वाले समय में भी यह दलबदल अभियान देखने को मिलेगा। कई भाजपाई कांग्रेस में शामिल होने के लिए उतावले हैं, तो वहीं कई कांग्रेसी भाजपा की ओर ताक रहे हैं। वहीं अन्य पार्टियों के नेता भी बगावत करने वाले नेताओं को साधने में लगे हैं। वहीं मप्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जहां कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लगवा चुके हैं, वहीं आलाकमान का कहना है कि कांग्रेस बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी। उधर, भाजपा के कई नेता शिवराज सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं।

● **पूर्वा पांडे,** राजगढ़ (म.प्र.)

मजदूर हो रहे परेशान

देशभर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार की यह जड़ बड़े राज्य से लेकर छोटे गांवों तक फैली हुई है। ग्राम पंचायतों में खुलेआम भ्रष्टाचार मचा हुआ है जिससे मजदूरों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते मजदूर बेरोजगार बने हुए हैं साथ ही सरकारी कार्यालयों में अराजकता भी बढ़ रही है और लोग पलायन पर मजबूर है। सरकार को इस विषय में ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है, जिससे मजदूरों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

● **अमित कुमार,** जबलपुर (म.प्र.)

मजेदार होगा 2024 का लोकसभा चुनाव

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से पार्टियों ने कमर कस ली है। इसमें कई राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां जीत के लिए अलग-अलग हथकंडे अपनाने की रणनीति बना रही हैं। अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा विरोधी हैं, इसलिए भाजपा को हराने में क्षेत्रीय पार्टियों की विफलता के बाद भाजपा विरोधी वोटर कांग्रेस की ओर लौटेगा तो क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होंगी। वहीं कई पार्टियां कांग्रेस को मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने को भी तैयार बैठी हैं। इससे भाजपा सतर्क हो गई है और रणनीति पर काम करने में लगी है।

● **संतोष साहू,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

कांग्रेस बोली- राजस्थान में सबकुछ ओके

राजस्थान में गुटबाजी खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान अब गंभीरता से जुट गया है। 29 मई को हुई बैठक को इस दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। आलाकमान ने यह संदेश देने की कोशिश की कि गहलोत और पायलट के बीच चल रहा झगड़ा सुलझ गया है। इसके उलट सचिन पायलट ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो कथा पोस्ट की उसने फिर संदेह खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में पायलट आम जनता के साथ नजर आ रहे हैं। पर, न तो कांग्रेस का चुनाव निशान कहीं नजर आता है और न ही पायलट के अलावा पार्टी का कोई दूसरा नेता इसमें है। इससे यह सवाल तो उठ ही रहा है कि क्या पायलट ने अपनी अलग पार्टी बनाने का इरादा छोड़ा नहीं है। पायलट और गहलोत के आपसी विवाद को तो भाजपा भी मुद्दा बनाना चाह रही है। प्रधानमंत्री ने अजमेर की रैली में नाम लिए बिना इसका उल्लेख भी कर दिया। 8 महीने में प्रधानमंत्री की राजस्थान में यह छठी रैली थी। कांग्रेस राजस्थान में यही उम्मीद लगाए है कि भाजपा ने कोई चेहरा न दिया और प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा तो कर्नाटक का दोहराव दिखेगा राजस्थान में।

जल्द होगा शिंदे कैबिनेट का विस्तार

महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को एक साल होने वाला है। लेकिन अब एक बार फिर से राज्य में कुछ बड़ा होने की बातें हो रही हैं। इन बातों को बल एक मुलाकात दे रही है। यह मुलाकात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बीच हुई थी। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री शिंदे ने ट्वीट कर कहा, हमने तय किया है कि शिवसेना और भाजपा लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव सहित आगामी सभी चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा, हम दिल्ली आते रहते हैं। राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। चाहे वह विकास परियोजनाएं हों, मराठवाड़ा जल ग्रीड परियोजना का मुद्दा हो, कोंकण का जल मुद्दा हो या किसानों का संकट हो। हालांकि दोनों दलों ने केंद्रीय भाजपा नेतृत्व के साथ बैठक के पीछे के सटीक एजेंडे का खुलासा नहीं किया है, यह यात्रा राज्य में शिंदे-फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरा होने से पहले हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में लंबे समय से लंबित कैबिनेट विस्तार के साथ-साथ केंद्र सरकार में मंत्री पद के लिए शिंदे की अगुवाई वाली सेना की मांग और लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर भी मंथन हुआ है।

एक होंगे दो गुलाबी गमछे

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस और 15 सालों तक सत्ता में रह चुकी भाजपा दोनों ही दल पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने एक पत्र जारी करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को विलय और किसी भी प्रकार के गंठबंधन के लिए तैयार रहने को कहा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जेसीसीजे एक बार फिर गंठबंधन कर आगामी चुनाव में अपना दमखम दिखा सकती है। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जेसीसीजे ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आगामी चुनाव से पहले जेसीसीजे और बीआरएस के बीच गठबंधन हो सकता है। छत्तीसगढ़ की सियासत में दो गुलाबी गमछा एक साथ देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक जोगी कांग्रेस या बीआरएस की ओर से अधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि किसी दक्षिण भारत का राजनीतिक दल गठबंधन में हो।

भाजपा-मनसे में गठबंधन

महाराष्ट्र की सियासत ने पिछले एक साल से कई रंग बदले हैं। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट, फिर शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन कर भाजपा की नई सरकार का गठन। उसके बाद एनसीपी नेता अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने की अटकलें और अब बंद कमरे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात। इस मुलाकात ने अब कई चर्चाओं को हवा दे दी है। इस दौरान मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने आवास पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अचानक हुई इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में नए-नए कयास लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का मुद्दा क्या रहा, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चा है कि बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा-मनसे के बीच गठबंधन हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में नया संकेत उद्धव ठाकरे की पार्टी से अनबन के बाद भाजपा और राज ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं।

भाजपा से हाथ मिलाएंगे नायडू?

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के कभी संयोजक रहे चंद्रबाबू नायडू एनडीए में वापसी के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जाने का इरादा उन्होंने छोड़ दिया या यह कह सकते हैं कि भाजपा विरोधी गठबंधन से उनका मोहभंग हो गया है। उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं से नायडू की यह पहली मुलाकात नहीं थी, बल्कि पिछले कई महीनों से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और गठबंधन पर बात हो रही है। असल में आंध्र प्रदेश की स्थिति भाजपा के लिए बहुत अलग है। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बहुत सद्भाव रखते हैं। वे हर मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं।

प्रतिनियुक्ति की तैयारी तो नहीं

प्रदेश के प्रशासन की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे साहब इन दिनों अनायास ही राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। वैसे तो साहब हर दिन चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार अपने पुत्र को लेकर चर्चा में हैं। सूत्रों का कहना है कि विगत दिनों साहब ने अपने पुत्र की एक कद्दावर नेता से मुलाकात करवाई है। तबसे ही साहब चर्चा में आ गए हैं। साहब को करीब से जानने वालों का दावा है कि साहब ने यह मुलाकात पुत्र को दिल्ली दरबार में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए की है। दरअसल, साहब इस साल के अंत में रिटायर होने वाले हैं। साहब को इस बात का डर है कि उनके रिटायर होने के बाद उनसे खार खाए बैठे अधिकारी उनके पुत्र से बदला न लेने लगें। गौरतलब है कि साहब के अब तक के कार्यकाल में लगभग पूरा प्रशासनिक महकमा उनसे परेशान है। बताया जाता है कि साहब ने किसी को भी परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कोई अधिकारी जब भी बड़ी उम्मीद के साथ साहब के पास जाता है, वह उसे उलटे पांव लौटा देते हैं। ऐसे में साहब की आशंका जायज है। गौरतलब है कि साहब के पुत्र भी आईएएस अधिकारी हैं और इस समय प्रदेश के एक आदिवासी बहुल जिले की कलेक्टरी कर रहे हैं। साहब ने उक्त मंत्री से किस संदर्भ में मुलाकात की, यह तो साहब ही जानें, लेकिन उस मुलाकात के बाद एक ही बात की जा रही है कि साहब ने बेटे को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की फील्डिंग जमा ली है।

साहब का रसूख कायम

अभी हाल ही में घपले-घोटालों के कारण चर्चा में रहे पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन में व्याप्त भर्राशाही और लालफीताशाही की परतें खुल रही हैं। विभाग में पदस्थ अफसरों ने किस तरह विभाग को अपनी जागीर बनाकर रखा था, इसका ताजा मामला अभी हाल ही में सामने आया है। बताया जाता है कि विभाग में एक आईपीएस अधिकारी जबसे एमडी के पद पर पदस्थ हुए थे, तभी से उनकी गाड़ियां विभाग में टैक्सी के रूप में अटैच हैं। आलम यह है कि साहब अब भले ही विभाग में नहीं हैं, लेकिन टैक्सियां अभी भी कमाई कर रही हैं। गौरतलब है कि प्रदेश का पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन एक ऐसा संस्थान है, जहां करोड़ों-अरबों रुपए के काम होते हैं, लेकिन यह विभाग कभी भी सरकार की नजर पर नहीं चढ़ा है। लेकिन हाल ही में सामने आए बड़े भ्रष्टाचार ने अफसरों की सांठगांठ की पोल खोलकर रख दी है। सरकार विभाग को कमाई का साधन बनाने वाले अफसरों की कुंडली बना रही है। ऐसे में साहब को यह डर सता रहा है कि कहीं अगली बार उनका नंबर न आ जाए। अब देखना यह है कि साहब के घालमेल तक सरकार पहुंच पाती है या नहीं।

गबन नहीं, दबंगई के शिकार

करीब 6 साल पहले मालवा क्षेत्र के एक जिले में गोलीकांड से चर्चित हुए 2007 बैच के एक आईएएस अधिकारी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वे छुट्टी के दिन तबादले होने के कारण चर्चा में हैं। यहां बता दें कि साहब किसी गबन के कारण नहीं, बल्कि दबंगई के शिकार हो गए। दरअसल, साहब सरकार के मुखिया के चहेते संस्थान में पदस्थ थे। यह संस्थान सुशासन की स्थापना के लिए गठित किया गया है। बताया जाता है कि यहां पदस्थापना के बाद साहब खुद सुशासन को भूल गए और यहां के 2 कमरों में ताले डाल दिए थे। साहब ने ताले क्यों डाले थे, यह तो वे नहीं बता पाए लेकिन सूत्रों का कहना है कि संस्थान में साहब अपनी दादागिरी दिखाना चाहते थे, ताकि साहब का वर्चस्व कायम रहे। इसलिए साहब ने गेस्ट हाउस के 2 कमरों में ताला डाल दिया। बताया जाता है कि साहब का यह दुस्साहस संस्थान के वाइस चेयरमेन को नागवार गुजरा और उन्होंने साहब से सवाल दाग दिया कि तुम कौन होते हो ताला डालने वाले। लेकिन साहब अपनी पर अड़े रहे। बताया जाता है कि संघ के पावरफुल व्यक्ति से टकराना साहब को भारी पड़ा और वे उनकी दबंगई के शिकार हो गए। फिर क्या था, साहब से सारे काम छीनकर मंत्रालय में बिना काम के सचिव पदस्थ कर दिया गया है। अब साहब केवल सुबह से शाम तक कुर्सी तोड़ रहे हैं।

विकास की कील गड़ जाए

कुबेर के खजाने पर बैठे एक मंत्रीजी इन दिनों बौराए फिर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले 4 सालों तक मंत्रीजी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कोई काम नहीं करवाए हैं। अब उनकी कोशिश यह है कि इस चुनावी साल में कम से कम विकास की कील तो गड़ जाए। सूत्रों का कहना है कि पाला बदलने के बाद जबसे मंत्रीजी ने प्रदेश के सबसे मालदार विभाग की कमान संभाली है, तबसे उनका ध्यान केवल अपना खजाना भरने पर ही रहा है। मंत्रीजी खजाना भरने में इस कदर मशगूल हो गए कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र की सुध तक नहीं आई। अब जब चुनावी बिगुल बजने वाला है तो मंत्रीजी को याद आया कि क्षेत्र में कुछ तो ऐसा काम हो जिसे वे जनता के बीच जाकर गिना सकें। इस कड़ी में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल खुलवाने की कवायद शुरू कर दी है। बताया जाता है कि अभी तक नियमों को ताक पर रखकर काम करने वाले मंत्रीजी दूसरे विभागों के अफसरों से काम करवाने के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे मंत्रीजी के खिलाफ अफसरों में नाराजगी है।

जैसा कहेंगे वैसा करना

प्रदेश में चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सत्तारूढ़ संगठन अभी से भविष्य की तैयारियां करने लगा है। यह तैयारी सांगठनिक न होकर प्रशासनिक स्तर पर है। दरअसल, संगठन को उम्मीद है कि अगली बार भी उसी की सरकार बनेगी, इसलिए उसने जिलों में पदस्थ होने वाले भावी अफसरों को मंत्र देना शुरू कर दिया है। इस मंत्र के तहत उन्हें घूंटी पिलाई जा रही है कि हम जैसा कहेंगे, आप लोग वैसा ही करना। सूत्रों का कहना है कि संगठन ने 2015 बैच के आईपीएस अधिकारियों को यह मंत्र देना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि गत दिनों संगठन ने 2015 बैच के एक आईपीएस अधिकारी को मंत्र दिया कि तुम्हें एक जिले में एसपी बनाकर भेज रहे हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि वहां जाकर वही करना है, जो हम कहेंगे। बताया जाता है कि संगठन के इस प्रस्ताव को उक्त आईपीएस अधिकारी ने सिरे से नकार दिया। उक्त अफसर ने साफ-साफ शब्दों में कर दिया कि मैं अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा, किसी और के कहने पर नहीं।

कोई भी काम करना हो तो अक्सर लोग पहले मुहूर्त देखते हैं। शुभ समय में किया गया काम शुभ परिणाम देता है, ऐसी मान्यता हमारे ग्रंथों में है। सिर्फ पंचांग देखकर ही मुहूर्त नहीं निकाले जाते, कुछ संकेत भी होते हैं, जिन्हें देखकर यह तय किया जाता है कि कौनसा समय अच्छा है।

● **स्वामी अवधेशानंद गिरी**

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देशद्रोही ताकतों को ताकत दी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को प्रमाण पत्र देकर जातिगत आरक्षण का लाभ देने का प्रयास किया है। यह देश के लिए ठीक नहीं है। उधर, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब में ओबीसी भाईयों के संवैधानिक अधिकारों का खुलकर हनन हो रहा है।

● **जेपी नड्डा**

बीसीसीआई नहीं चाहता था कि विराट कोहली टेस्ट की कप्तानी छोड़ें। उनसे टेस्ट की कप्तानी न छोड़ने के लिए अनुरोध भी किया गया था। कप्तानी छोड़ने का फैसला विराट का था। हमने जब यह खबर सुनी तो हम भी हैरान थे। उस वक्त टीम में रोहित शर्मा ही कप्तानी का बेहतर विकल्प थे। डब्ल्यूटीसी फाइनल की हार में टीम की अप्रोच डिफेंसिव थी।

● **सौरभ गांगुली**

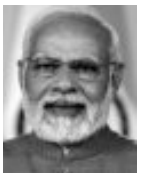

एक समय ऐसा था जब देश में नौकरी के लिए घूस लिया जाता था, अब युवाओं को आसानी से नौकरी मिल रही है। आने वाले समय में देश में नौकरियों की भरमार रहेगी। युवाओं का भविष्य संवारने का काम सरकार कर रही है।

● **नरेंद्र मोदी**

बॉलीवुड में मैंने 9 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी शुरुआत ही है। मेरे सबसे प्रिय वेल विशर्स मुझे सपोर्ट करने और इन 9 सालों के दौरान मुझे इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। यह जर्नी आप सभी के बिना ऐसी नहीं होगी। मैं आप सभी की आभारी हूं कि मुझे आपके परिवार और जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका मिला। मेरे सभी उतार-चढ़ाव में साथ देने और मुझे एक्ट्रेस बनाने के लिए शुक्रिया। जो भी मैं आज हूं, आप सभी के साथ की वजह से हूं। मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मेरी आंखों में बहुत से सपने थे। मैं आप लोगों के साथ और आगे चलने के लिए अभी भी तैयार हूं।

● **कियारा आडवाणी**

वाक्युद्ध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार डरी हुई है। डरी हुई सरकार कई गलत कदम भी उठा रही है, जिससे यह साफ हो गया है कि भाजपा का बोरिया-बिस्तर बांधने का समय आ गया है। यही कारण है कि विपक्ष की एकता को देखकर सभी घबराए हुए हैं। अहंकार में पीएम ने कई गलत कदम उठाए हैं।

● **राहुल गांधी**

राहुल गांधी को पहले यह सीखने की जरूरत है कि कब, कहां और क्या बोलना चाहिए। अमेरिका में भारत के खिलाफ बोलकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि भले ही वे 50 के हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी बुद्धि अपरिपक्व है। पीएम पर उंगली उठाने से पहले उन्हें अपने गिरेबां में झांक लेना चाहिए।

● **स्मृति ईरानी**

पुरुषोत्तम शर्मा को नहीं मिलेगा वीआरएस!

मप्र कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अफसर व स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने राज्य सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है। शर्मा ने वीआरएस का आवेदन जरूर दिया है, लेकिन उस पर पेंच फंस सकता है। ऐसा इसलिए कि शर्मा की जांच चल रही है और जांच जारी रहने के दौरान वीआरएस मंजूर नहीं होता है। दरअसल, डीओपीटी का नियम है कि अगर किसी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है तो उसे वीआरएस नहीं दिया जा सकता। हालांकि इस संदर्भ में शर्मा का कहना है कि हमने आवेदन के साथ वह सर्कुलर (आदेश) भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है, तो वीआरएस मंजूर नहीं होगा। मेरी जांच भ्रष्टाचार से जुड़ी नहीं है। इसलिए वीआरएस मंजूर होने में दिक्कत नहीं होगी। हमने सरकार से कहा है कि जो भी सजा देना है दें, लेकिन वीआरएस मंजूर कर लें। पूरी पेंशन नहीं देना है, तो अंतरिम पेंशन दें।

दरअसल, शर्मा ने वीआरएस का फैसला सरकार से नाराज होकर किया है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार मुख्य सचिव से मिलने का समय मांगा, लेकिन मुझे समय तक नहीं दिया गया है। शर्मा ने कहा, भीख मांग लूंगा, पेट भर लूंगा, लेकिन बिना काम का वेतन नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, वीआरएस मिलने के बाद ऋषिकेश जाकर

भजन करूंगा। शर्मा प्रदेश के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर हैं। उन्हें 2025 में सेवानिवृत्त होना है। साल 2021 में शर्मा के खिलाफ पत्नी ने मारपीट और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था। इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एफआईआर होने के बाद सरकार ने शर्मा को निलंबित कर दिया था। उसके बाद सरकार की ओर से उनके निलंबन की अवधि को लगातार बढ़ाया जा रहा था, लेकिन बहाल नहीं किया गया।

इस मामले को लेकर शर्मा ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत के आदेश पर उन्हें बहाल तो कर दिया गया, लेकिन कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया। उसके बाद से शर्मा लगातार मुख्य सचिव से मिलने का समय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने कई बार मुख्य सचिव से मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन उनके पास डीजी रैंक के अफसर से मिलने तक का वक्त नहीं है। मुझे बिना काम किए वेतन लेना अच्छा नहीं लग रहा है। काम करो, तो वेतन लो, बिना काम किए वेतन लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वीआरएस मांगा है। शर्मा ने वीआरएस का आवेदन गृह विभाग में दे दिया है।

● **कुमार राजेंद्र**

नहीं बन पाए एएसपी

मप्र में पद रिक्त होने पर भी प्रदेश में उप पुलिस अधीक्षकों (डीएसपी) की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के पद पर पदोन्नति नहीं हो पा रही है। इसकी वजह यह कि डीपीसी वर्ष में एक बार करने का नियम है। उधर, कई अधिकारी तो पदोन्नति की प्रतीक्षा में सेवानिवृत हो चुके हैं। एएसपी स्तर के अभी 40 पद रिक्त हैं। 4 मई 2022 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में 2012 बैच के 17 उप पुलिस अधीक्षकों को पदोन्नत किया गया था। वहीं अब 2013 बैच के उप पुलिस अधीक्षक भी पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। पदोन्नति का इंतजार करने वाले 5 से 10 डीएसपी प्रतिवर्ष सेवानिवृत हो रहे हैं। इनमें सीधी भर्ती के अलावा निरीक्षक से पदोन्नत हुए डीएसपी भी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि 2022 में जिन पुलिस अधीक्षकों को पदोन्नत किया गया था, उनमें 11 सीधी भर्ती और 6 पदोन्नति वाले थे। अभी भी 40 पद रिक्त हैं। उधर, पदोन्नति की आस लगाए बैठे गोविंद बिहारी रावत और अवधेश द्विवेदी बिना एएसपी बने रिटायर हो गए। ऐसे कई और अधिकारी कतार में हैं।

आईपीएस की डीपीसी उलझी

मप्र में 2 साल से आईपीएस बनने का इंतजार कर रहे राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आईपीएस अवार्ड के लिए अभी इंतजार करना होगा। राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस अवार्ड का मामला उलझा हुआ है। डीपीसी 2 मई को हुई थी लेकिन अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय से क्लीयरेंस नहीं मिला है। वर्ष 2021 और 2022 के लिए पहले यह बैठक जनवरी-फरवरी में भोपाल में होनी थी, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का समय नहीं मिलने और अन्य कारणों से डीपीसी टलती चली गई। डीपीसी अभी और लटक सकती है, क्योंकि अरुण मिश्रा का लिफाफा बंद है और उन्होंने इस संदर्भ में याचिका लगाई है। जानकारों का कहना है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक यह मामला लटका रह सकता है। अब देखना यह है कि राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में जाने की आस लगाए बैठे अधिकारियों की लॉटरी कब लगती है।

4 डीआईजी के पद खाली

प्रदेश में चुनावी साल होने के कारण एक ही जगह पर 3 साल या उससे अधिक समय से पदस्थ रहे अधिकारियों का तबादला करना है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जल्द ही बड़ी संख्या में आईपीएस अफसरों की पदस्थापना करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार व शासन में बीते कई दिनों से मंथन का दौर जारी है। माना जा रहा है कि यह सूची कभी भी जारी की जा सकती है। इसमें पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों में पदस्थ आईपीएस अफसरों तक के नाम शामिल हैं। दरअसल नई पदस्थापना के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा जो सूची तैयार की गई है, उसमें अफसरों के नाम बताए जा रहे हैं। इनमें पुलिस मुख्यालय की कई शाखाओं के प्रभारियों के भी नाम शामिल हैं। उधर, पूर्व में सरकार ने कई जिलों में मैदानी अफसरों की जिम्मेदारी में फेरबदल किया था। जिसमें से 4 जिलों में डीआईजी के पद अभी भी खाली पड़े हैं। इनमें शहडोल, खरगौन, चंबल और रतलाम शामिल हैं। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इन खाली पड़े डीआईजी के पदों पर अफसरों की तैनाती करती है।

मप्र में मिशन सत्ता के लिए भाजपा और कांग्रेस में खंदक की लड़ाई शुरु हो गई है। दोनों पार्टियों का एक ही टारगेट है, सरकार बनाना। इसके लिए योजनाओं और घोषणाओं का दौर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों ने महिलाओं पर फोकस किया है, उससे यह साफ हो गया है कि मप्र के सत्ता संग्राम में अबकी बार आधी आबादी का बड़ा खेल रहेगा। यानी महिला वोटरों ने जिधर का रुख कर लिया, उधर वाली पार्टी की सरकार बननी तय है।

महिलाओं के हाथ जीत की पतवार

मप्र के विधानसभा चुनावों में लगभग 5 महीनों का समय ही बचा है। ये समय आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसने राजनेताओं की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। आंख खुलने से लेकर बिस्तर पर गिरने और फिर शायद सपनों में भी नेताओं को चुनावी तारीख करीब, और करीब आते दिखाई दे रही होगी। राजनीतिक दल और उनके दिग्गज भी रणनीतियों को धरातल पर उतारने और तुरुपों को फेंकने में लगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा को कल्याणकारी योजनाओं और लाड़ली बहना योजना पर भरोसा है, तो कांग्रेस को एंटी-इनकम्बेंसी, अपनी गारंटियों के साथ ही नारी सम्मान योजना से उम्मीद है। यानी दोनों पार्टियों ने महिलाओं पर आधारित अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की 2,60,23,733 महिला मतदाताओं को साधने का भरपूर जतन किया है।

गौरतलब है कि राज्य की विधानसभा सीटों में से 18 निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। गौरतलब है कि भाजपा ने गुजरात में और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में महिलाओं को अपने पाले में लाकर सरकार बनाने में कामयाबी पाई है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने मप्र में भी अपनी रणनीति लगभग तैयार कर ली है और उसे लेकर धरातल पर काम भी शुरू हो गया है। भाजपा गुजरात वाली रणनीति पर मप्र में भी चांस लेने के मूड में है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि इस समय मप्र में सत्ता विरोधी लहर की सुगबुगाहट सुनने में आ रही है। इसके लिए पार्टी को दो मोर्चों पर काम करना है। पहला अंदरूनी कलह को दूर करना और दूसरा बड़े वोट बैंक के बीच जुड़ाव बढ़ाने का काम। इसके लिए सिर्फ भाजपा ही नहीं कांग्रेस ने भी रोडमैप तैयार कर लिया है।

मप्र में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में लगी हुई है। महिला वोटर्स को साधने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 5 मार्च को लाड़ली बहना योजना लांच करना हो या फिर महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारियों को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का ऐलान। ये घोषणाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा का फोकस महिला वोटर्स पर सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से महिला संबंधी मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं और एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं।

एससी-एसटी और महिला वोटबैंक है जरूरी

मप्र में जीत की राह आदिवासी और एससी-एसटी वोटबैंक के द्वार से होकर ही गुजरती है। इसके अलावा इस समय राजनीति का केंद्र प्रदेश की महिला वोटबैंक पर भी है। इस समय के ताजा आंकड़े तो यही बताते हैं कि देश की 50 प्रतिशत आबादी यानी महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत में भी भागीदारी बढ़ी है। ऐसे में इन्हें लुभाने के लिए दोनों राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं। मप्र में वोटरों की संख्या के आंकड़े देखें तो इस समय 5 करोड़ 39 लाख 85 हजार 876 हो गए हैं। रिपोर्ट की मानें तो वोटर लिस्ट अपडेशन में 13 लाख 39 हजार नए मतदाता के नाम जुड़े हैं। खास बात ये है कि इसमें पुरुष के मुकाबले महिला वोटर ज्यादा है। करीब 75 हजार से ज्यादा नाम जुड़े हैं। मप्र के 41 जिलों में महिलाओं का आंकड़ा ज्यादा है। प्रदेश के 52 में से 41 जिलो में महिला वोटरों के नाम ज्यादा जुड़े हैं। यानी महिला वोटरों का आंकड़ा 7.07 लाख बढ़ा है। मप्र के पुराने इलेक्शन में साल 2005 के बाद से लगातार महिला वोटरों का प्रतिशत बढ़ा है। साल 2014-15 के चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं की बराबरी में वोटिंग की थी। ये ऐसे पता चलता है कि साल 2004 में पुरुष मतदाताओं का वोट प्रतिशत 78.84 प्रतिशत और महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत 74.58 प्रतिशत था। ये बाद में बढ़कर 2009 में पुरुष का 81.7 प्रतिशत और महिला का प्रतिशत 79.21 प्रतिशत रहा। वहीं 2014-15 में पुरुष मतदाताओं का वोट प्रतिशत 83.59 प्रतिशत था और महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत 83.17 प्रतिशत था। इसलिए इस बार दोनों पार्टियों का इन पर फोकस है और शिवराज सरकार कई योजनाएं भी चला रही है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मिशन 2023 के लिए महिला वोटर्स को साधने का प्लान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म और बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा देने का प्रावधान पहले ही कर चुके हैं। अब वे महिला सुरक्षा, महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। राज्य में आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वसहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर फोकस किया जा रहा है।

आधी आबादी... ये वो वर्ग है, जिसका हर चुनाव में रोल अहम होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मामा और भैया वाली छवि गढ़ने में इस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी विधानसभा चुनाव से पहले लाड़ली बहना योजना लाकर मास्टरस्ट्रोक चल दिया है और ये बात अब कांग्रेस भी समझ रही है। इस कड़ी में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च कर दी है, ताकि आधी आबादी को साधा जा सके। कांग्रेस का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनने जा रही है और वो मप्र की महिलाओं को 1500 रुपए महीने देगी। लाड़ली बहना योजना भाजपा का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। यही वजह है कि, कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी हुई है, वो भी हर हाल में इस वर्ग को साधना चाह रही है। हालांकि, भाजपा का दावा है कि कांग्रेस की योजना वर्चुअल है और ये भाजपा की एकजुटता से मुकाबला नहीं कर पाएगी।

पार्टियों के रूख को देखकर यह साफ है कि इस बार महिला वोटर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने जा रही है। यही कारण है कि भाजपा सरकार लाड़ली बहना योजना के जरिए उनके खाते में हर महीने एक हजार रुपए डालने जा रही है। इसकी काट के लिए कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना बनाई है। इस योजना में 1500 रुपए महीने महिलाओं के खाते में डालने का वादा किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं पर फोकस करने के लिए मिशन खुशहाली की कार्ययोजना तैयार की है। मिशन खुशहाली में नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के साथ ही उनको स्वरोजगार से जोड़ने और उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं एक छाते के नीचे लाई जा रही हैं। कांग्रेस में महिला सुरक्षा, उनकी पढ़ाई से लेकर स्कूटी देने तक की योजनाएं तैयार की गई हैं। कांग्रेस ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार वचन पत्र घोषित किया था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र जारी करने के पीछे महिला मतदाताओं के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने की मंशा है। दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बढ़ी है। 18 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है।

कांग्रेस ने भी खेला बड़ा दांव

उधर चुनावी बेला में कांग्रेस ने भी महिला मतदाताओं को साधने के लिए नारी सम्मान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कांग्रेस पदाधिकारी महिलाओं से फार्म भरवा रहे हैं। दरअसल, भाजपा को धराशायी करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। किसानों की कर्ज माफी के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, प्रदेश में बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से देने जैसी घोषणाओं के साथ पार्टी लोगों के बीच पहुंच रही है। बिजली की 100 यूनिट मुफ्त देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस की ओर से भी लाड़ली बहना योजना काट करने के उद्देश्य से नारी सम्मान योजना शुरु करने की घोषणा करते हुए महिलाओं से इसके फॉर्म भरवाना भी शुरु कर दिए हैं। अब इसी के साथ कांग्रेस महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी वचन पत्र भी घोषित करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं कि शपथ कमलनाथ जी ही लेंगे। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं, पर शिवराज सिंह कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के बाद अब मप्र में लाड़ली बहना योजना गेमचेंजर बनने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना के जरिए सवा करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे एक हजार रुपए डालकर बड़े वोट बैंक को साध लिया है। गौरतलब है कि भाजपा शिवराज के चेहरे के साथ अबकी बार 200 पार के नारे के साथ कांग्रेस को पटकनी देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। समाज के सभी वर्गों को साधने के अलावा शिवराज और भाजपा महिला वोटरों से सीधे संपर्क स्थापित करने में जुटी है। उनकी सरकार ने 2023-24 के बजट में महिला वर्ग के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शिवराज सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत 23 से 60 वर्ष तक की आयु की महिलाओं के खाते में प्रतिमाह सीधे एक हजार रुपए डालने जा रही है। स्कूली छात्राओं को साधने के लिए प्रथम श्रेणी में 12वीं पास होने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी देने का प्रावधान बजट में किया गया है। प्रदेश की महिला कर्मचारियों को इस वर्ष से सात अतिरिक्त कैजुअल अवकाश देने का ऐलान भी किया गया है। पिछले तीन चुनावों में प्रदेश में महिलाओं के मत प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया है। आकड़ों के लिहाज से प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं, जो आबादी के हिसाब से करीब 48 फीसदी हैं। वहीं जनवरी 2023 में जारी की गई पुनरीक्षित मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या 7.7 लाख और पुरुषों की 6.32 लाख बढ़कर सामने आई है। प्रदेश के 52 में से 41 जिले ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या में पुरुषों की तुलना में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य की 18 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है।

कर्नाटक में भाजपा को मिली करारी हार के बावजूद शिवराज के चेहरे और भाजपा के महिला दांव ने उनके कैबिनेट के सदस्यों में उत्साह भरने का काम किया है। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं, शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास की तर्ज पर काम करके जन-जन को लाभान्वित कर रही है।

● **कुमार विनोद**

सियासी मैदान में नए खिलाड़ी

विधानसभा चुनाव में अब महज पांच माह का समय बचा है, ऐसे में अब भाजपा व कांग्रेस के सामने नई-नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती वे क्षेत्रीय दल बन रहे हैं, जिनका अब तक प्रदेश में कोई वजूद ही नहीं था। इनमें आप, बीआरएस और एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक दल शामिल हैं। इसके अलावा इस बार बसपा और सपा की नजर भी मप्र पर लगी हुई है। इसकी वजह है यह दोनों दल उप्र में सत्ता से दूर हैं। इन सभी दलों द्वारा अपने संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करने पर इन दिनों जोर दिया जा रहा है। इन दलों के चुनावी मैदान में उतरने से जहां दोनों प्रमुख दल भाजपा व कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन इसमें सर्वाधिक नुकसान कांग्रेस को होना तय है। इसकी वजह है अब तक कांग्रेस को मिलने वाला एकमुश्त मुस्लिम समाज के मतों में विभाजन होना।

फिलहाल अब तक आम आदमी पार्टी (आप), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) द्वारा मप्र में चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा चुका है, जबकि बसपा व सपा तो पहले से ही चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। यह दोनों दल तो कई चुनाव से प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाते आ रहे हैं। इसके बाद भी वे अपनी नीतियों व पार्टी की रीति की वजह से प्रदेश में तीसरी ताकत कभी नहीं बन सके हैं। इसी खाली जगह पर अब अन्य क्षेत्रीय दलों की नजर है। इसमें आप और एआईएमआईएम से भाजपा व कांग्रेस को अधिक खतरा है। इसकी वजह है इन दोनों दलों को पहली बार में ही नगरीय निकाय चुनाव में अच्छी सफलता मिलना। आप का तो सिंगरौली में अपना महापौर तक जनता चुन चुकी और कई निकायों में उसके पार्षद भी निर्वाचित हो चुके हैं। सिंगरौली महापौर पद पर अपना कब्जा जमाने के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश के 17 पार्षद पदों पर भी जीत हासिल की जा चुकी है। इसमें पांच प्रत्याशी सिंगरौली नगर निगम से चुनाव जीते हैं। वहीं, एआईएमआईएम भी अपनी जोरदार दस्तक देते हुए जबलपुर, खंडवा और बुरहानपुर में 4 पार्षद पदों पर जीत दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा खंडवा और बुरहानपुर में एआईएमआईएम के महापौर उम्मीदवारों को दस हजार से अधिक वोट मिलना भी अलग सियासी संकेत देता है। यह बात अलग है कि जो नए दल प्रदेश में चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वे अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर कम ही असर पड़ेगा। कांग्रेस के चुनावी समीकरण जरूर बिगड़ सकते हैं।

मप्र की राजनीति में अभी तक दो प्रमुख दल कांग्रेस एवं भाजपा ही हैं। दोनों दलों के बीच ही सीधा मुकाबला होगा, लेकिन जिस तरह से नए दल मप्र में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, उस पर भरोसा कर लिया जाए तो करीब आधा दर्जन राजनीतिक दल पहली बार चुनाव में उतरेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन तब कोई सफलता नहीं मिली थी। अगर प्रदेश में मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार, मप्र में मुसलमानों की आबादी 6.6 प्रतिशत है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों से लेकर राऊ-महू जैसे कस्बाई नगर की कतिपय सीटों पर अल्पसंख्यकों की संख्या निर्णायक हो गई है। करीब दो दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां 30 से 40 हजार वोटर्स हैं। भोपाल मध्य पर 1.11 लाख, बुरहानपुर में 96 हजार, जबलपुर पूर्व 77 हजार, भोपाल उत्तर 87 हजार, नरेला 68 हजार, इंदौर-5 में 69 हजार और रतलाम में 51 हजार मुस्लिम वोटर्स हैं।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश में आप द्वारा हर माह संगठनात्मक बैठकें की जा रही हैं। इसके लिए लगातार दिल्ली से नेता भी प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 महीने पहले ही मप्र की सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि आप की प्रदेश इकाई का कहना है कि पार्टी फिलहाल शहरी क्षेत्र की सभी सीटों पर संगठन का ढांचा तैयार कर रही है। साथ ही शहरी क्षेत्र में ही प्रत्याशी खड़ा करने पर जोर है। इसकी वजह है प्रदेश में एक महापौर की सीट पर चुनाव जीतना। इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए करीब 3 दर्जन ऐसी सीटें चिंता की वजह बनी हुई हैं, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक संख्या में पहुंच चुके हैं। अभी इनमें से भाजपा व कांग्रेस के पास बराबर सीटें हैं। पिछली बार इन 33 सीटों में से 18 पर भाजपा और 15 में कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार निकाय चुनाव में सियासी समीकरण बदलने से दोनों ही दल आशंकित हो उठे हैं। इसकी वजह है महापौर चुनाव के दौरान बुरहानपुर और उज्जैन में ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए थे। वहीं सिंगरौली में आप प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली थी।

● **जितेंद्र तिवारी**

कांग्रेस को नुकसान ज्यादा

खास बात यह है कि जितने नए दल चुनाव में उतरेंगे, उतना ही नुकसान कांग्रेस को होना तय माना जा रहा है। भाजपा को नुकसान कम होने की संभावना की बड़ी वजह है, प्रदेश में उसका वोट बैंक स्थाई होना। मप्र में 2003 में सत्ता में आई भाजपा ने लगातार अपना वोट बैंक मजबूत किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन तब भी भाजपा को मिले मत कांग्रेस से अधिक थे। इससे यह साफ है कि नए दलों के आने से कांग्रेस को ही नुकसान होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम सीधे तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाएगी। यह भी संभावना है कि भाजपा से असंतुष्ट वोट कांग्रेस को न जाकर इन दलों को चला जाए। इसका फायदा भी भाजपा को ही मिले। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी हिंदी भाषी राज्य मप्र की राजनीति में आने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ही उनके द्वारा मप्र के कई नेता एक साथ बीआरएस में शामिल किए गए हैं। प्रदेश के जो नेता पार्टी में शामिल किए गए हैं, उनमें रीवा के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल (भाजपा), पूर्व विधायक डॉ. नरेश सिंह गुर्जर (बसपा), सतना (सपा) के धीरेंद्र सिंह, सतना जिला पंचायत के सदस्य विमला बारी और अन्य शामिल हैं।

मप्र में कांग्रेस का ओपीएस फॉर्मूला

हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह कांग्रेस मप्र में भी पुरानी पेंशन के फॉर्मूले को भुनाएगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में इसकी घोषणा कर दी है और इसे मप्र के लिए 5 गारंटी की सूची में शामिल भी कर लिया है। पुरानी पेंशन बहाली के इस फॉर्मूले को कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में परख चुकी है। इन दोनों राज्यों में मिली सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब मप्र के विधानसभा चुनाव के लिए ओपीएस के फॉर्मूले को अपने एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन पर भाजपा की कमजोर कड़ी पकड़ ली है।

हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रियंका गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे सरकारी कर्मियों की एक बड़ी भूमिका रही है। गत दिनों प्रियंका गांधी ने मप्र में जिन पांच गारंटी की बात कही है, उनमें सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली भी शामिल है। इस साल मप्र के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पहले ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है। केंद्र में स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव और नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे की गहराई भाजपा समझ नहीं पा रही है। भाजपा अब भी एनपीएस में सुधार की बात कहती है, जबकि कर्मचारी संगठन कह चुके हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन बहाली से परे कुछ भी मंजूर नहीं है। एनपीएस को समाप्त करना ही पड़ेगा। अब ओपीएस का मुद्दा हर राज्य में पहुंच चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे का असर देखने को मिलेगा। देश में सरकारी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवारों को मिलाकर देखें, तो वह आंकड़ा 10 करोड़ से पार चला जाता है। कर्मचारियों ने पहले भी कहा है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, वही देश पर राज करेगा।

केंद्र सरकार, ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे आने वाली पीढ़ियों पर बोझ बता चुके हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन को लेकर कहा था कि ऐसा पाप न करें, जो आपके बच्चों का अधिकार छीन ले। प्रधानमंत्री ने आर्थिक संकट में फंसे एक पड़ोसी मुल्क का उदाहरण भी दिया। देश में कुछ राज्य आज उसी राह पर चल रहे हैं। वे तत्कालीन भुगतान के चक्कर में देश को बर्बाद कर देंगे। अपने फैसलों के द्वारा वे आने वाली पीढ़ियों पर भारी बोझ डाल रहे हैं। इसके बाद कर्मचारी संगठनों और विपक्ष के दबाव में केंद्र सरकार ने इस मामले में जो कमेटी गठित की है, उसके एजेंडे में कहीं भी ओपीएस का जिक्र नहीं है। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की कमेटी बनाई है।

गौरतलब है कि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने अब मप्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गत दिनों जबलपुर में कांग्रेस के चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। सभा में प्रियंका ने मप्र में सरकार बदलने पर कहा- पिछली बार आपने हमारी सरकार बनाई थी, लेकिन जोड़-तोड़ और पैसे से भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी बना ली। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा- अफसोस कि ऐसे कुछ नेता हमारे भी ऐसे थे, जो पार्टी छोड़कर चले गए। उनको पैसा मिला। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूं। आपके पास 6 महीने हैं। इन 6 महीनों में देखिए, कांग्रेस की सरकारें अपने प्रदेश में क्या कर रही हैं? अपना वोट अपने लिए डालिए। प्रियंका ने कहा- आज मैं कुछ गारंटी दे रही हूं। वे गारंटी, जो हम 100 प्रतिशत पूरा करेंगे। यह मेरा वादा है। ये गारंटी है, घोषणा नहीं। यही वादा हमने कर्नाटक में किया। वहां की सरकार ने पहली कैबिनेट में ही इसका बिल पास कर दिया। उन्होंने कहा- हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 1000 का नहीं, 500 रुपए का मिलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री। 200 यूनिट हॉफ होगी। मप्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कमलनाथ की सरकार ने किसान कर्जमाफी की थी। बचे हुए किसानों की कर्जमाफी का काम पूरा करेंगे। प्रियंका ने कहा कि चुनाव के समय बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन बाद में भुला दिए जाते हैं। हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, सेवा सर्वोपरि होती थी लेकिन पिछले 18 सालों से आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। कई घोषणाएं की जाती हैं लेकिन पूरी नहीं की जाती हैं।

● **अरविंद नारद**

एनपीएस में सुधार कर सकती है सरकार

केंद्र सरकार ने कह दिया है, यह कमेटी देखेगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना के आलोक में कोई परिवर्तन आवश्यक है। यदि ऐसा है, तो राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के लिए उपयुक्त उपायों के लिए सुझाव देना है। इसमें आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा। कमेटी को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई, उसमें कहीं भी ओपीएस नहीं लिखा है।

अवैध कॉलोनियां होने लगीं वैध

मप्र में 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा सरकार ने कर दी है। इससे प्रदेश की 2500 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को फायदा होगा। नई व्यवस्था के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को 20 प्रतिशत विकास शुल्क भी नहीं देना होगा। हालांकि, सरकार के पास 2016 के बाद बनी अवैध कॉलोनियों का डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। अभी 31 दिसंबर 2016 तक की 6077 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जा रही है। 31 दिसंबर 2022 तक की अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने के निर्णय से अतिरिक्त रूप से 2500 कॉलोनियों के रहवासी लाभांवित हो सकेंगे। इन कॉलोनियों में बने ऐसे मकान जो कंपाउंडिंग की सीमा में आ रहे हैं, उनके नक्शे पास किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अधिकतम 6 माह में सभी कॉलोनियां नियमित होंगी।

सरकार की घोषणा के अनुसार आर्थिक कमजोर परिवारों के 323 से 430 वर्गफीट प्लाट पर बने मकानों और निम्न आय वर्ग वालों के 441 से 1033 वर्गफीट पर बने मकानों के लिए अब कोई विकास शुल्क नहीं लगेगा। यह राशि सरकारी योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को अनुदान के रूप में शासन द्वारा दी जाएगी। कॉलोनियों के **नियमितीकरण होने** से कई फायदे मिलेंगे। वैध हुई कॉलोनियों के रहवासी बैंक लोन ले सकेंगे। बिल्डिंग परमिशन लेकर पानी, बिजली कनेक्शन और सड़क के लिए आवेदन दे सकेंगे। रहवासी संघ बनाकर सरकार को सुझाव दे सकेंगे कि कौन से विकास कार्य पहले हों। अवैध कॉलोनियों में भले ही बिजली सड़क और पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही हो मगर अवैध कॉलोनियों में भूखंड और भवन की कीमत काफी कम होती है। ऐसी जमीनों और उन पर बने मकानों का बैंक से लोन भी नहीं होता है। नियमितीकरण का प्रमाण पत्र मिलने के बाद भूखंड और भवन के दाम में इजाफा होता है। इसके अलावा बैंक से आसानी से ऋण भी मिल जाता है। यही वजह है कि लोग अवैध कॉलोनी को वैध करने की हमेशा से मांग उठाते आए हैं। पहले दो तरह से विकास शुल्क वसूल किया जाता था। जिस भी कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस के लिए 75 फीसदी मकान हों तो वहां पर कुल विकास खर्च का 25 प्रतिशत वहां रहने वाले लोग देते थे और 75 प्रतिशत की राशि नगरीय निकाय चुकाती थी। दूसरे नियम में जहां पर ईडब्ल्यूएस की संख्या 75 फीसदी से कम हो तो वहां पर 50 प्रतिशत रहवासियों से राशि ली जाती थी और 50 प्रतिशत नगरीय निकाय खर्च करती थी। अभी नया नियम आया नहीं है।

मप्र के प्रत्येक जिले में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। प्रदेश के सभी 52 जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों की सूची बनाई गई थी। जिन कॉलोनियों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कॉलोनी की भूमि सरकारी नहीं है तो ऐसी जमीनों का पूरी तरह परीक्षण करने के बाद विकास शुल्क जमा करते ही कॉलोनियों को वैध करने के निर्देश जारी करने का फैसला हो चुका है। इस कड़ी में मप्र की 6 हजार कॉलोनियों से अधिक कॉलोनियों को फायदा मिलने जा रहा है।

अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की डेडलाइन 2022 करने से भोपाल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 320 से बढ़कर 850 हो जाएगी। 2016 की डेडलाइन के हिसाब से 320 अवैध कॉलोनियों को चुना गया था। प्रशासन के सर्वे में भोपाल में 576 कॉलोनियां चिन्हित की गईं थीं। अब इनकी संख्या 850 हो सकती है। भोपाल के 5 लाख लोगों को आने वाले दिनों में बिजली, पानी, सड़क, सीवेज आदि सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभी फिलहाल अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। इनमें से ऐसी कॉलोनियों में से 238 को वैध का दर्जा मिल गया हैं। यानी इन कॉलोनियों में जल्द ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिसके लिए आम नागरिकों को वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। आने वाले समय में लगभग 350 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इस तरह शहर में लगभग 588 से अधिक अवैध कॉलोनियों वैध हो जाएंगी। जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों 31 दिसंबर 2016 तक बनी अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया है।

● **प्रवीण सक्सेना**

1120 कॉलोनियों को बिल्डिंग परमिशन जारी

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में अवैध और अनाधिकृत निर्माण का जीआईएस सर्वे कराया है। जिससे विभाग को संपत्तिकर में वृद्धि हुई है। वहीं नगर पालिका निगम क्षेत्रांतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। मार्च 2023 की स्थिति में 31 दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को बिल्डिंग परमिशन देने का काम शुरू हो गया है। इनमें भोपाल की 238, इंदौर की 100, खंडवा की 40, बुरहानपुर की 5, उज्जैन की 33, देवास की 95, रतलाम की 51, जबलपुर की 21, कटनी की 76, छिंदवाड़ा की 100, ग्वालियर की 169, मुरैना की 3, रीवा की 40, सतना की 137, सिंगरौली की 9 और सागर की 3 कॉलोनियां शामिल हैं। अभी तक इन कॉलोनियों में रह रहे परिवार कई सुविधाओं से वंचित थे। जिनमें सड़क प्रमुख है। आर्किटेक्ट ने जो लेआउट तैयार किया है वह सभी कॉलोनियों के हिसाब से अलग-अलग है। इसमें तीन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। सबसे पहले सड़कों का प्लान किया गया है। इन कॉलोनियों में कितनी सड़कें होंगी और वह कैसे बनेंगी। उनकी लागत क्या होगी, इसे रखा गया है। ले-आउट में कॉलोनियों की नालियों के प्लान पर भी फोकस किया गया है। इसमें देखा गया है कि घरों के पानी की निकासी किस तरह होगी। कितनी नालियां रहेंगी और वहां की जनसंख्या के मान से यह कितनी चौड़ाई और गहराई में रहेंगी।

चीतों की मौत ने गिराए जमीन के भाव

मप्र के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाने के साथ ही आसपास के इलाकों में जमीन के दाम भी चीतों की रफ्तार की तरह बढ़ने लगे थे। कुछ ही महीनों में दाम पांच गुना तक बढ़ गए थे। अब एक के बाद एक 6 चीतों की मौत से इस प्रोजेक्ट को लेकर कई उलझनें पैदा हो गई हैं। इस बात की भी चर्चा है कि आने वाले वक्त में चीतों को कूनो से किसी और जगह सुरक्षित शिफ्ट कर दिया जाए। इन सबको देखते हुए यहां जमीन के दाम फिर नीचे आने लगे हैं। जिन लोगों के सौदे जुबानी या एडवांस थे, वो रद्द हो रहे हैं। जिन लोगों ने जमीन की कीमत का बड़ा हिस्सा दे दिया था, वो अब रजिस्ट्री कराने में आनाकानी कर रहे हैं। यहां पिछले वर्ष सितंबर के महीनों में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाने के पहले ही जमीनों के दाम आसमान छूने लगे थे। जिन जमीनों के भाव 1 लाख रुपए बीघा थे वो चीतों के आने से पहले ही 10 से 12 लाख रुपए बीघा तक पहुंच गए थे।

चीतों के आने के बाद तो ये 25 से 30 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। 25 किसानों ने अपनी जमीनों का सौदा किया, जिनमें से महज 7 से 8 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। चीता प्रोजेक्ट को झटका लगने के बाद 5 ने सौदे कैंसिल कर दिए, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। बार-बार कहने पर भी अब रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 65 किमी दूर है कूनो नेशनल पार्क। पार्क से ही लगा है मोरावन गांव।

गांव के अरुण गुर्जर का कहना है कि उनके गांव के वीरू गुर्जर ने ग्वालियर की एक पार्टी को 25 लाख रुपए में कूनो से 10 किलोमीटर दूर की जमीन बेची थी, पार्टी ने 2 से 5 लाख रुपए एडवांस भी दिया, लेकिन चीतों की मौत होने के बाद वह पार्टी जमीन की रजिस्ट्री कराने नहीं आ रही। सौदा कैंसिल हो रहा है। मेघसिंह गुर्जर ने विजयपुर के एक नेताजी को जमीन बेची। आधी रकम भी मिल गई, लेकिन खरीदार रजिस्ट्री नहीं करा रहे। वहीं कुंवर ऋषिराज सिंह जिन्होंने मोरावन के पास होटल का काम शुरू कराया है। उनके होटल का काम 60 फीसदी हो भी चुका है। बाकी के लोग या तो जमीनों को बेचना चाह रहे हैं या फिर सौदा कैंसिल करना चाहते हैं। कल तक बेतहाशा बढ़ रहे जमीन के दाम में जैसे रिवर्स गियर लग गया हो। चीतों की यहां से शिफ्टिंग होती है तो यहां कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत के अलावा टिकटोली गेट नहीं खुलना भी लोगों को खूब खल रहा है। क्योंकि, टिकटोली गेट नहीं खुलने से पास के सेसईपुरा और कराहल इलाके में इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक कोई भी पर्यटक घूमने नहीं आया है। रामचरण जाटव का कहना है कि पर्यटकों की आवाजाही शुरू नहीं होने से सेसईपुरा और कराहल से लेकर टिकटोली और मोरावन सहित आसपास के पूरे इलाके के जो लोग चीता प्रोजेक्ट के शुरू होने से रोजगार की आस लगाए बैठे थे, उन्हें भी अब तक निराशा ही हाथ लगी है। पहले यहां दिल्ली-मुंबई से लोग जमीन के भाव पूछने आ रहे थे। अब तो मप्र के लोग भी नहीं आ रहे।

कूनो के पास के गांव मोरावन में रिसोर्ट का काम करवा रहे कुंवर ऋषिराज सिंह का कहना है कि ये बात सही है कि चीतों की मौत होने के बाद इस इलाके में जमीनों के भाव एक दम से कम हो गए हैं। पहले रोज कोई न कोई गाड़ी लेकर यहां खरीदार दिखता था, लेकिन अब पिछले कई दिनों से कोई खरीदार नहीं आ रहा। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी, उनके भी सौदे कैंसिल हो रहे हैं। हमने अपने रिसोर्ट का काम चीता प्रोजेक्ट आने से पहले शुरू करा दिया था। इसकी प्लानिंग अलग है, क्योंकि हम इस क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित हैं। दरअसल, पालपुर रियासत कुंवर ऋषिराज सिंह के पूर्वजों की जागीर थी, इसलिए उनका निवेश व्यावसायिक से अधिक भावनात्मक है।

हथेड़ी ग्राम पंचायत के उपसरपंच मुकेश गुर्जर का कहना है कि जमीनों के दाम आसमान से जमीन पर आ गए हैं। फिलहाल हालत बहुत खराब है क्योंकि चीतों की मौत होने के बाद लोगों के सपनों पर पानी फिर गया है। यहां पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं पर आशंका पनपने लगी है। जमीनों का कोई खरीदार नहीं आ रहा और जिन्होंने एडवांस दे दिया, वह रजिस्ट्री नहीं करवा रहे। उम्मीद है कि चीतों की मौत का सिलसिला अब रुक जाएगा। ये चर्चा भी थम जाएगी कि चीतों को यहां से शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा हुआ तो एक बार फिर सब पटरी पर लौट सकता है। चीता प्रोजेक्ट को लेकर पर्यटन और रोजगार की जो संभावनाएं सोची गई हैं, वो धरातल पर दिखने लगेंगी।

● **लोकेंद्र शर्मा**

कूनो में अब 18 चीते ही बचे

पहली खेप में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बाड़े में रिलीज किया था। इसके बाद 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो लाए गए थे। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। पहले 3 चीतों और फिर एक-एक कर 3 चीता शावकों की मौत हो गई। अब कूनो में 18 चीते ही रह गए हैं। चीतों की सलामती के लिए इलाके में महामृत्युंजय मंत्र से लेकर सुंदरकांड का पाठ तक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चीतों की मौतों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने हाल ही में चीतों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र को राजनीति से ऊपर उठते हुए इन्हें राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने वन्यजीव विशेषज्ञ समिति को 15 जल्द से जल्द चीता टास्क फोर्स को सुझाव देने के निर्देश भी दिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि एक्सपर्ट रिपोर्ट से लगता है कि चीतों की बड़ी आबादी के लिए कूनो में पर्याप्त स्थान और संसाधन नहीं हैं, इसलिए केंद्र सरकार को दूसरे पार्क या सेंचुरी में चीतों की शिफ्टिंग पर विचार करना चाहिए।

मप्र ही नहीं बल्कि देशभर में इन दिनों महाकाल लोक छाया हुआ है। पहले महाकाल लोक अपनी भव्यता और आकर्षण के कारण चर्चा में रहा और अब आर्थिक अनियमितता के कारण। गौरतलब है कि महाकाल लोक के निर्माण में 1150 करोड़ से ऊपर खर्च होना है। पहले चरण में जो निर्माण कार्य हुआ है, वह शुरु से ही विवादों में है। इन विवादों को मजबूती 28 मई को उस समय मिली, जब थोड़ी सी तेज हवा में ही महाकाल लोक की 6 मूर्तियां उखड़कर जमीन पर गिर पड़ीं। अब इस मामले में लोकायुक्त की जांच शुरु हो गई है।

महाकाल लोक में आर्थिक अनियमितता या भूल...?

28 मई 2023 का दिन देश के लिए तो ऐतिहासिक बनाया गया लेकिन मप्र के मशहूर महाकाल मंदिर के लिए यह दिन खुद-ब-खुद ऐतिहासिक बन गया। दुनियाभर में मशहूर उज्जैन स्थित भगवान शिव के मंदिर परिसर में तूफान ने अचानक राज्य सरकार के सिस्टम का असली चेहरा सामने ला दिया। साथ ही यह भी साफ हो गया कि कथित रामभक्तों ने भगवान महाकाल को भी नहीं छोड़ा। महाकाल खुद भ्रष्टाचार के शिकार बन गए। भ्रष्टाचार भी उस परियोजना में हुआ है, जिसके पहले चरण का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह उद्घाटन मात्र साढ़े सात महीने पहले ही हुआ था।

28 मई 2023 को जब सारा देश नए संसद परिसर का उद्घाटन देख रहा था तब महाकाल के महालोक में मौजूद भक्तों ने एक अलग नजारा देखा। जिस महालोक को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे थे और दुनियाभर में शेखी बघार रहे थे, वह जरा सी आंधी में ताश के पत्तों सा बिखर गया। महालोक में सप्तऋषियों की जो मूर्तियां लगाई गई थीं, वे उखड़ गईं। कई मूर्तियां खंडित हो गईं। मूर्तियों के खंडित होने पर यह पता चला कि यह मूर्तियां फाइबर ग्लास की बनी हुई थीं। अगर आंधी उन्हें नहीं गिराती तो कुछ दिन में तेज गर्मी उनकी शक्लें बदल देती। यह बात उसी समय उठी थी, जब प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। बात भोपाल तक पहुंची तो लोकायुक्त ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस देकर जांच शुरू की। बाद में क्या हुआ यह पता नही चला। हां, जिन अफसरों को नोटिस दिए गए थे, उन्हें सरकार ने और अच्छे पदों पर बैठा दिया। अभी दूसरे चरण का काम चल रहा है। इसे जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस चरण पर 778 करोड़ से भी ज्यादा खर्च होने का अनुमान है।

आज आंधी ने जो किया उसको लेकर बातें तो सात महीने से हो रही थीं। जैसा कि राज्य में ट्रेंड चल रहा है, महाकाल मंदिर के विस्तार की योजना से सबने अपना-अपना विस्तार किया है। कहा तो यह भी जाता है कि कर्नाटक की तरह 40 प्रतिशत का खेल यहां भी खुलकर खेला गया। इसी वजह से 700 करोड़ की परियोजना 1150 करोड़ से भी ऊपर निकल गई। संभावना है कि यह राशि अभी और बढ़ेगी क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव भी तो होना है। फिर परियोजना तो परियोजना है। वह चाहे सिंचाई के लिए बन रहा बांध हो या फिर महाकाल का महालोक! पानी तो सबसे बहाया जाना है।

भक्तों की भीड़ के आगे छोटे पड़ते मंदिर प्रांगण के पिछले सालों में कई बार बदलाव किए गए। इसी नजरिए से वर्तमान भाजपा सरकार ने मंदिर को भव्य और विस्तृत आकार देने के लिए एक परियोजना तैयार की। इसे नाम दिया गया- महाकाल का महालोक। सरकारी जानकारी के मुताबिक जब इस परियोजना पर अंतिम फैसला हुआ था, तब इसकी अनुमानित लागत करीब 700 करोड़ थी। बाद में इसे बढ़ाकर 850 करोड़ किया गया। अब यह परियोजना 1150 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। अभी इस पर काम चल रहा है।

मंदिर परिसर विस्तार के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को किया था। पहले चरण पर करीब 365 करोड़ खर्च हुए थे। पहले चरण के उद्घाटन के समय खुद प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल के इस महालोक की जमकर तारीफ की थी। उद्घाटन के तत्काल बाद इस परियोजना में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। उस समय राज्य के लोकायुक्त ने इस परियोजना से जुड़े करीब डेढ़ दर्जन अफसरों को नोटिस भी दिए थे। इनमें तीन आईएएस अफसर भी शामिल थे। नोटिस के

निर्माण कार्यों के दस्तावेज नहीं दे रही उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी

उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के श्री महाकाल महालोक में हुए निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की तीन शिकायतों के बाद भी जांच के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रही है। जांच करने पहुंची लोकायुक्त संगठन की टीम को स्मार्ट कंपनी के अधिकारियों ने निर्माण से जुड़े दस्तावेज देने व दिखाने से मना कर दिया। इसके बाद लोकायुक्त संगठन की ओर से स्मार्ट सिटी के कार्यपालक निदेशक को नोटिस भेजकर फिर से निविदा समेत सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। नहीं देने पर जब्त करने की चेतावनी दी गई है। यह भी पूछा गया है कि सप्तऋषियों की मूर्तियां फाइबर रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक (एफआरपी) की लगाने का निर्णय कब लिया गया था। संगठन यह भी जांच कर रहा है कि मूर्तियों का निर्माण तय मापदंडों के अनुसार किया गया था या नहीं। महाकाल लोक के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत सबसे पहले तराना (उज्जैन) सीट से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने अगस्त 2022 में की थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में तराना के ही लक्ष्मण कुमार नामक व्यक्ति ने भी शिकायत की थी। 28 मई को आंधी में सप्तऋषियों में से छह मूर्तियां गिरने के बाद लोकायुक्त संगठन ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर एक और शिकायत दर्ज की है।

बाद क्या हुआ! यह या तो लोकायुक्त जानते होंगे या फिर खुद महाकाल! एक बात और! भाजपा ने सत्ता में आने के बाद उज्जैन में दो सिंहस्थ (महाकुंभ) का आयोजन कराया है। 2004 और 2016 के महाकुंभ में राज्य सरकार ने हजारों करोड़ व्यवस्थाओं पर खर्च किए थे। लेकिन इनमें ज्यादातर व्यवस्थाएं स्थाई साबित नहीं हुई हैं। अभी भी क्षिप्रा नदी का पानी साफ नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रंथ लिखे जा सकते हैं! सार यह है कि सिस्टम ने भगवान को भी नहीं बख्शा!

पूरे महाकाल लोक में करीब 136 मूर्तियां लगाई गई हैं। गत दिनों 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली तो सप्तऋषियों की सात में से छह मूर्तियां पेडस्टल से नीचे गिर गईं। 10 से 25 फीट ऊंची मूर्तियों को फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनाया गया है। एफआरपी से निर्मित सप्तऋषियों की मूर्तियां 10 फीट ऊंचे स्तंभ पर स्थापित थीं जो रूद्रसागर, त्रिवेणी मंडपम एवं कमल कुंड के बीच हैं। प्रशासन का कहना है कि तेज आंधी और बारिश का असर यहां ज्यादा था जिसकी वजह से सप्तऋषियों की मूर्तियों में से 6 मूर्तियां पेडस्टल से अलग होकर नीचे गिर गईं। 10 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण तीन क्विंटल वजन की यह मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं। यह मूर्तियां तो एफआरपी यानी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की बनी हैं। गुजरात की एमपी बावरिया फर्म से जुड़े गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के कलाकारों ने इसे बनाया था।

कांग्रेस के अनुसार, उज्जैन में जो मूर्तियां बनी हैं वे 150 जीएसएम के नेट की हैं जबकि कायदे से यह 400 जीएसएम की होती हैं। इनमें तीन लेयर होनी चाहिए, इस वजह से स्ट्रेंथ नहीं आई। फाउंडेशन के लिए आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कहा कि, धर्म के क्षेत्र का भ्रष्टाचार हमने अपनी आंखों से देखा। डीपीआर इन्होंने बनाकर दी, वहीं टेंडर हमने जारी कर दिया, ताकि मीन-मेख ना निकालें। 97 करोड़ का टेंडर था। इसका नियम था कुछ बढ़ाना है तो 10 प्रतिशत बढ़ा सकते हो ऊपर से 97 करोड़ का और दे दिया, 100 परसेंट भ्रष्टाचार का होता है। वर्तमान जज हाईकोर्ट जांच करें। कांग्रेसी और भाजपाई आरोप-प्रत्यारोप में उलझे

हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इस काम के लिए टेंडर 4 सितंबर 2018 को जारी हुआ, जब भाजपा की सरकार थी। स्वीकृति उज्जैन स्मार्ट सिटी ने 7 जनवरी 2019 को दी, जब कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। एलओए (लेटर ऑफ एग्रीमेंट) 25 फरवरी 2019 को मिला, वर्कऑर्डर 7 मार्च 2019 को जारी हुआ। स्कोप ऑफ वर्क में 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट एवं 15 फीट ऊंचाई की लगभग 100 एफआरपी की मूर्तियां शामिल थीं। लागत 7 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान था।

मूर्तियों की सामग्री की आपूर्ति का भुगतान 13 जनवरी 2020 को, डिजाइनिंग, नक्काशी का भुगतान 28 फरवरी 2020 को और मूर्ति स्थापना के काम का भुगतान 31 मार्च 2021 को किया गया था। सीपेट ने 12 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दी, जिसमें एफआरपी सामग्री को मानकों के मुताबिक बताया। आईपीई ग्लोबल ने काम का मूल्यांकन, सत्यापन और पर्यवेक्षण किया। डीएलपी यानी (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) में होने की वजह से ठेकेदार मूर्तियां फिर से स्थापित करेगा। जब महाकाल लोक बना तो भाजपा ने इसे अपनी उपलब्धि बताया, कांग्रेस ने अपनी। जब मूर्तियां खंडित हुईं तो भाजपा कांग्रेस का, कांग्रेस भाजपा का निर्माण बता रही है। जनता कन्फ्यूज है।

धरमपुरी के कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा ने विधानसभा में सवाल पूछा था कि महाकाल लोक पर कुल कितनी राशि व्यय हुई? अनुबंध किस एजेंसी व फर्म से किया गया? उसमें क्या-क्या शर्तें रखी गई थीं? क्या कॉरिडोर में बनाई गई मूर्तियां अनुबंध के अनुसार नहीं हैं? फाइबर व अन्य धातु की मूर्ति लगाई हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई? इस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जवाब में कहा था कि नवनिर्मित महाकाल कॉरिडोर में (उस समय तक) 161 करोड़ 83 लाख 890 रुपए व (जीएसटी का अतिरिक्त) व्यय हुआ है। इस कार्य का अनुबंध ज्वाइंट वेंचर एमपी बावरिया, डीएच पटेल व गायत्री इलेक्ट्रिकल नामक फर्म व एजेंसी से किया गया था। कॉरिडोर में बनी मूर्तियां अनुबंध के अनुसार ही हैं। श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति, संस्कृति विभाग तथा सभी हितग्राहियों के परामर्श के अनुसार ही कॉरिडोर का काम, मूर्तियों का चयन व प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया। उन्होंने यह नहीं बताया था कि अनुबंध के तहत महाकाल लोक में मूर्तियों का निर्माण फाइबर से होना था, धातु से या फिर पत्थरों से?

● **सुनील सिंह**

तत्कालीन अधीक्षण यंत्री धर्मेंद्र वर्मा की भूमिका पर सवाल

सबसे हैरानी की बात यह है कि सिंहस्थ के दौरान विवादों में घिरे पीएचई के एई रहे धर्मेंद्र वर्मा को स्मार्ट सिटी उज्जैन का सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर बनाकर महाकाल लोक के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। सवाल यह उठता है कि जल कार्य वाले विभाग के इंजीनियर को सिविल वर्क की जिम्मेदारी किसने दी? वर्मा की नियुक्ति बताती है कि व्यवस्था में किस तरह का घालमेल था। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत कर कहा था कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए स्मार्ट सिटी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंशुल गुप्ता ने टेंडर में न्यूनतम निविदाकार होने के बाद भी एमपी बावरिया को काम दिया। टेंडर में जीआई शीट लगानी थी, जिस पर 22 लाख रुपए का खर्च होना था। ठेकेदार ने इसकी जगह पोली-काबोर्नेट शीट लगाई। यह अतिरिक्त आइटम जोड़ा गया। इससे ठेकेदार को एक करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ पहुंचा है। लोकायुक्त ने कांग्रेस विधायक महेश परमार की शिकायत पर जिम्मेदार अफसरों को नोटिस भी भेजा था, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है।

आठ हजार जल स्त्रोत सूखे

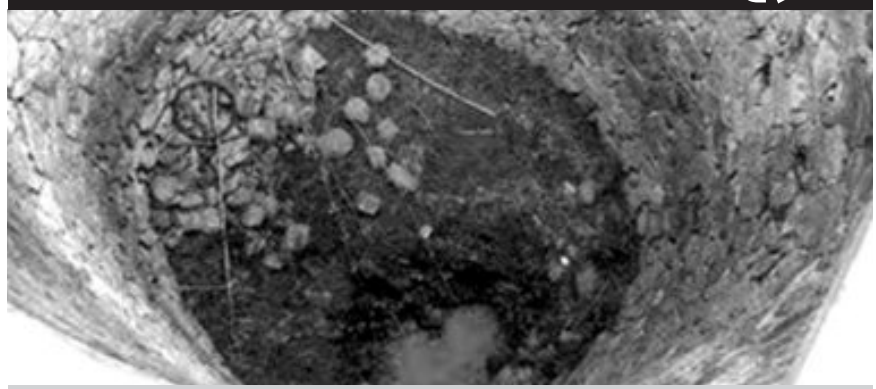

देश में 55 प्रतिशत जल स्त्रोत निजी

अगर देशभर के आंकड़ों को देखा जाए तो मौजूदा जल स्त्रोतों में से 55.2 प्रतिशत यानी की आधे से अधिक निजी स्वामित्व के हैं, जबकि शेष पंचायत, नगरीय निकाय राज्य के जल संसाधन विभाग के अधीन हैं। इसी तरह से मप्र में 47,153 जल स्त्रोत पंचायतों के अधीन आते हैं, जबकि सरकारी एजेंसियों के हवाले 22,780 और 859 सिंचाई विभाग के तहत आते हैं। इसी तरह से निजी मालिकाना हक वालों के पास 11,700 से अधिक जल स्त्रोत हैं। इसमें भी जो सबसे खराब स्थिति मिली है वह है तालाब, झीलों, टैंक, जलाशयों, चेक डेम और जल संरक्षण की योजनाओं के मामलों में मप्र का स्थान देश के टॉप 5 राज्यों में भी नहीं है।

एक तरफ प्रदेश में पानी का संकट बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर 50 फीसदी ऐसे जल स्त्रोत हैं, जिनका प्रदेश में उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। अगर इन सभी स्त्रोतों का उपयोग किया जाए तो प्रदेश में जल संकट काफी हद तक समाप्त हो सकता है। प्रदेश में इसको लेकर क्या स्थिति है ये इससे ही समझी जा सकती है कि गैर उपयोग में आने वाले जल स्त्रोतों के देश के औसत में मप्र का तीन गुना अधिक है। यह खुलासा हुआ है हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देशभर में मौजूद जल स्त्रोतों की कराई गई गणना में। यह आंकड़ें परेशान करने वाले हैं। प्रदेश में जल स्त्रोतों को बारहमासी बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं बनाकर उन पर किया गया क्रियान्वयन भी जुटाए गए आंकड़ों से सच को उजागर करता है।

हद तो यह है कि इसमें करीब 2300 से अधिक जल स्त्रोत तो ऐसे मिले हैं, जिन पर या तो पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है या फिर इतना अधिक निर्माण कर उन्हें बर्बाद कर दिया है कि अब उनका उपयोग किया जाना ही संभव नहीं है। इस मामले में इनके संरक्षण का काम करने वाले विभागों से लेकर उन संस्थाओं की भी पोल खुल जाती है जो इनकी देखरेख या फिर अतिक्रमण हटाने या उस पर कार्रवाई करने का काम करती हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो मप्र में आठ हजार जलस्त्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं। इसकी वजह इनके रिचार्ज के लिए सरकारी स्तर पर पूरी तरह से लापरवाही बरती जाना है। गणना के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 82 हजार से अधिक जलस्त्रोत पाए गए हैं, जिनमें से 45 हजार बेकार हो चुके हैं। इन आंकड़ों के लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों के 24 हजार से अधिक गांवों को गणना में शामिल किया गया था। इसमें 78,298 तालाब, 71 टैंक, 30 झील, 75 जलाशय, 337 जल संरक्षण योजना के डेम व अन्य प्रकार के करीब 2201 जल स्त्रोत मिले हैं। इस प्रकार से प्रदेश में जल स्त्रोतों की कुल संख्या 81012 है। अगर शहरों की बात की जाए तो प्रदेश में 1520 तालाब, 110 अन्य तरह के स्त्रोत और एक वॉटर कंजर्वेशन स्कीम का जल स्त्रोत मिला है। इनमें से 36628 तालाब, 41 टैंको, 17 झीलों, 48 जलाशयों 220 चेकडेमों व 303 अन्य तरह के ही जल स्त्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। खास बात यह है जिन जल स्त्रोतों का उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें सर्वाधिक 43190 तालाब शामिल हैं।

प्रदेश की गणना में पता चला है कि 8036 वॉटर बॉडीज तो ऐसी हैं, जिनमें पानी सूख जाने की वजह से उनका उपयोग किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा 1366 पर निर्माण कर लिया गया है, जबकि 917 जल स्त्रोत इतने जीर्ण-शीर्ण हालात में पहुंच चुके हैं कि वे मरम्मत तक की स्थिति में नहीं रह गए हैं। इसके अलावा 594 जल स्त्रोत ऐसे हैं, जिनका रखरखाव नहीं होने से उनमें में गाद भर गई है, जबकि उद्योगों की गंदगी की वजह से 168 जल स्त्रोतों का पानी इस्तेमाल करने लायक ही नहीं बचा है। इसके बाद भी महज 1421 जल स्त्रोतों की मरम्मत या रिनोवेशन के काम को ही हाथ में लिया गया है।

लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के मामले में मप्र को पहला स्थान मिला है। हर मापदंड पर पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए यह मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान की प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह उपलब्धि सामने आई है। अभियान का लक्ष्य जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्राम, जिला एवं राज्य स्तर पर व्यापक जन-भागीदारी और पानी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। अभियान में रासायनिक मापदंडों और जीवाणुतत्व संबंधी मापदंडों का पता लगाने के लिए सभी गांवों में पीडब्ल्यूएस स्त्रोतों का परीक्षण, गांवों में घरेलू स्तर पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, दूषित नमूनों के लिए किए गए। पर्याप्त मात्रा के साथ स्वच्छ जल की उपलब्धता जल जीवन मिशन का प्रमुख घटक है। सुरक्षित और स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ जल से सुरक्षा (एसजेएसएस) अभियान चलाया गया। अभियान की रिपोर्ट में मप्र को अग्रणी राज्य में शामिल किया गया है। पर्याप्त मात्रा के साथ स्वच्छ जल की उपलब्धता जल जीवन मिशन का प्रमुख घटक है। सुरक्षित और स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान चलाया गया। अभियान की रिपोर्ट में मप्र को अग्रणी राज्य में शामिल किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देशव्यापी अभियान में 2 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी और निरीक्षण की गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया। अभियान में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आंकलन कर रिपोर्ट जारी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर शुद्ध जल पहुंचाने के संकल्प में मप्र सरकार तेजी से कार्य कर रही है। स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान की उपलब्धि मप्र के विकास के जनभागीदारी मॉडल का एक और सशक्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र में सरकार एवं नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने इस उपलब्धि पर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, नागरिकों एवं टेस्टिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने वाली समस्त महिलाओं को बधाई दी है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

लोकायुक्त भिजवा रहा जेल

भ्रष्टाचार के मामलों में विशेष पुलिस स्थापना यानी की लोकायुक्त संगठन का रुख सख्त बना हुआ है, जिसकी बदौलत ही हर माह औसतन आठ भ्रष्टों को सजा दिलावाई जा रही है। अगर इस मामले में सरकार का पूरा सहयोग लोकायुक्त को मिले तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। दरअसल कई मामले ऐसे हैं, जिनमें लोकायुक्त संगठन को चालान पेश करने की अनुमति का लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। इससे इतर भ्रष्टाचार के लंबे समय से लंबित चल रहे मामलों के निराकरण के लिए अब लोकायुक्त पुलिस द्वारा नई रणनीति तैयारी की गई है। इसके तहत जल्द विवेचना करने के बाद मामलों को पुख्ता प्रमाणों के साथ न्यायालय में मजबूत तथ्यों के साथ पेश किया जा रहा है।

यही वजह है कि बीते एक साल में 98 भ्रष्टाचारियों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। अगर सजा का औसत निकाला जाए तो एक साल में कुल पेश किए गए चालानों में सजा का प्रतिशत 70 रहा। इसमें भी खास बात यह है कि कुछ 8 से 15 साल पुराने सात मामलों में लोकायुक्त संगठन ने भ्रष्टाचारियों को न केवल अलग-अलग धाराओं में सजा दिलाई है, बल्कि उन पर करोड़ों रुपए का अर्थदंड भी लगवाया है। अधिकृत जानकारी के मुताबिक बीते वर्ष यानी की वर्ष 2022 में मप्र लोकायुक्त संगठन ने भ्रष्टाचार के कुल 279 प्रकरण दर्ज किए थे, इनमें 252 मामले तो रिश्वत लेते पकड़े जाने के ही हैं। इसके अलावा 17 प्रकरण वे हैं, जिनमें लोकायुक्त संगठन द्वारा छापे मारे गए थे, जबकि 10 मामले पद के दुरुपयोग के शामिल हैं।

अगर इन मामलों की तुलना वर्ष 2021 के मामलों से करें तो बीते साल 12 प्रतिशत मामले अधिक दर्ज किए गए। वहीं रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के मामलों में भी 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। बीते साल लोकायुक्त पुलिस ने 2022 में कुल 358 प्रकरणों में विवेचना पूरी की है, जिसमें 269 रंगे हाथों रिश्वत लेने के, 25 अनुपातहीन संपत्ति के मामले में मारे गए छापे के और 64 प्रकरण पद के दुरुपयोग के शामिल हैं। इसी तरह से लोकायुक्त पुलिस ने प्राथमिक जांच के 52 मामलों का भी निराकरण किया है।

बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार के मामले में बेहद रौद्र रुख दिखा रहे हैं। शायद यही वजह है कि अफसरों को न चाहते हुए भी ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी पड़ रही है। हाल ही में ऐसे ही एक मामले में एक अफसर को सेवा से बर्खास्त तक किया जा चुका है। यही नहीं बीते दो माह में 75 मामलों में 119 शासकीय सेवकों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सर्वाधिक 23 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राजस्व में 12, नगरीय विकास एवं आवास में 9, स्वास्थ्य में 8, गृह और कृषि विभाग में 6-6 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के चार प्रकरण शामिल हैं। ऐसे मामलों में अब मुख्यमंत्री खुद विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि वे 15 जून के बाद कार्यवाही की जानकारी लेंगे। यदि विभाग किसी प्रकरण में कार्यवाही में विलंब करता है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर लोकायुक्त को चालान के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेना होती है। विभाग इन्हें विधि और विधाई विभाग (लॉ डिपार्टमेंट) के पास अभिमत के लिए भेजता है। स्वीकृति की समय सीमा तय है, लेकिन ज्यादातर मामलों में प्रभाव का उपयोग कर, विधि विभाग के अभिमत के नाम पर अटका दिए जाते हैं। यदि कर्मचारी के संबंधित विभाग और विधि विभाग की राय में मत भिन्नता होती है तो फिर इसे कैबिनेट के पास भेजा जाता है। यही वजह है कि फिलहाल 200 से अधिक मामले अब भी दोनों जांच एजेंसियों के अनुमति के अभाव में पड़े हुए हैं। यह वे मामले हैं, जिनकी जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन चालान पेश नहीं हो पा रहा है।

● **राकेश ग्रोवर**

इन मामलों में लगा बड़ा अर्थदंड

लोकायुक्त के जिन मामलों में सजा के साथ बड़ा अर्थदंड लगा है, उनमें तत्कालीन तहसील संयोजक, ग्राम रक्षा समिति ग्वालियर हरीश शर्मा के खिलाफ 2008 में दर्ज प्रकरण में 24 जनवरी 2022 को विशेष न्यायालय ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी तरह से बालू सिंह सिसोदिया, तत्कालीन सहायक यंत्री एवं विद्युत सुरक्षा निरीक्षक रतलाम, प्रभारी विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग गरोठ, जिला मंदसौर के खिलाफ 2009 में दर्ज प्रकरण में विशेष न्यायालय ने 5 जनवरी 2022 को 4 साल के सश्रम कारावास और 20 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अनिल कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोहावल, जिला सतना के विरूद्ध वर्ष 1998 में अलग-अलग धाराओं में दर्ज चारों मामलों में विशेष न्यायालय ने 27 दिसंबर 2022 को क्रमशः 2 वर्ष की जेल एवं दो हजार रुपए अर्थदंड, 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड, 3 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड एवं 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एक अन्य मामले में प्रीतम सिंह मान के खिलाफ 2014 में दर्ज प्रकरण में 14 जुलाई 2022 को सुनाए गए निर्णय में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी तरह से तत्कालीन एसडीओपी तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जीपी शर्मा को विशेष न्यायालय दमोह ने विगत 24 नवंबर को 3 वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

अमृत सरोवर योजना में पिछड़ा मप्र

मप्र के अफसरों की कार्यशैली ऐसी है कि कभी भी कोई भी विकास का काम समय पर पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से न केवल सरकारी खजाने पर आर्थिक भार बढ़ जाता है, बल्कि आमजन को भी मिलने वाली सुविधा का लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही मामला है अमृत सरोवर योजना का। जिसकी वजह से प्रदेश में इस योजना के तहत बनाए जाने वाले 7442 जलाशयों में से 3433 पर तो काम ही शुरू नहीं किया गया है। अब चंद दिनों बाद मानसून दस्तक दे देगा, जिससे इन पर काम होना संभव नहीं है।

इसकी वजह से एक बार फिर से प्रदेश में अमृत सरोवरों के कामों पर पूरी तरह से ब्रेक लगना तय है। प्रदेश में यह हाल तब है, जबकि यह योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में पहले से ही प्रदेश पीछे चल रहा है। योजना के हाल इससे ही समझे जा सकते हैं कि प्रदेश में चिन्हित 7442 जलाशयों में बीते एक साल में सिर्फ 4019 का ही काम पूरा हो पाया है। इन 7442 अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए जगह चिन्हित करने और उनके लिए 7 हजार 581 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट भी रखा गया है। दरअसल प्रदेश के हर जिले में औसतन योजना के तहत 100 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इसकी वजह है इनसे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। जल संरक्षण के लिए **प्रदेशव्यापी अभियान** के तहत निर्मित यह सरोवर सिंचाई, मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन के साथ धार्मिक व पर्यटन के प्रायोजनों को भी पूरा करते हैं। इसका निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया जा रहा है। इसके बाद भी प्रदेश के कई जिलों में 50 अमृत सरोवर भी नहीं बन सके हैं। अगर जिलों की स्थिति देखें तो टीकमगढ़ में 51, शाजापुर में 56, शहडोल में 76, राजगढ़ में 58, रायसेन में 63, नरसिंहपुर में 31, रायसेन में 63, होशंगाबाद में 67, हरदा में 43, छतरपुर में 65 अमृत सरोवर ही बन पाए हैं। हालांकि इस मामले में छिंदवाड़ा में सबसे अच्छा काम हुआ है। छिंदवाड़ा में सर्वाधिक 198 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा किया गया है। इस मामले में दूसरा नंबर मुरैना जिले का है जहां पर 148, तीसरे नंबर पर भिंड है, जहां पर 121 जल संरचनाओं को अमृत सरोवर में बदला गया है, जबकि बैतूल में 106 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना से प्रत्येक जिले में 100 तालाब बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में लगभग 4 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इस हिसाब से एक तालाब पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे। योजना के विस्तार तथा उद्देश्य के मद्देनजर राशि को बहुत कम माना गया है। इसको देखते हुए गांवों में जनभागीदारी से राशि एकत्र करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

योजना के तहत कम से कम 100 तालाब प्रत्येक जिले में विकसित करने का टारगेट है। लक्ष्य को पूरा करने में कई जिले अव्वल साबित हो रहे हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में केंद्र सरकार के टारगेट का दोगुना लक्ष्य 30 मई तक पूरा होने की संभावना है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक अमृत सरोवर योजना के तहत उज्जैन जिले की अलग-अलग तहसीलों में 200 तालाब विकसित किए जा रहे हैं। टारगेट 30 मई तक पूरा होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून महीने में उज्जैन आ रहे हैं। उज्जैन आगमन पर प्रधानमंत्री से अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाब का उद्घाटन भी कराया जा सकता है।

अमृत सरोवर योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेंगे। इलाकों में बनाए गए बड़े तालाब से पानी का भंडारण होगा और जलस्तर भी ऊपर आएगा। इसके अलावा कृषि कार्य में भी आवश्यकता अनुसार जल का उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में पशु-पक्षी के लिए भी तालाब काफी कारगर साबित होंगे। तालाब का निर्माण करने में सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक तालाब पर लगभग 4 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। राशि का निर्धारण स्थान और परिस्थिति अनुसार कम ज्यादा हो सकता है। इस तरह तालाब के विकास में लगभग 4 करोड़ की राशि का बजट है। उज्जैन में राशि दोगुनी अर्थात् 8 करोड़ रुपए के आसपास है।

संसाधनों का लगातार दोहन की वजह से, पूरे देश के समक्ष ग्राउंड वाटर लेवल की कमी की समस्या के रूप में आ रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में भूमिगत जल की गिरावट को देखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है, ताकि देश में जल संरक्षण को बल मिले। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार, किसानों के लिए अमृत सरोवर योजना लाई है। योजना के तहत 50 हजार तालाब किसानों को दिए जाने हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ जल संरक्षण को बल मिलेगा बल्कि किसानों की आय में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। किसान इन तालाब से सिंचाई और मछलीपालन दोनों का फायदा उठा सकते हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

तेजी से लक्ष्य हो रहा है पूरा

ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमृत सरोवर योजना देश में तेजी से काम कर रही है। 11 महीने के अंदर ही कुल लक्ष्य का 80 प्रतिशत काम को पूरा कर लिया गया है। सरकार योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। 54 हजार से भी ज्यादा बनाए गए उपभोक्ता समूह की वजह से योजना की दिशा सकारात्मक है, किसान तालाब में न सिर्फ मछलीपालन बल्कि मखाने की खेती, कमल की खेती, सिंघाड़े की खेती के अलावा बत्तख पालन से भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अमृत सरोवर योजना के फायदे या लाभ की बात करें तो इससे किसानों का तीन तरीके से मुनाफा होगा। आज देश के ज्यादातर राज्यों में कृषि सिंचाई के लिए जल की कमी हो रही है। यही वजह है कि अमृत सरोवर योजना को तमिलनाडु, मप्र, राजस्थान, उप्र, झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में प्रमुखता से लाया जा रहा है। राजस्थान, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में बढ़ते पानी के संकट को दूर करने के लिए जरूरी है कि इस तरह की योजनाएं चलें। गौरतलब है कि जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सिंचाई के लिए कई जगह पर पानी की भारी समस्या बन गई है। नलकूपों में पानी की कमी हो रही है। लगातार घट रहे भू-जल स्तर को बढ़ाने का यही तरीका है कि किसानों को बारिश के जल को ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चूंकि तालाब निर्माण जल संग्रहण का एक बेहतरीन तरीका है इसलिए सरकार किसानों को तालाब निर्माण या पोखर निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

मुफ्त की रेवड़ियां या कर्ज की बेड़ियां

बड़ी संख्या में लोगों को बना दिया निठल्ला

हालांकि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजना, शिक्षा के लिए सहायता, स्वास्थ्य के लिए व्यय में वृद्धि जैसे उपहारों से उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मजबूत कार्य संस्कृति विकसित करने में मदद मिलती है। अत्यंत गरीबी से पीड़ित आबादी के लिए यह मदद डूबते को तिनके का सहारा जैसी है, लेकिन सार्वजनिक धन से मुफ्त का वादा शुद्ध चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित तो करता ही है, बड़ी संख्या में लोगों को निठल्ला भी बना देता है। हमें समझना होगा कि महिलाओं को बस में मुफ्त पास की तुलना में यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अगर लोगों को भरोसा हो कि सरकारें उनकी जरूरतों का ख्याल रख रही हैं तो उन्हें मुफ्त उपहारों की जरूरत शायद नहीं होगी। संसदीय लोकतंत्र सत्ता के साथ-साथ विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों की ताकत पर निर्भर करता है। दलों को अपनी योजनाओं और घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करते समय अधिक जिम्मेवार बनते हुए रणनीतियों का विश्लेषण करना चाहिए। अगर सत्ता में बैठे दल रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई को पूरा करते हुए रोजगार और व्यवसाय के अवसर निर्मित करते हैं तो उन्हें चुनाव जिताने की गारंटी वाले फॉर्मूले की तरह मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं होगी।

सतत् लाभ अर्जित करने के अर्थशास्त्र में दो स्थापित सिद्धांत है। पहला, खर्चे में कटौती का नाम ही आमदनी है, और दूसरा, बांटते रहने से लाभ बढ़ता जाता है। अर्थशास्त्र के इस दूसरे नियम पर चलते हुए यानी मुफ्त की रेवड़ी बांटकर सस्ती लोकप्रियता और अधिकाधिक वोट कमाने का धंधा राजनीति शास्त्र ने अख्तियार कर लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुफ्त लुटाने की योजना न तो टिकाऊ है और न ही व्यवहारिक, फिर भी इसकी जमीनी सच्चाई हाथी के दांत (खाने के और, दिखाने के और) की तरह है। वोट की खातिर मुफ्त रेवड़ी संस्कृति की गंगा में डुबकी लगाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। कोई किसी से उन्नीस नहीं है, सब बीस बनकर बाजी मार लेना चाहते हैं।

यह चलन पिछले एक-दो दशकों में खूब बढ़ा है और मुफ्त उपहार भारत में राजनीति का अभिन्न अंग बन गया है। आज भले ही कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की मुफ्त योजनाओं के कारण चर्चा हो रही हो लेकिन मुफ्त की योजनाओं के मामले में दक्षिण का तमिलनाडु राज्य चैंपियन रहा है। अब यह प्रथा उत्तर के राज्यों में भी फैल चुकी है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस पास, मुफ्त बिजली-पानी आदि की घोषणा की है। देखा देखी पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मप्र, राजस्थान में भी मुफ्त की संस्कृति सिर चढ़कर बोल रही है। अब तो कई एक राजनीतिक दल जिनकी सरकारें मुफ्त उपहार के बल पर किसी राज्य में सत्ता में है, वे दूसरे राज्यों के चुनाव में मुफ्त उपहारों की नजीर देकर वोट मांगते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अलग-अलग राज्यों में मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति को आगे कर अपना जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। यह जानते हुए भी कि भगवान के आशीर्वाद के अलावा दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। लोग मुफ्त की आस लगाए हुए हैं। यह एक आत्मघाती मानसिकता है क्योंकि करदाताओं का पैसा ही सरकारें मुफ्त के नाम पर लोगों में बांटकर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लेती हैं। आम जीवन में अनेक लोग मुफ्त की संस्कृति के खिलाफ मुखर भी होते हैं, किंतु राजनीतिक पार्टियां उनकी अनदेखी कर, सरल मार्ग की तरह इसे पकड़े हुए हैं।

मुफ्त की घोषणाओं को पूरा करने के चलते राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐसे राज्यों को चिन्हित किया है जिनका कर्ज उनकी धारण क्षमता से बहुत अधिक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल, उप्र, बिहार में औसतन सरकारी उधारी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक हो गई है। भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऋण मिलाकर ही सरकार के ऋण माने जाते हैं। राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति ने वर्ष 2017 में यह सुझाव दिया था कि जीडीपी के अनुपात में ऋण की सीमा अधिकतम 60 प्रतिशत होनी चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार की ऋण सीमा 40 प्रतिशत और राज्य सरकार की 20 प्रतिशत होनी चाहिए। कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार की सीमा वर्ष 2019-20 में 62 प्रतिशत तक पहुंच गई थी लेकिन वर्ष 2021-22 में घटकर 57.33 प्रतिशत तथा 2022-23 में 55.88 प्रतिशत तक आ गई है।

लेकिन राज्य सरकारों की देनदारियां जीडीपी के अनुपात में समान वर्षों में क्रमश: 26.66 प्रतिशत, 31.8 प्रतिशत, 28.71 प्रतिशत रही हैं। यदि दोनों को जोड़ दें तो कुल देनदरियां 60 प्रतिशत की सीमा से बहुत अधिक हो जाती हैं। केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर कुल देनदारियां वर्ष 2019-20 में 77 प्रतिशत, 2020-21 में 92 प्रतिशत, 2021-22 में 86 प्रतिशत और 2022-23 में 84 प्रतिशत की रही है। भारत के महालेखाकार (कैग) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि अधिकांश राज्यों में ऋण जीडीपी अनुपात लक्षित 20 प्रतिशत से दो गुना से भी ज्यादा है। पंजाब में लगभग 49 प्रतिशत, राजस्थान में 43 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 38 प्रतिशत, बिहार में 37 प्रतिशत, मप्र में 32 प्रतिशत, उप्र में 31 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

कैग के आंकलन के मुताबिक उन राज्यों के ऊपर कर्ज की रकम लगातार बढ़ती जा रही है जहां मुफ्त की योजनाओं पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसमें सबसे ऊपर पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। दिल्ली में भी मुफ्त योजनाओं की बाढ़ है, लेकिन यहां प्रति व्यक्ति राजस्व शेष भारत से दोगुना से भी कुछ अधिक है, इसलिए स्थिति अभी उतनी भयावह नहीं है। लेकिन दिल्ली में भी बुनियादी ढांचे के विकास के काम लगभग रुक गए हैं। जाहिर है कि कोई भी राज्य अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा मुफ्त की योजनाओं पर लुटा देगा तो आवश्यक सेवाओं और बुनियादी विकास पर पूंजीगत खर्च कम होता जाएगा। कर्ज का जाल बढ़ेगा और अंतत: यह सभी भार देश के करदाताओं और आम लोगों के सिर पर ही जाएगा।

● **बृजेश साहू**

फर्जी बैंक गारंटी का खेल

मप्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाले आबकारी विभाग को हर बार की तरह इस बार भी शराब ठेकेदारों ने अरबों रुपए की चपत लगाई है। दरअसल, ठेकेदारों ने फर्जी बैंक गारंटी लगाकर यह खेल खेला है। भोपाल में कलेक्टर की जांच में दो दुकानों का मामला सामने आने के बाद उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वहीं प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर के पास शिकायत पहुंची है कि रीवा जिले में कई दुकानें भी फर्जी बैंक गारंटी लगाकर ली गई हैं, जिससे सरकार को 500 करोड़ रुपए की चपत लगने का अनुमान है।

गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार और आबकारी विभाग शराब की खरीदी और बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन शराब का कारोबार करने वाले अपना खेल खेलने का रास्ता निकाल लेते हैं। इस बार रीवा जिले में शराब कारोबार में बड़ा फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। करोड़ों की फर्जी बैंक गारंटी आबकारी विभाग को थमा दी गई। जिला सहकारी बैंक मोरबा सिंगरौली से जारी बैंक गारंटी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 500 करोड़ के घोटाले का अंदेशा जताया गया है। इसकी शिकायत प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग और रीवा संभाग के कमिश्नर से की गई है।

जानकारी के अनुसार 500 करोड़ के इस संभावित घोटाले में शराब के कारोबार में ठेकेदार, आबकारी अधिकारी और सहकारी बैंक मैनेजर ने बड़ा खेल किया है। शराब दुकान के ठेके में जमा होने वाले बैंक गारंटी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सहकारी बैंक की बैंक गारंटी बिना मान्यता के ही जमा कर ली गई। इसमें भी एफडीआर और प्रापर्टी मॉड्रगेज नहीं कराया गया। बैंक गारंटी का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग के जिला अधिकारी और मऊगंज सर्किल प्रभारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। रीवा जिला के कई शराब दुकानों के लिए जमा की गई करोड़ों रुपए की बैंक गारंटी फर्जी बताई जा रही है। हालांकि इसकी जांच की मांग की गई है। दावा किया जा रहा है कि बैंक गारंटी की जांच की जाए तो कई सारे राज बाहर आ सकते हैं। राजपत्र में सहकारी बैंक की मान्यता नहीं होने के बाद भी बैंक गारंटी क्यों ली गई। महालक्ष्मी ग्रुप के ठेके कई सर्किल में हैं लेकिन एक ही सर्किल प्रभारी मनोज बेलवंशी से ही क्यों सत्यापन कराया गया। रीवा के रायपुर कर्चुलियान शराब दुकान में 24 घंटे के अंदर बैंक गारंटी कैसे बन गई, जबकि ठेका 26 मार्च को हुआ और 28 मार्च को बैंक गारंटी विभाग को प्रस्तुत की गई। बैंक ने सारे कागज में हाथ से लिखित सत्यापन को विभाग के अधिकारियों ने कैसे मान्य कर लिया। बैंक गारंटी बनाने के लिए शाखा प्रबंधक एवं बैंक की खुद की स्वीकृति की सीमा होती है। इससे ऊपर के लिए कमेटी की स्वीकृति लेना जरूरी है। मैनेजर ने इतनी बड़ी राशि की बैंक गारंटी कैसे बना दी।

गौरतलब है कि फर्जी बैंक गारंटी से ही अब तक ठेकेदार धड़ल्ले से शराब उठाते रहे और दुकानों का संचालन करते रहे। ऐसे में यदि शराब ठेकेदार भाग खड़े हुए तो शराब दुकान की फीस भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। सहकारी बैंक से बनी बैंक गारंटी से करीब 500 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता बीके माला ने कमिश्नर रीवा संभाग से शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है। इसके अलावा एक शिकायत प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग से भी की गई है।

यदि किसी दुकान का शराब ठेका होता है तो उस दुकान की फीस का 5 परसेंट लाइसेंस फीस विभाग तुरंत ले लेते हैं। 95 फीसदी राशि सालभर में 12 महीने में ठेकेदार को जमा करना होता है। उसकी ड्यूटी मई और जून में 10-10 फीसदी राशि देना रहता है। इसी राशि के एवज में शराब बेचने के लिए ठेकेदार को दी जाती है। ठेकेदार फीस न जमा करे और भाग खड़ा हो इसकी सिक्योरिटी के तौर पर ही टोटल वैल्यू का 10 फीसदी बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है। यदि ठेकेदार जमा किए बिना भाग खड़ा हो तो विभाग इस राशि को बैंक से भुना सकता है। बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक संबंधित फर्म और व्यक्ति के सिक्योरिटी के तौर पर चल, अचल संपत्ति डिपॉजिट कराता है। तब जाकर बैंक गारंटी जारी की जाती है।

● **राजेश बोरकर**

भोपाल में लाइसेंस रद्द

भोपाल में एक शराब ठेकेदार ने 1 करोड़ 84 लाख की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर शराब दुकानों को ले लिया। आबकारी विभाग के इस घोटाले का खुलासा तब हुआ, जब कलेक्टर आशीष सिंह ने इसकी जांच कराई। कलेक्टर ने दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही लाइसेंसियों के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। अब दोनों शराब दुकानों का नए सिरे से टेंडर कराया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक दुकान का संचालन आबकारी अमले के द्वारा किया जाएगा। दरअसल, कंपोजिट मदिरा समूह लालघाटी की दो दुकानें 22 करोड़ 34 लाख 38 हजार 213 रुपए में नीलाम हुई थीं। इसे उच्चतम ऑफर देते हुए राठौर एंड मेहता एसोसिएट्स ने लिया था। ग्रुप को निर्धारित देय अग्रिम राशियां 31 मार्च तक जमा करना था। लाइसेंसी के द्वारा 10 अप्रैल को निर्धारित राशि की बैंक गारंटी क्रमांक 0789/जीईएफ/00010 बैंक की 1 करोड़ 84 लाख रुपए का डीडी जमा की गई। यह डीडी 7 अप्रैल को बनाई गई थी। 19 अप्रैल को अरेरा हिल्स स्थित ब्रांच से डीडी के सत्यापन के लिए सहायक जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए गए थे। सहायक आबकारी अधिकारी के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में बताया गया कि शाखा से कई बार संपर्क करने के बाद भी बैंक गारंटी का सत्यापन नहीं हुआ। बताया गया कि इस संबंध में बैंक गारंटी जारी नहीं की गई है। इस बैंक गारंटी के सत्यापन को लेकर बैंक कार्यालय ईमेल किया गया। 26 मई को बैंक की तरफ से जवाब आया कि उनके यहां से यह बैंक गारंटी जारी नहीं की गई है।

निवेशकों के लिए बंजर बना बुंदेलखंड

उद्योगों का सूखा झेल रहे बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले के लिए वर्ष 2018 में उप्र सरकार का इन्वेस्टर्स समिट एक सौगात लेकर आया था। इसमें इंग्लैंड की कंपनी एबी मौरी ने 400 करोड़ रुपए की लागत से खमीर प्लांट लगाने का एमओयू किया था। प्रदेश सरकार ने भी तेजी दिखाते हुए दो साल के भीतर चित्रकूट से मीरजापुर हाईवे पर मौजूद बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में 68 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी थी। खमीर फैक्ट्री लगने से बुंदेलखंड के करीब 2,000 लोगों में नौकरी की आस भी जगी थी। चित्रकूट के राजकीय इंटर कॉलेज में प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद बरगढ़ गांव में रहने वाले सत्यप्रकाश विश्वकर्मा का कहना है कि दो साल से लोग बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में खमीर की फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।

सत्यप्रकाश के जेहन में करीब 34 वर्ष पूर्व की यादें ताजा हो जाती हैं जब 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी कांटीनेंटल ग्लास फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। सत्यप्रकाश कहते हैं कि शिलान्यास के पहले साल तो बहुत तेजी से निर्माण कार्य हुआ, लेकिन 1989 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सत्ता से हटने के बाद फैक्ट्री का निर्माण कार्य ठप हो गया। उसके बाद से किसी भी सरकार ने ग्लास फैक्ट्री की सुध नहीं ली। आज बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में वीरानी छाई हुई है। बंद पड़े ग्लास फैक्ट्री के परिसर को बड़ी-बड़ी झाड़ियों ने ढंक लिया है। चित्रकूट के जिला उद्योग अधिकारी संदीप केसरवानी का कहना है कि चित्रकूट में खमीर प्लांट लगाने वाली कंपनी एबी मौरी ने अधिक जमीन की मांग की थी इसलिए उसे पीलीभीत जिले में 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। बरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में खमीर प्लांट के लिए आवंटित जमीन पेप्सिको की सहायक कंपनी वरुण बेवरेज को आवंटित की गई है। यह अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य शुरू कर देगी।

धर्मनगरी चित्रकूट की तरह इसके बगल का जिला बांदा भी औद्योगिक निवेश की राह तक रहा है। जिले में चिल्ला रोड पर जिले की इकलौती औद्योगिक इकाई राजकीय कताई मिल दिसंबर, 1998 से बंद है। वर्ष 2018 के इन्वेस्टर्स समिट में बंद पड़ी कताई मिल की जगह पर दूसरा उद्योग लगने की संभावना बनी थी लेकिन किसी भी निवेशक ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। बांदा से महोबा रोड पर 150 हेक्टेयर क्षेत्र में भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों को लुभाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। इस औद्योगिक क्षेत्र में ई-रिक्शा, लोहे के दरवाजे, प्लास्टिक सामग्री आदि से जुड़े 16 कारखाने संचालित हो रहे हैं लेकिन यहां कई जरूरी सुविधाओं का अभाव है। ई-रिक्शा कारखाना संचालक समीर गुप्ता का कहना है कि भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, जलभराव और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं। प्रति वर्ष आठ हजार रुपए मेंटेनेंस चार्ज के रूप में लिए जाते हैं लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलता। औद्योगिक क्षेत्रों की बदहाली भी निवेश में बड़ी बाधा है। वैसे, फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले बांदा में उद्योग विभाग को 24 उद्यमियों से 180 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।

वर्ष 2017 में उप्र में सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास तेज करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। यह योगी के प्रयासों का नतीजा ही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी, 2018 को लखनऊ में आयोजित उप्र इन्वेस्टर्स समिट में उप्र को रक्षा उत्पादों का केंद्र बनाने और बुंदेलखंड के विकास को गति देने के लिए डिफेंस **कॉरिडोर परियोजना** की घोषणा की थी। परियोजना के छह नोड में से दो चित्रकूट और झांसी, बुंदेलखंड के ही जिले हैं। डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी उप्र एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) को चित्रकूट में 101 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जा चुकी है लेकिन इस पर उपक्रम लगाने के लिए किसी भी निवेशक ने रूचि नहीं दिखाई है। झांसी में आवंटित 195 हेक्टेयर जमीन में 183 हेक्टेयर केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन उपक्रम भारत डायनिमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को पट्टे पर दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है। बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के आंकड़ों का अध्ययन करने वाले कानपुर विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर राज बहादुर का कहना है कि एक्सप्रेसवे और अन्य आधारभूत ढांचा अपेक्षाकृत मजबूत होने के बावजूद बुंदेलखंड नोएडा जैसे किसी विकसित शहर से दूर है। एक विकसित एयरपोर्ट की सुविधा न होने से भी बुंदेलखंड बड़े निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

बुंदेलखंड की लगातार उपेक्षा

योगी सरकार ने मार्च, 2017 में सत्ता संभालने के एक साल के भीतर फरवरी, 2018 में लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसमें साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार, इनमें से तीन लाख करोड़ रुपए के एमओयू क्रियान्वित किए जा चुके हैं। दूसरी बार प्रदेश की सत्ता संभालने के 100 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी ने तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया था। इस सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की निवेश वाली जिन 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था उनमें बुंदेलखंड में स्थापित होने वाली परियोजनाओं की संख्या महज 34 है। अभी भी नोएडा, गाजियाबाद समेत उप्र के पश्चिमी जिले निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं। औद्योगिक विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी बुंदेलखंड में निवेश बढ़ने को लेकर बेहद आशान्वित हैं। गुप्ता कहते हैं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में होने वाले निवेश को राज्य की नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत 15 से 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इससे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश का माहौल बना है।

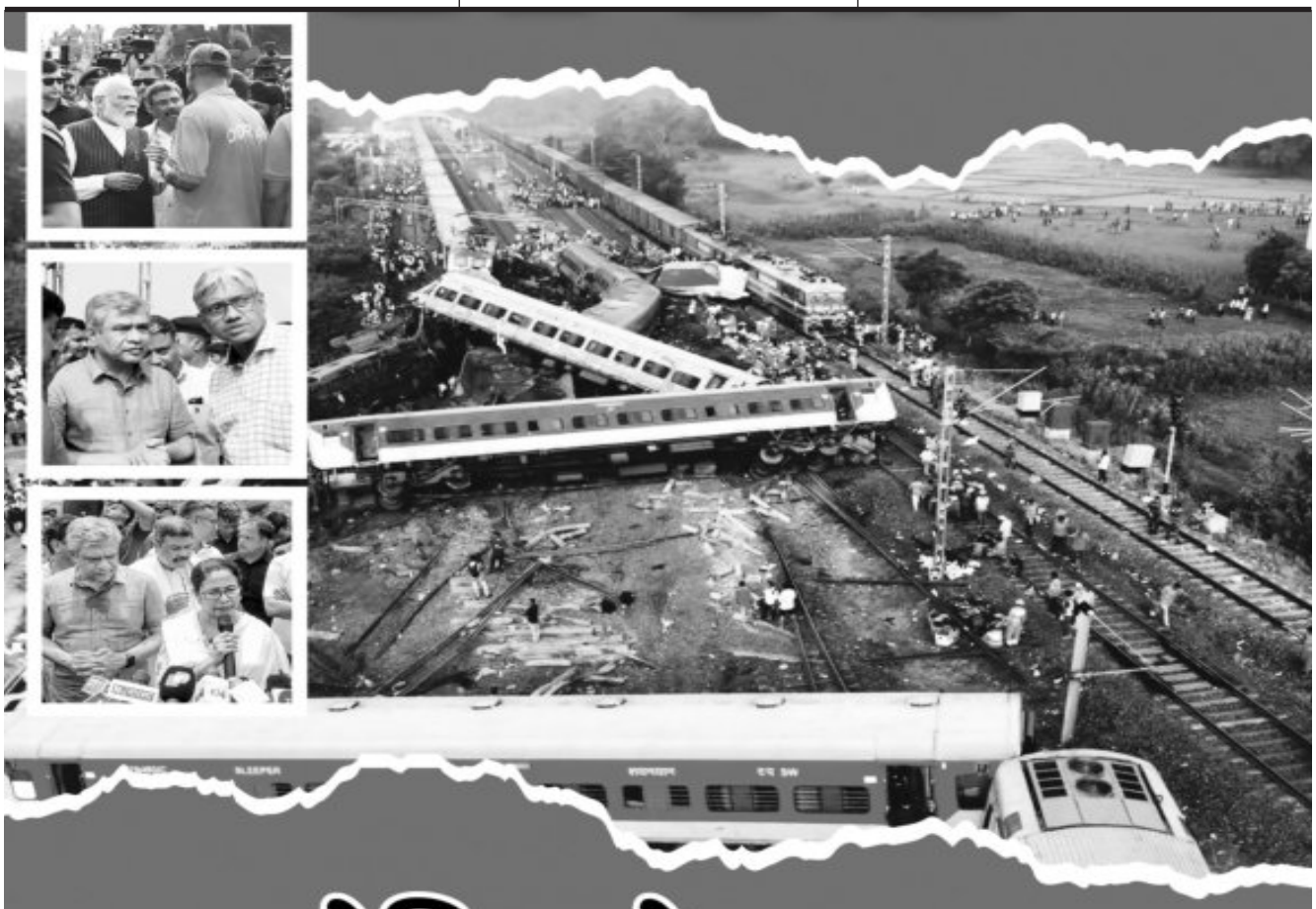

ओडिशा ट्रेन हादसा गड़बड़ी या साजिश ?

कहां है रेल हादसों को 'शून्य' करने का वादा और दावा करने वाले

लोको पायलट से लेकर रनिंग स्टाफ और ट्रैकमैन भारी दबाव में

भारतीय रेल इस विशाल देश की जीवनरेखा है। रोजाना ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने वाली यह रेल प्रणाली कितनी कमजोर है, इसका ताजा प्रमाण ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना है। इस दुर्घटना में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 289 लोगों की मौत हुई है जबकि कुछ एजेंसियों द्वारा 1000 से अधिक की मौत का दावा किया जा रहा है। यह हादसा रेलवे की गड़बड़ी है या किसी की साजिश इसकी जांच सीबीआई कर रही है।

● राजेंद्र आगाल

भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन यह भारतीय रेलवे का दुर्भाग्य ही है कि यह बीते कई साल से तमाम रेल मंत्रियों की प्रयोगशाला बन गया है। जितने मंत्री आते हैं उनमें कई अपने तरीके से नए प्रयोग करते हैं। 1950 के बाद से भारतीय रेलवे में यात्री और माल परिवहन 16 गुना बढ़ा है, जबकि रेल लाइनों का विस्तार 25 फीसदी से भी कम हुआ है। इसकी सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और समय-पालन, संरक्षा, गाड़ियों की क्षमता, यात्रियों की सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां खड़ी हैं। एनसीआरबी के अनुसार पिछले 10 वर्षों में ट्रेन हादसों में 2.6 लाख लोगों ने जान गंवाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज रेलवे में 3.20 लाख रिक्तियां हैं। सबसे अहम काम करने वाले लोको पायलट से लेकर रनिंग स्टाफ और ट्रैकमैन भारी दबाव में हैं। ऐसे में समय-पालन, संरक्षा, गाड़ियों की क्षमता, यात्रियों की सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां खड़ी हैं।

रोजाना ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने वाली यह रेल प्रणाली माल ढुलाई में भी एक दशक पहले अमेरिका, चीन और रूस के साथ एक अरब टन के विशिष्ट क्लब में शामिल हो चुकी है, लेकिन यह इसकी विशिष्टता है। जमीनी हकीकत यह है कि आज यह तमाम दबावों से जूझते हुए भारी वित्तीय तंगी से गुजर रही है। इसकी तमाम परिसंपत्तियों को बदलने के साथ यात्री और माल यातायात के बेहतर संचालन के लिए पहल करने की दरकार है। और सबसे बड़ी जरूरत है रेल यात्रा को सुरक्षित बनाना।

हादसे ने खोली सुरक्षा की पोल

वर्षों बाद 2 जून को हुई किसी बड़ी रेल दुर्घटना ने भारत को चौंका दिया। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन हादसा जहां एक ओर रेलवे के सुरक्षा दावों की पोल खोलता है वहीं दूसरी ओर इसके पीछे किसी अवांछित साजिश की संभावना भी जताई जाने लगी है। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से ट्रेन दुर्घटनाओं में काफी कमी देखी गई थी। जैसे आतंकवादियों के किए बम धमाकों की खबरें नहीं आतीं, वैसे ही ट्रेन दुर्घटनाओं की खबरें भी अब शायद ही सुनाई देती हैं। ऐसे में ओडिशा के बालासोर से आई ट्रेन दुर्घटना की खबर ने न केवल लोगों को परेशान कर दिया बल्कि पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है। ऐसा हादसा परेशान करने वाला तो है ही। रेल सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार में बहुत बुनियादी काम हुए हैं। कोच में एलएचबी तकनीक, ट्रैक मैनेजमेंट, सिग्नलिंग जैसे बुनियादी ढांचे में आमूलचूल बदलाव हुआ है। आए दिन होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हाल ही में (2022-23 से) ट्रेनों में कवच नामक सुरक्षा प्रणाली लगाना शुरू किया गया है। इसके पूरी तरह लागू होने के बाद ट्रेनों के एक-दूसरे से टकराने की संभावना नगण्य हो जाएगी। लेकिन इस बीच बालासोर की भयावह ट्रेन दुर्घटना ने हर सुरक्षा उपाय पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस दुर्घटना के पीछे कोई मानवीय चूक है, तकनीकी खामी या फिर कोई साजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन इस दुर्घटना में जो असमय जिंदगियां चली गई हैं उस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकेगा। 2004 में श्रीलंका के ट्रेन हादसे के बाद दो दशक में यह दुनिया का दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा है। यह भारतीय रेलवे के माथे पर ऐसा दाग है जिसे हटा पाना उसके लिए आसान नहीं होगा।

उधर, पूर्व रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी ने साजिश वाली बात पर शंका भी जाहिर कर दी है। दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि एक्सीडेंट के जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर लगता है जैसे कोई साजिश रची गई है। रेलवे की ओर से जो तात्कालिक जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें सिग्नल के साथ छेड़छाड़ और मेन लाइन में तोड़फोड़ की आशंका व्यक्त की गई है जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि क्या इस दुर्घटना के पीछे कोई साजिश थी?

कानपुर में 2016 में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। कानपुर के रेल हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। रेल हादसों में साजिश रचने के आरोप में एक शख्स शमशुल होदा को काठमांडू में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दुबई में बैठकर शमशुल होदा भारतीय ट्रेनों को निशाना बना रहा था। नेपाल और भारत के दबाव के बाद शमशुल होदा को दुबई से काठमांडू भेजा गया और वहां पहुंचने पर नेपाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ था जब नेपाल से गिरफ्तार बृज किशोर गिरी के फोन से एक ऑडियो क्लिप मिला। ऑडियो क्लिप में कानपुर रेल हादसे की साजिश की बातचीत थी। नेपाल पुलिस ने एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियों को ऑडियो क्लिप सौंप दिए। एनआईए ने इस मामले में तीन एफआईआर दर्ज की थी। शमशुल होदा को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में भी रेलवे की विभागीय जांच की तात्कालिक रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है कि सिग्नल और मेन लाइन के साथ छेड़छाड़ के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं। आगे जांच के बाद अगर पटरियां काटने या फिश प्लेट खोलकर दुर्घटना करवाए जाने की कोई साजिश मिले तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहरहाल इन बातों का सच जानने के लिए अभी कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी जब उच्चस्तरीय जांच की रिपोर्ट सामने आएगी।

देश की सबसे भयावह रेल दुर्घटनाओं में 2 जून की शाम ओडिशा के बालासोर में हुआ रेल हादसा जुड़ गया जिसमें 289 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 1175 लोग घायल हुए। तीन ट्रेनों के बीच हुई इस अनहोनी में दो यात्री गाड़ियां बेंगलूरू-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस शिकार बनीं। युद्धस्तर पर चले राहत और बचाव अभियान में स्थानीय लोगों से लेकर रेलवे, ओडिशा सरकार और अन्य प्रांत भी शामिल हुए। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक,

रेलवे सुरक्षा का पैसा फुट मसाजर और क्रॉकरी पर खर्च

नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2017 में रेलवे सुरक्षा को बेहतर करने के लिए जो विशेष फंड बनाया था उसका इस्तेमाल फुट मसाजर, क्रॉकरी, बिजली के उपकरण, फर्नीचर, विंटर जैकेट, कम्प्यूटर और स्वचलित सीढ़ियां खरीदने में किया गया था। इसके अलावा इस फंड से बागीचे बनाए गए और तिरंगा झंडा भी लगाया गया। दिसंबर 2022 में पेश की गई सीएजी की एक रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में 11,464 वाउचरों का दिसंबर 2017, मार्च 2019, सितंबर 2019 और जनवरी 2021 में औचक निरीक्षण किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा फंड के तहत 48.21 करोड़ रुपए के खर्च की गलत बुकिंग दिखाई गई है। रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से बनाए गए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष को सरकार ने साल 2017-18 के बजट में पेश किया था। उस वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए अगले पांच सालों के भीतर एक लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। सरकार इस फंड के लिए सीड कैपिटल देगी। इसके अलावा रेलवे अपने स्रोतों और राजस्व से भी बाकी संसाधन जुटाएगा। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 289 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद रेल सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

कवच लगाने के सारे दावे हवा-हवाई

एक और अहम तथ्य उभरा है कि कवच स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली यहां लागू होती तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी और सिग्नल की खराबी की स्थिति में भी लूप लाइन पर जाकर ट्रेन 400 मीटर पहले रुक जाती। कवच को लेकर रेल मंत्रालय रक्षात्मक है। 2022 में आम बजट के दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ऐलान किया था कि कवच तकनीक से रेलवे यात्री ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित बनाएगी। इस तकनीक को अमेरिका से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक की रेलवे को आपूर्ति करने की योजना है। उनका कहना था कि 2 हजार किमी रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय दक्षिण मध्य रेलवे के 1455 किमी पर कवच प्रणाली लागू है। दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मंडल पर भी 3,000 किमी में काम प्रगति पर है। रेल मंत्रालय ने हाल में संसदीय समिति को सूचित किया है कि भारतीय रेल के उच्च घनत्व वाले 35,000 किमी मार्ग पर कवच को मंजूरी दी गई है। बाद में चरणबद्ध तरीके से सारे रेलवे नेटवर्क को कवर किया जाएगा। जिस कवच की यहां चर्चा हो रही है, वह पीयूष गोयल के रेल मंत्री काल में ही परीक्षण के अधीन थी, लेकिन असली सवाल यह है कि ममता बनर्जी के रेल मंत्री काल में विकसित उस कवच का क्या हुआ, जिसे कोंकण रेलवे ने विकसित किया था।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमाम आला अधिकारी और नेता पहुंचे। दुर्घटना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप भी लगे। सरकार से सवाल पूछे जाने का क्रम जारी है। यह घटना जिस तरह से हुई और इसके जितने कोण हैं, उसमें रेलवे की लापरवाह सिग्नलिंग प्रणाली की खामी साफ तौर पर दिखती है। रेल संरक्षा आयोग ने जांच आरंभ कर दी है। इस बीच में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश का ऐलान कर घटना को नया मोड़ दे दिया है।

मंत्रियों की प्रयोगशाला

भारतीय रेल का दुर्भाग्य ही है कि यह बीते कई साल से तमाम रेल मंत्रियों की प्रयोगशाला बन गई है। जितने मंत्री आते हैं उनमें कई अपने तरीके से नए प्रयोग करते हैं। इन सबके बावजूद एनसीआरबी के अनुसार पिछले 10 वर्षों में ट्रेन हादसों में 2.6 लाख लोगों ने जान गंवाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज रेलवे में 3.20 लाख रिक्तियां हैं। सबसे अहम काम करने वाले लोको पायलट से लेकर रनिंग स्टाफ और ट्रैकमैन भारी दबाव में हैं। ऐसे में समय-पालन, संरक्षा, गाड़ियों की क्षमता, यात्रियों की सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां खड़ी हैं। 1950 के बाद से भारतीय रेल में यात्री और माल परिवहन 16 गुना बढ़ा है, जबकि रेल लाइनों का विस्तार 25 फीसदी से भी कम हुआ है। इसकी सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और समय-पालन, संरक्षा, गाड़ियों की क्षमता, यात्रियों की सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां खड़ी हैं। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना जहां एक ओर रेलवे के सुरक्षा दावों की पोल खोलता है वहीं दूसरी ओर इसके पीछे किसी अवांछित साजिश की संभावना भी जताई जाने लगी है। रेल दुर्घटनाओं में दोष चाहे नीति-निर्माताओं का हो मगर अमूमन लोको पायलट, गैंगमैन या ट्रैकमैन के मत्थे जिम्मेदारी मढ़कर भूल जाया जाता है। जरूरी है कि गहन पड़ताल के साथ पूरे तंत्र की कमजोरियों और कमियों की समीक्षा हो। बीते 15 साल में भारतीय रेल में 10 रेल मंत्री बदल गए, लेकिन रेलवे में

देश की बड़ी रेल दुर्घटनाएं

- **23 दिसंबर, 1964-** रामेश्वरम में चक्रवात में फंसी पंबन-धनुस्कोडि पैसेंजर ट्रेन। ट्रेन में सवार 126 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई।
- **6 जून, 1981-** देश की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बिहार में हुई। जिसमें पूरी ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी। जिसमें करीब 750 यात्रियों की मौत हुई थी।
- **20 अगस्त, 1995-** उप्र के फिरोजाबाद में खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस टकरा गई। इस दुर्घटना में 305 लोगों की मौत हुई थी।
- **26 नवंबर, 1998-** पंजाब के खन्ना में जम्मू तवी-सियालदह एक्सप्रेस, फ्रंटियर गोल्डन टेंपल मेल के पटरी से उतरे तीन डिब्बों से टकराई थी। जिसमें 212 की मौत हो गई थी।
- **2 अगस्त, 1999-** बिहार के कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल, अवध असम एक्सप्रेस से टकराई। इसमें करीब 285 लोगों की मौत हुई।
- **9 सितंबर, 2002-** हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस रफीगंज में धावे नदी पर एक पुल के ऊपर पटरी से उतर गई थी। इसमें 140 से अधिक की मौत हुई।
- **28 मई, 2010-** मुंबई जाने वाली जनेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। और एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। जिससे 148 यात्रियों की मृत्यु हुई।
- **7 जुलाई 2011-** उप्र के एटा जिले में छपरा-मथुरा एक्सप्रेस की एक बस से टक्कर हो गई थी। इसमें 69 लोगों की जान चली गई थी।
- **22 मई, 2012-** आंध्र प्रदेश में मालगाड़ी और हुबली-बैंगलोर हम्पी एक्सप्रेस टकरा गई। चार डिब्बे पटरी से उतरे। एक में आग लगने से 25 की मौत हो गई थी।
- **26 मई, 2014-** उप्र के संत कबीर नगर में खलीलाबाद स्टेशन के पास रुकी मालगाड़ी से गोरखधाम एक्सप्रेस टकरा गई थी। जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।
- **20 नवंबर,2016-** उप्र के कानपुर के पुखरायां में इंदौर-पटना एक्सप्रेस 19321 के 14 कोच पटरी से उतर गए थे। हादसे में 152 लोगों की मौत हुई और 260 घायल हो गए थे।
- **18 अगस्त, 2017-** उप्र के मुजफ्फरनगर में पुरी-हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी।
- **13 जनवरी, 2022-** पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार क्षेत्र में बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी।
- **2-3 जून, 2023-** ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी के टकराने से 233 लोगों की मौत हो गई।

हादसों की तस्वीर नहीं बदली है। रेल मंत्री से लेकर अधिकारी तक अक्सर हादसों को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। पिछले दो दशकों से रेलवे में हादसों को रोकने के लिए कई तकनीक पर विचार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी एक ऐसी तकनीक का इंतजार है जो रेलवे की तस्वीर बदल सके। मोदी सरकार में पहले रेल मंत्री बने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा लेकिन चंद महीनों में ही उनकी जगह यह पद 10 नवंबर 2014 को सुरेश प्रभु को दे दिया गया। अतीत में इस सीट पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, रामविलास पासवान, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता रहे। जॉन मथाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, ललित नारायण मिश्र और कमलापति त्रिपाठी, जॉर्ज फर्नांडीस, माधवराव सिंधिया और सीके जाफर शरीफ जैसे बड़ी कद-काठी के नेता रेल मंत्री थे। तमाम नए प्रयासों के बाद भी रेल मंत्री के तौर पर सुरेश प्रभु रेल बजट को समाप्त करने के साथ कुछ नई पहल करने में सफल तो रहे पर रेल दुर्घटनाओं के चलते उनको विदा होना पड़ा। मुजफ्फरनगर में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद वे संभल पाते कि इटावा में कैफियत एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। भारी आलोचनाओं के चलते प्रधानमंत्री ने पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एके मित्तल को तलब कर फटकार लगाई, बाद में उनको त्यागपत्र देना पड़ा और मंत्री सुरेश प्रभु की भी 3 सितंबर 2017 को विदाई हो गई। बाद में यह पद पीयूष गोयल को सौंपा गया जो 7 जुलाई 2021 तक इस पद पर रहे। इसके बाद से नौकरशाह से नेता बने अश्विनी वैष्णव के पास यह दायित्व है। वे पहले ऐसे रेल मंत्री हैं जिसके पास इतने विशाल महकमे के साथ संचार, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम मंत्रालय भी हैं।

कई सवाल हुए खड़े

बीती सदी में जबकि तकनीक कमजोर थी और संसाधनों की किल्लत थी तो भारतीय रेल की अलग स्थिति थी, लेकिन आज साधन संपन्नता और फुलप्रूफ तकनीक के इस दौर में ओडिशा में जैसा रेल हादसा हुआ है वह कई सवाल खड़े करता है। तीन गाड़ियों की जिस तरह की भिड़ंत हुई है विशेषज्ञ उसे सीधे तौर पर उपकरण की खराबी की वजह मानते हैं। बेशक ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और स्थानीय नागरिकों की सजगता के कारण राहत के कामों में समय रहते गति मिल गई, वरना हताहतों की संख्या और होती।

यह बात भी इस संदर्भ में प्रकाश में आ रही है कि जहां घटना हुई है, उस इलाके का सिग्नल ओवरएज हो गया था और स्थानीय यूनियनों ने इसे बदलने के लिए ज्ञापन भी दिया था। यह

ट्रेन हादसे के गुनहगार कौन?

तीन ट्रेन, दर्दनाक हादसा और 289 लोगों की मौत। ओडिशा के बालासोर में हुई दुर्घटना ने पूरे देश को झंकझोर कर रख दिया है। सैकड़ों परिवारों ने अपने रिश्तेदारों को इस हादसे में खोया है। मौत से ज्यादा आंकड़ा घायलों का है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस भीषण दुर्घटना के बाद अब कई ऐसे सवाल हैं, जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। जैसे आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। इसकी जांच जब सीबीआई कर रही है तो फिर जांच एजेंसी के रडार पर आखिर कौन-कौन है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जांच को अपने हाथ में लेने के बाद आखिर सीबीआई किस दिशा में आगे बढ़ेगी। सीबीआई की टीम ने गत दिनों दो बार बालासोर में घटना स्थल और बहनागा रेलवे स्टेशन पहुंचकर जांच की। टीम ने मेन लाइन और लूप लाइन दोनों की जांच की। सीबीआई के अधिकारी इस दौरान सिग्नल रूम भी गए। टीम के साथ रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे। टीम का पूरा फोकस हादसे के पीछे की वजह और गुनहगार की पड़ताल करने पर है। इस सिलसिले में टीम रेलवे सुरक्षा एक्सपर्ट से भी विचार-विमर्श कर सकती है। जांच के लिए बनाई गई टीम का नेतृत्व सीबीआई के संयुक्त निदेशक (विशेष अपराध) विप्लव कुमार चौधरी कर रहे हैं। सीबीआई जल्द ही सहायक स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती और बहनागा स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही सिग्नल और ट्रैक की देखरेख करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। बता दें कि सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद जांच एजेंसी ने दोपहर 2.15 बजे एफआईआर दर्ज की थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक केस दर्ज करना सीबीआई का शुरुआती काम है।

जांच का विषय है कि वास्तविक स्थिति क्या थी जिसके कारण समस्या आई, पर रेलवे की अपनी आंतरिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 200 सिग्नल ओवरएज होते हैं और 100 बदले जाते हैं। वहीं हर 4500 किमी ट्रैक या रेलपथ हर साल बदले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बदलने का औसत 1500 किमी है। 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में रेलपथ नवीनीकरण के लिए लंबित काम 9090 किलोमीटर था, जिस पर 54.402 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। इस समय कुल बकाया काम करीब 15,000 किमी रेलपथ का है। 2023-24 में इस मद में आवंटन 1400 करोड़ रुपए रखा गया है। यह ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक नहीं है।

एक लाख करोड़ रुपए के समर्पित राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का सृजन सुरेश प्रभु के रेल मंत्री काल में हुए प्रयासों की देन था। इसका प्रमुख ध्यान रेलगाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरने और समपार दुर्घटनाओं को रोकना था, जो भारतीय रेल के 90 फीसदी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इस कोष से यातायात सुविधाएं, चल स्टॉक, समपार, रेल पथ नवीनीकरण, पुल और सिग्नलिंग जैसे कई ऐसे कामों पर व्यय होता है जो सीधे सुरक्षा संरक्षा से जुड़ा है। इस पर सालाना 20,000 करोड़ रुपए व्यय होना था लेकिन 2021-22 को छोड़कर यह निधि किसी साल पूरा खर्च नहीं हुई। कोरोना के समय 2020-21 में अधिक तेजी से तमाम काम हो सकते थे, तब 315 करोड़ रुपए से भी कम व्यय हुआ। चालू और पिछले साल का आवंटन ही 11000 करोड़ रुपए रहा। फिर भी रेल संबंधी संसदीय स्थाई समिति का आंकलन है कि 2017-18 में इस कोष की स्थापना के बाद से रेल दुर्घटनाओं और होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आई है, पर अब भी सबसे

अधिक दुर्घटना ट्रेन के पटरी से उतरने की हो रही है। एक और अहम मुद्दा भारतीय रेल में कर्मचारियों की रिक्तियों से भी जुड़ा है। आज रेलवे में 3.20 लाख रिक्तियां हैं और संरक्षा श्रेणी में सबसे अहम काम करने वाले लोको पायलट से लेकर रनिंग स्टाफ और ट्रैकमैन सभी भारी दबाव में हैं। 1990 में चार लाख ट्रैकमैन भारतीय रेल के पास थे जिनकी संख्या आधी हो चुकी है। ठेके पर श्रमिकों को रखकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है।

जानवरों की तरह ठुंसे रहते हैं यात्री

1840 के दशक में जब भारत में पहली बार रेलवे की योजना बनाई गई, तो इसका मुख्य उद्देश्य माल और पशुओं की ढुलाई था। ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल व्यापारिक एकाधिकार की एक व्यवस्था थी, जिसने ब्रिटिश ताज के अधीन रहते हुए धीरे-धीरे भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा और उस पर शासन किया। कंपनी के निदेशकों को भारतीयों में रेल यात्री बनने की संभावना नहीं दिखती थी। जबकि अनेक लोग न सिर्फ भारतीयों के गतिहीन होने के ब्रिटिश तर्क से असहमत थे, बल्कि अपने समर्थन में वे समुद्री रास्तों से भारतीयों के व्यापार के समृद्ध इतिहास की याद दिलाते थे। इसके बावजूद ब्रिटिश कालीन रेलवे नीति इस औपनिवेशिक सोच पर आधारित थी कि भारत के लोग गरीबी-तंगहाली से ग्रस्त, छोटे-छोटे गांवों में अलग-थलग रहने वाले और धार्मिक रूढ़ियों से घिरे हैं और यात्राएं करने में सक्षम नहीं हैं। यह विचार हालांकि उस औपनिवेशिक सोच से गुंथा था कि रेल नेटवर्क से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। रेलवे के विकास का विचार औपनिवेशिक व्यापारिक आधिपत्य की व्यवहारिक जरूरतों से भी जुड़ा था, जो अंग्रेजी उद्योगों के लिए जरूरी कपास जैसे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए आवश्यक थीं। भारत के अंदरूनी क्षेत्रों से कच्चे माल को बंदरगाह वाले शहरों तक तेजी व कुशलता के साथ पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था जरूरी थी। तृतीय श्रेणी के कूपों का किराया कम रख भारतीयों को ललचाने की कोशिश की गई, जो बेशक पूंजीवादी उद्यम के लाभ कमाने के उद्देश्य के उलट थी। पर ब्रिटिश पूंजीपतियों व अंशधारकों को रेलवे से लाभ की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार ने भारतीय करदाताओं की कीमत पर इन कंपनियों को अपने निवेश पर पांच फीसदी वार्षिक रिटर्न देना सुनिश्चित किया था।

आज भारतीय रेल कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, जिस तरफ सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय रेल 13,523 यात्री और 9146 माल गाड़ियों का संचालन रोज करती है, पर यात्री गाड़ियों की औसत रफ्तार 50.6 और माल गाड़ियों की 24 किमी प्रतिघंटा है। रेलवे नेटवर्क के तहत वर्गीकृत उच्च मांग वाले कॉरिडोरों में पहली श्रेणी हाईडेंसिटी नेटवर्क भारतीय रेल नेटवर्क का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा (11 हजार किमी रेलमार्ग) है लेकिन यह करीब 41 प्रतिशत माल परिवहन करता है। वहीं 11 अतिव्यस्त मार्ग (24230 किमी) भारतीय रेल नेटवर्क का करीब 35 प्रतिशत हैं, जो 40 फीसदी यात्री परिवहन करता है। ये दोनों भारतीय रेल नेटवर्क 50 प्रतिशत या 34,214 किमी बनते हैं। ये रेलवे का 80 प्रतिशत बोझ संभालते हैं लेकिन इनकी 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग हो रही है। इसके आंकलन में यह पाया गया कि 25 प्रतिशत नेटवर्क की 100 से 150 प्रतिशत क्षमता उपयोग हो रही है जबकि एक प्रतिशत ऐसा है जो क्षमता का डेढ़ गुना से अधिक उपयोग कर रहा है। उच्च घनत्व वाले नेटवर्क का 22 प्रतिशत हिस्सा 150 प्रतिशत से अधिक उपयोग में आ रहा है, जबकि 58 प्रतिशत 100 से 150 प्रतिशत क्षमता उपयोग कर रहा है।

संरक्षा, सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर भारतीय रेल को ध्यान देने की दरकार है और भारत सरकार को आधुनिकीकरण के लिए भारी रकम देने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। निजी निवेश से वह राह नहीं निकलेगी। अगर रेलवे को 160 किमी या अधिक गति की गाड़ियां चलानी हैं तो 9000 से 12,000 हार्सपावर के बिजली इंजनों की जरूरत है जिसमें काफी रकम लगेगी। अन्य तैयारियों और तकनीक पर धन व्यय करना होगा। यात्री परिवहन आम मुसाफिरों लायक बने और सुरक्षित हो, जिस पर काफी निवेश चाहिए। सरकारी विभागों में भारतीय रेल के कर्मचारी विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे बेहद मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ हैं। वे सुदूर इलाकों, खतरनाक घने जंगलों, तपते रेगिस्तान में 24 घंटे सेवाएं देते हैं। जब देश सो रहा होता है तो भी वे काम कर रहे होते हैं। लोग सुरक्षित सफर करें इसके लिए हर साल 400 से 500 गैंगमैन शहीद हो जाते हैं। रेल दुर्घटनाओं में दोष नीति निर्माताओं का होता है तो लोको पायलट, गैंगमैन या ट्रैकमैन को निशाना बना दिया जाता है। इस नाते जरूरी है कि इस रेल दुर्घटना की गहन पड़ताल के साथ पूरे तंत्र की कमजोरियों और कमियों की समीक्षा हो और वह रास्ता निकाला जाए, जिससे ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर दोबारा देखने को न मिले।

पटरी के पास से अवैध घुसपैठिए हटाए जाएं

ओडिशा रेल हादसे पर देश के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नौकरशाहों, सैन्य अधिकारियों और नागरिक समाज के अन्य सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। नागरिक समाज के इन सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि रेल पटरी के आसपास अवैध निर्माण, अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों को हटाया जाए और रेलवे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। पत्र पर कुल मिलाकर 270 लोगों ने साइन किया है और इन्होंने इसमें देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। पत्र में लिखा है, ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण दुर्घटना से हम बहुत परेशान हैं, जिसमें हमारा तेजी से बढ़ता और आधुनिक होता रेलवे प्रभावित हुआ है। हालांकि, जांच अभी भी चल रही है, लेकिन प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा शक है कि ट्रेन के पटरी से उतरने का कारण मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है, जो आतंकवादी संगठनों के इशारे पर साजिश का एक स्पष्ट मामला जान पड़ता है। पत्र में कहा गया है कि हस्ताक्षर करने वालों में से कुछ ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में काम किया है, जहां उन्हें रेलवे नेटवर्क के सुचारू संचालन में तोड़फोड़ की स्थितियों का सामना करना पड़ा। पत्र में कहा गया है, जम्मू-कश्मीर ने 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन पर कई हमले देखे, जहां पटरियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया।

चुनाव लोकप्रियता का इम्तिहान

कहते हैं किसी नेता के सियासी कैरियर में टिकट कट जाने से ज्यादा बड़ा ग्रहण तब लगता है जब चुनाव हार चुके उम्मीदवार पर पार्टी एक बार फिर दांव खेले और पार्टी को निराशा ही हाथ लगे। कहानी यहीं नहीं रुकती। पार्टी दो बार हार चुके उम्मीदवार को फिर मौका देने का सोचती है और इस बार भी पार्टी को निराशा ही हाथ लगती है। मतलब 2008 में विधानसभा चुनाव और दो लोकसभा चुनाव हार उसके खाते में जुड़ जाते हैं। फिर भी, पार्टी हारे हुए नेता के नेतृत्व में ही 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने का सोचती है। इस बार नेता पार्टी के अरमानों पर खरा उतरता है और पार्टी उसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप देती है। इसे किस्मत कहें या कुछ और? ऐसी ही किस्मत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी है, जो हार पर हार के बावजूद अपनी बाजी पलटने में सफल रहे। कई राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि अगर भूपेश ने हार के सामने घुटने टेक दिए होते तो आज वे मुख्यमंत्री नहीं होते। आज भूपेश देश में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एकाधिक बार हारने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं और पांच महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह पारिवारिक पृष्ठभूमि है।

राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में 2018 में शपथ लेते ही उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करके अपनी पारी की शुरुआत की। उनकी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की शृंखला और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जैसी नवाचारी पहल से लोगों को आसानी से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया। बेरोजगारों को प्रतिमाह भत्ता मिलना प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों की भी चिंता करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि कर उनका मान बढ़ाया है। श्रमिकों का मान बढ़ाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तथा स्थायी विकलांगता की स्थिति में उन्हें देय राशि 50 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने की घोषणा की। साथ ही अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।

जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ का चुनावी माहौल दक्षिण या पश्चिम के राज्यों से बिलकुल ही अलग है। यहां के लोग तो उस राजनीतिक दल और उम्मीदवार पर अपना स्नेह बिखेरने को तैयार रहते हैं जो सुख-दुख में उनका साथ देता है। आज भूपेश सत्ता में हैं और भारतीय जनता पार्टी बघेल सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। भाजपा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। भाजपा ने वादा किया है कि यदि वह विधानसभा चुनाव में विजयी होती है और सरकार बना लेती है, तो उपद्रवी तत्वों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर कार्रवाई को अमल में लाएगी। मतदाताओं ने भी भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों को देख लिया है, इसलिए इस बार वे बहुत सोच-समझकर अपना मत देंगे। फिलहाल, भूपेश बघेल के सियासी कद का कोई नेता राज्य में नहीं है। उस पर से उन्हें अपनी शुरू की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। 'कका' बघेल फिलहाल लोगों का आशीर्वाद लेने उनके बीच पहुंच चुके हैं, इंतजार चुनाव की तारीख का है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के 71 विधायक हैं। इन सभी विधायकों को 2023 में रिपीट करना, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हर विधानसभा में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार ही जीतने वाली प्रत्याशियों पर ही दांव लगा सकती है। छत्तीसगढ़ में 29 विधानसभा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। इसमें से कांग्रेस के पास 27 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आरक्षण विवाद से आदिवासी कांग्रेस सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसका प्रभाव कांग्रेस पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। क्योंकि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज ने खुद का प्रत्याशी खड़ा किया था और चुनावी रिजल्ट में कांग्रेस-भाजपा के बाद तीसरे पायदान पर सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी था। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी पार्टी को नुकसान कर सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का धड़ा सरकार से लगातार नाराज चल रहा है। सिंहदेव ने चुनाव के ठीक पहले अपनी नाराजगी जताते हुए और सरकार में ठीक से काम नहीं कर पाने की वजह बताते हुए ग्रामीण और पंचायत विकास विभाग के पद से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब 2023 विधानसभा चुनाव में 2018 से चल रहे टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच कुर्सी की लड़ाई खत्म नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

त्रिकोणीय मुकाबले के आसार

छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में फोकस बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए ग्राउंड पर उतर रही है। इसके अलावा पिछले महीने अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की मानें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सक्रियता से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 महीने से चल रहे ईडी अपनी कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के घर तक पहुंची है। इसे लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर कोयले के कारोबार में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। वहीं ईडी की रेड विधानसभा चुनाव के नजदीक आते-आते लगातार बढ़ रही है। इसका चुनावी असर भी हो सकता है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस मिशन 2024 को लेकर पूरी तरह उत्साहित है। कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि इस साल के आखिर में होने वाले पांच विधानसभाओं के चुनावों में से हिंदी पट्टी के तीन राज्य जीतने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनावों में विपक्ष का नेतृत्व करने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए पार्टी ने मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए विशेष रणनीति बनाई है। मप्र को छोड़कर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है।

मिशन 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस

दिल्ली में कांग्रेस की मंथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के सामने इस समय तीन बड़े मुद्दे हैं, जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। पहला- विपक्षी एकता के टेढ़े सवालों को सुलझाना। दूसरा- केजरीवाल को विपक्षी एकता में शामिल करने या नहीं करने पर फैसला लेना। तीसरा- राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद का हल निकालना। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि अगर पार्टी के अंदरूनी विवाद सुलझा लिए जाएं, तो लोकसभा चुनाव आते-आते वह हिंदी पट्टी में भी अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर लेगी।

कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक की चुनावी रणनीति बनाने वाले सुनील कानुगोलू को 2024 के लोकसभा तक सभी चुनावों की रणनीतिक जिम्मेदारी दे दी है। प्रशांत किशोर की टीम का हिस्सा रहे सुनील को कांग्रेस का प्रशांत किशोर भी कहा जाने लगा है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले के रहने वाले सुनील की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी अहम भूमिका रही थी।

कर्नाटक में भाजपा के खिलाफ 40 पर्सेंट वाली सरकार, पेटीएम, क्यूआर कोड जैसे कैंपेन सुनील की रणनीति का हिस्सा थे। भाजपा ने कर्नाटक की तरह मप्र में भी कांग्रेस तोड़कर अपनी सरकार बनाई थी, इसलिए सुनील को मप्र में चुनावी रणनीति का काम सौंप दिया गया है, वह मप्र पहुंच चुके हैं, और उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि इस साल के आखिर में होने वाले पांच विधानसभाओं के चुनावों में से हिंदी पट्टी के तीन राज्य जीतने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनावों में विपक्ष का नेतृत्व करने की स्थिति में आ जाएगी, जो कर्नाटक से पहले तक उसे खुद को संभव नहीं लगता था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव में नेतृत्व का दावा लगभग छोड़ने की पेशकश कर दी थी। उसके बाद ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को विपक्षी एकता की कमान संभालने का जिम्मा दिया था। नीतीश कुमार की कोशिशें कितनी सफल हुई हैं, उसका कुछ अंदाजा पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पता चल जाएगा। यह बैठक कांग्रेस की रणनीति से ही हो रही है। जिसमें वे दल भी शामिल होंगे, जो फिलहाल कांग्रेस से सहमत नहीं हैं। कांग्रेस ने 29 मई को आगामी रणनीति के लिए दिनभर बैठकें कीं। जिनमें सबसे अहम बैठक राजस्थान की गुटबाजी और केजरीवाल को लेकर कांग्रेस में उठे बवंडर का समाधान निकालने वाली बैठकें प्रमुख थीं।

राजस्थान में गुटबाजी

कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट राजस्थान की गुटबाजी है। कई बार की कोशिशों के बाद आखिर 29 मई की रात को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आमने-सामने बिठाया। केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे। चार घंटे की तू-तू, मैं-मैं के बाद सिर्फ इतना कहा गया कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ इतना बयान गहलोत और सचिन पायलट की कड़वाहट खत्म होने का प्रमाण नहीं हो सकता। गहलोत किसी भी हालत में सचिन पायलट को संगठन या सरकार में समाहित करने को तैयार नहीं हैं। अगर गहलोत को मजबूरी में किसी बात पर सहमत होना भी पड़ता है, तो कांग्रेस में एक-दूसरे को पटखनी देने की पुरानी परंपरा है।

मप्र को लेकर भी अहम रणनीतिक बैठक हुई। जहां तक राष्ट्रव्यापी विपक्षी एकता का सवाल है, तो कांग्रेस अगर आगामी बैठक से पहले केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला करती है, तो विपक्षी एकता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस केजरीवाल का विरोध करती है तो विपक्षी एकता की संभावनाएं धूमल हो जाएंगी। ऐसी सूरत में केजरीवाल, ममता, केसीआर का तीसरा मोर्चा बनेगा।

केजरीवाल को लेकर कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ पंजाब, दिल्ली और गुजरात प्रदेश कांग्रेस ईकाइयों का विरोध ही नहीं है। बल्कि मुश्किल यह भी है कि अगर केजरीवाल राष्ट्रव्यापी एकता में शामिल होते हैं, तो वे इन राज्यों में तो कांग्रेस से लोकसभा सीटों में हिस्सा मांगेंगे ही, बाकी राज्यों में भी हिस्सा मांगेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने

29 मई को पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से केजरीवाल के मुद्दे पर अलग-अलग बात की। इन दोनों ही बैठकों में राज्यों के नेताओं ने विपक्षी एकता के नाम पर केजरीवाल को समर्थन करने का कड़ा विरोध किया। अजय माकन ने अपने पक्ष को बहुत ही जोरदार ढंग से रखते हुए दिल्ली विधानसभा में पास किए उस प्रस्ताव का जिक्र किया, जिसमें राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कि 2013 में कांग्रेस ने समर्थन देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी, उसने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी कि वह 2013 वाली गलती दोहराने का काम नहीं करे। अब ऐसा लग रहा है कि जुलाई में होने वाले संसद सत्र तक कांग्रेस कोई स्टैंड नहीं लेगी।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौंसले बुलंद हैं, और केजरीवाल के साथ किसी तरह का तालमेल बिठाकर पार्टी हाईकमान बनी हुई फिजा खराब नहीं करना चाहती। वैसे भी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस से समर्थन के बाद अध्यादेश पर आधारित सरकारी बिल आसानी से पास होने वाला है, इसलिए हो सकता है कि बिल के मतविभाजन के समय विपक्ष की वाकआउट करने की ही रणनीति बने। कांग्रेस इस स्थिति को इस साल के आखिर में होने वाले पांच विधानसभाओं के चुनाव नतीजों तक बनाकर रखना चाहेगी। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक के बाद हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में उसकी सरकार बन जाएगी। हिंदी पट्टी के जिन तीन राज्यों में इसी साल के आखिर में चुनाव हैं, इनमें से दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस की सरकार है, जबकि दलबदल के कारण वह मप्र की जीती हुई बाजी हार गई थी।

मप्र की चुनावी रणनीतिक बैठक के बाद राहुल गांधी ने घोषणा की कि कांग्रेस मप्र में 150 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उनके इतने आत्मविश्वास का कारण यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए नेताओं के कारण भाजपा में असंतोष व्याप्त है, क्योंकि उन्हें भाजपा में शामिल होते ही सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई, जबकि भाजपा में लंबे समय तक काम करने वाले दरकिनार कर दिए गए। जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, उन सभी सीटों पर कांग्रेस ने कर्नाटक जैसी रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

जिस तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसी तरह कांग्रेस की निगाह भाजपा के नाराज नेताओं पर टिकी है। कई नेता शामिल हो गए हैं और अन्य कई नेताओं से बातचीत चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की नजर भाजपा के असंतुष्ट नेताओं पर है तो वहीं पार्टी के नेताओं को सक्रिय करने की हर संभव कोशिश हो रही है। दिग्विजय सिंह मिशन 66 पर लगे हुए हैं। ये 66 सीटें वे हैं जहां कांग्रेस लंबे अरसे से हार का सामना कर रही है। इसके लिए 16 नेताओं की एक टीम को काम पर लगाया है।

दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने व्यापक दौरे शुरू कर दिए हैं। गत दिनों हुई बैठक में उन कारणों पर चर्चा हुई, जिनके कारण कर्नाटक में कांग्रेस जीती। उन सभी कारणों को मप्र, राजस्थान में भी आजमाया जाएगा। जैसे सस्ती बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा, कर्जमाफी और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को 27 प्रतिशत आरक्षण जैसे मुद्दे। कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि चुनाव से दो महीने पहले अधिकांश उम्मीदवार घोषित कर देगी। इससे टिकट न मिलने पर जो नेता बगावत कर सकते हैं, उन्हें बिठाने या दावेदारी वापस लेने के लिए मनाने का भी पार्टी को पर्याप्त वक्त मिलेगा।

कांग्रेस हाईकमान ऐसा मानकर चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में उसकी जीत बहुत आसान है क्योंकि भाजपा ने 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को बिलकुल किनारे लगा दिया है, जबकि उनका कोई विकल्प खड़ा ही नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की कमजोरी यह भी है कि आदिवासी के नाम पर बने इस राज्य में उसके पास दमदार आदिवासी नेतृत्व ही नहीं है। मप्र के बंटवारे से पहले भी भाजपा यहां मजबूत स्थिति में नहीं थी, बंटवारे के बाद भाजपा में आए लगभग सभी कांग्रेसी नेता अपनी मूल पार्टी में लौट चुके हैं। अजीत जोगी के कांग्रेस छोड़ अलग पार्टी बनाने के कारण कांग्रेस के वोटों में विभाजन का फायदा भाजपा को होता रहा, लेकिन अजीत जोगी के देहांत के बाद तीसरी ताकत रही नहीं। आज भी अगर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में तीसरी ताकत के रूप में खड़ी हो जाए, तो भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर हो सकती है।

● **विपिन कंधारी**

मप्र कांग्रेस में भी गुटबाजी लेकिन औरों से कम

मप्र कांग्रेस में अर्जुन सिंह खेमा और शुक्ल बंधु खेमा एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर राजनीति करता था। दोनों कांग्रेस में रहते हुए भी अलग-अलग पार्टियों की तरह काम करते थे, एक बार प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ गोलियां तक चल गई थीं। अर्जुन सिंह के खिलाफ शुक्ल खेमे को नरसिंह राव का समर्थन था। नरसिंह राव के समय श्यामाचरण शुक्ल मप्र के मुख्यमंत्री और विद्याचरण शुक्ल केंद्र में मंत्री थे। नरसिंह राव से टकराव के कारण अर्जुन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर तिवारी कांग्रेस बना ली थी। उसी गुटबाजी का नतीजा निकला कि मप्र में कांग्रेस बीच के एक साल को छोड़कर 20 साल से सत्ता से बाहर है। मप्र के बंटवारे के बाद शुक्ल खेमा छत्तीसगढ़ चला गया, वहां भी शुक्ल खेमे ने अर्जुन सिंह खेमे के अजीत जोगी से मात खाई। श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल के देहांत के बाद शुक्ल खेमा समाप्त हो गया। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजीत जोगी तीनों अर्जुन खेमे में थे। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे अर्जुन सिंह और शुक्ल खेमे की तरह आमने-सामने खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों खेमों में अभी तक गोलियां नहीं चलीं। सचिन पायलट यह ठान कर बैठे हैं कि अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री किसी भी हालत में नहीं बनने देना है, जबकि अशोक गहलोत यह ठान चुके हैं कि वह सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। यह स्थिति भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकती है।

पदयात्रा की पॉलिटिक्स

देश की राजनीति में यात्राएं निकालकर चुनावी माहौल बनाना और चुनाव जीतना बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन वर्तमान में देश की राजनीति में 3 युवाओं की पदयात्रा काफी चर्चा में रही है। पहली पदयात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली। इस यात्रा ने राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी यात्रा प्रशांत किशोर की है और तीसरी यात्रा सचिन पायलट की।

भारत में लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बाकी है। ऐसे में देश का राजनीतिक पारा हर दिन थोड़ा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बाद विपक्षी एकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले गठबंधन बनाए जाने की कवायद फिर से तेज हो गई है। इस बार इसकी पहल और केंद्रीय भूमिका में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार सक्रिय हैं और तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस इस बार कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है, और सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने और प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव बाद चर्चा करने के लिए भी मन बना चुकी है। इन सबके बीच पिछले एक साल में देश के तीन युवा नेताओं की पदयात्रा भी चर्चा के केंद्र में रही है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इन पदयात्राओं का क्या असर होगा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 के बीच भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 4800 किमी लंबी पदयात्रा की। उनकी पदयात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई और 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर खत्म हुई। मीडिया में उनकी यात्रा की खूब चर्चा हुई। कहा गया कि राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से अपनी छवि बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वे खुद को एक गंभीर राजनेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अमूमन हर दिन राहुल गांधी के साथ हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल चल रहे थे। बीच-बीच में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, पूर्व रॉ चीफ एएस दौलत जैसे नामचीन लोगों ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल के साथ चले। राहुल गांधी ने इस यात्रा को नफरत के खिलाफ बताया और कहा कि वे मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। श्रीनगर में बर्फबारी के बीच उनका भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस यात्रा का राजनीतिक लाभ मिलेगा। यात्रा खत्म होने के बाद राहुल अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं और हो सकता है कि वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव भी लड़ नहीं पाएं। कर्नाटक में मिली जीत को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता बता रही है। लेकिन कर्नाटक की जीत के कई अन्य कारण भी रहे, जैसे कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव का होना, भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और

2024 के मुकाबले का मैदान खुला है

कर्नाटक के चुनाव से निकलता एक संदेश ये था कि साल 2024 में मुकाबले का मैदान अभी खुला हुआ है, किसी की हार-जीत को अभी से तयशुदा मानकर नहीं चल सकते। और, इस संदेश की अब पुष्टी भी हो चली है। अब तयशुदा तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सत्तासीन भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। जो कोई भारतीय गणतंत्र के मूल्यों में विश्वास करता है उसके लिए यह एक अच्छी खबर है। साथ ही, ये भी सच है कि ये लड़ाई कतई आसान नहीं होने जा रही। भारत के गणतंत्र पर फिर से अपना दावा जताने के लिए जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा। साल 2024 की लड़ाई के बुनियादी व्याकरण को बताना मुश्किल नहीं। भाजपा की ताकत और कमजोरी, पार्टी के आगे मौजूद अवसर और खतरे (इसे अंग्रेजी में एसडब्ल्यूओटी यानी स्ट्रेन्थ, वीकनेस, ऑपर्च्युनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस कहा जाता है) से जुड़े पूरे विश्लेषण के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

सशक्त मुख्यमंत्री का नहीं होना।

भारत जोड़ो यात्रा की असली परीक्षा इस साल के अंत में होने वाले मप्र और राजस्थान के चुनावों में होगी। मप्र में 2018 के चुनाव में सत्ता हाथ में आने के बाद पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के कारण सत्ता गंवा चुकी है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और अपनी ही पार्टी के महत्वपूर्ण नेता सचिन पायलट के बगावती तेवर से जूझ रही है। पायलट ने भी राजस्थान में हाल ही में एक पदयात्रा की है। राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद 2 अक्टूबर 2022 को बिहार के चंपारण से एक और पदयात्रा की शुरुआत होती है, जिसका नाम है जन सुराज पदयात्रा। देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले स्थित भितिहरवा गांधी आश्रम से राज्य भर की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने पिछले साल 5 मई को पटना में जन सुराज पदयात्रा की घोषणा करते हुए बताया था कि वे पूरे बिहार की लगभग 3500 किमी लंबी पदयात्रा करेंगे।

पदयात्रा के पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि ये एक समाज के बीच से सही लोगों को ढूंढकर उन्हें एक मंच पर लाकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। प्रशांत किशोर अपने भाषणों में बताते हैं कि पार्टी बनेगी लेकिन वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, प्रशांत किशोर उसके नेता नहीं होंगे। अगर सबकी सहमति से पार्टी बनती है तो वो बिहार के सभी सही लोगों की पार्टी होगी जो उसे मिलकर बनाएंगे और वही उस पार्टी के संस्थापक सदस्य होंगे। वे कहते हैं कि ये पूरा प्रयास आजादी से पहले वाली कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है।

जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर अब तक 7 जिलों की लगभग 2500 किमी लंबी पदयात्रा कर चुके हैं। फिलहाल उनकी पदयात्रा पैर चोटिल होने के कारण स्थगित हो गई थी, लेकिन 11 जून से उन्होंने फिर से पदयात्रा शुरू की और अब पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। प्रशांत किशोर की पदयात्रा बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में जन सुराज समर्थित एक निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार ने भाजपा और महागठबंधन दोनों के प्रत्याशी को हराकर राज्य की राजनीति में ठीकठाक हलचल पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी चिन्हित सीटों पर इसी प्रकार अपने द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को उतार सकते हैं। खासकर उन सीटों पर जहां उनकी पदयात्रा पूरी हो चुकी है। अगर पीके ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा और महागठबंधन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।

हालांकि, भाजपा और महागठबंधन के नेता पर प्रशांत किशोर अभी ज्यादा बोलने से बच रहे हैं और उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हाल के दिनों में पीके बिहार की राजनीति में चर्चा में बने हुए हैं और अपने भाषणों में वे कांग्रेस, मोदी, लालू और नीतीश सबको बिहार की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि क्या उनके प्रयास से बिहार में कोई नई राजनीतिक व्यवस्था बनेगी और सत्ता परिवर्तन में उनकी भूमिका होगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।

कांग्रेस के वोटशेयर में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

लोकनीति के नवीनतम सर्वेक्षण का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाऊ निष्कर्ष ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के वोटशेयर में 10 प्रतिशत अंकों की बढ़ोत्तरी हुई है। सर्वेक्षण के मुताबिक अगर साल 2023 के अप्रैल माह में चुनाव होते तो कांग्रेस को 29 प्रतिशत वोट मिलते यानी साल 2019 में पार्टी को मिले 19.5 प्रतिशत वोटों से कहीं ज्यादा। कांग्रेस की तरफ वोटों का यह घुमाव (लगभग 7 करोड़ वोटों का इजाफा) आश्चर्यजनक है और इतने वोटों की बढ़त कांग्रेस को उस जगह पर पहुंचाने के लिए काफी है जहां वह 2014 में हुए अपने नाटकीय पतन से पहले थी। अब इसमें पेंच ये है कि भाजपा के वोटों में इससे मेल खाता घुमाव नहीं हुआ है। लोकनीति के सर्वेक्षण के निष्कर्ष तो ये बताते हैं कि भाजपा का वोटशेयर 2019 के 37.4 फीसदी से बढ़कर 39 प्रतिशत पर जा पहुंचा है। लोकनीति की टोली ने कांग्रेस के वोटशेयर में बढ़त का कारण अन्य दलों खासकर क्षेत्रीय पार्टियों के वोटों में टूट को बताया है।

उधर, राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 11 मई से 15 मई के बीच 125 किमी लंबी जन संघर्ष यात्रा की। उनकी पदयात्रा अजमेर से शुरू हुई और 15 मई को जयपुर में एक बड़ी रैली में तब्दील होकर खत्म हुई। जयपुर में भीषण गर्मी के बावजूद जुटी खचाखच भीड़ से उत्साहित सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान सिविल सेवा आयोग का पारदर्शी तरीके से पुनर्गठन किया जाए और उसमें महत्वपूर्ण पदों पर विश्वसनीय अधिकारियों को बैठाया जाए, पेपर लीक से आर्थिक नुकसान झेलने वाले बच्चों को उचित मुआवजा मिले और वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच हो। जयपुर में पायलट के भाषण को सुनने पर लगता है कि कोई तेजतर्रार युवा नेता विपक्षी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, जबकि राजस्थान में उनकी ही पार्टी की सरकार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीतिक लड़ाई अब हेडलाइन से बाहर हो चुकी है। अब असली संकट कांग्रेस पार्टी के सामने है, राजस्थान में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि हर 5 साल पर सत्ता बदलती रही है। कांग्रेस के भीतर इस अंदरूनी लड़ाई का निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा। खबर ये भी है कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति बना चुके हैं और ये हाल ही में हुआ एक दिन का अनशन, 5 दिनों की पदयात्रा और उसके बाद प्रदेशभर में आंदोलन उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में तीन युवा नेताओं ने पिछले एक साल के दौरान पदयात्रा के माध्यम से अपने लिए राजनीतिक नब्ज टटोलने का काम किया है। इसमें से पदयात्रा का किसको कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले समय में चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये नेता सड़कों पर उतरकर आए और सीधा लोगों के बीच जाकर उनके साथ संवाद स्थापित किया। इससे बाकी नेताओं पर लोगों के बीच जाने का दबाव भी बढ़ेगा और चुने हुए नेताओं की जवाबदेही भी तय होगी। ऐसे प्रयासों से नेताओं को चुनावी फायदा मिलेगा या नहीं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र के लिए नेताओं का इतना लंबा समय जनता के बीच बिताना निश्चित तौर पर सकारात्मक प्रयास के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

● **इन्द्र कुमार**

शिवसेना बनाम शिवसेना

वरना आज उद्धव ठाकरे को टेक्निकली गद्दी मिल ही जाती... दरअसल सुप्रीम फैसला नहीं एक बार फिर सुप्रीम बैलेंसिंग एक्ट हुआ है। बता भर दिया राज्यपाल का निर्णय असंवैधानिक था, स्पीकर का फरमान अवैध था, लेकिन बजाय उद्धव ठाकरे को राहत देने के शिंदे सरकार को राहत दे दी। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक मोरल स्टोरी कहा जाना चाहिए। एक नहीं कई मोरल हैं राजनीतिज्ञों के लिए। परंतु राजनीति में मोरल हाई ग्राउंड लेने की बात भर ही होती है, लेता कोई नहीं। हां, कभी ऐसा हो जाता है कि एक अवसरवादी या गलत कदम को कालांतर में नैतिक कदम बताने की राजनीति की जाती है और वही पीड़ित पक्ष यानि उद्धव गुट कर भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के बाद उद्धव ने **मोरैलिटी कार्ड** खेलते हुए कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। लेकिन उनकी नैतिकता देखिए उन्होंने नैतिकता का पैमाना ही बदल दिया। जब इस्तीफा दिया था तब नैतिकता का पैमाना संख्या बल बताया था उन्होंने।

उस क्राइसिस में इस आत्मघाती कदम को उठाने के पहले उद्धव जी ने अपने सहयोगियों मसलन कांग्रेस और एनसीपी से चर्चा तक नहीं की थी, ऐसा स्वयं एनसीपी के पवार जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि उद्धव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। यानी इस्तीफा देना उद्धव की गलती थी। और शीर्ष अदालत ने भी उनके इस्तीफे को ही आधार बनाकर कहा कि चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अदालत उन्हें पुनर्स्थापित नहीं कर सकती। परंतु राजनेता की यूएसपी होती है इन्हें गलती का एहसास खूब होता है पर वे स्वीकार नहीं करते।

सो पोस्ट वर्डिक्ट भी उद्धव जी अपने नैतिकता वाले स्टैंड पर कायम रहे लेकिन पैमाना जरूर बदल दिया। उन्होंने हाई मोरल ग्राउंड लेते हुए कहा कि अपने ही साथियों की गद्दारी से वे इतने आहत हुए थे कि उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था कि जिन लोगों को उनके पिता ने, पार्टी ने सबकुछ दिया, वे ही अविश्वास ले आए। विडंबना देखिए जिस नैतिकता के आधार पर, पैमाना जो भी रहा हो, उद्धव ने इस्तीफा दिया, वही शीर्ष अदालत के लिए तकनीकी आधार बन गया शिंदे सरकार को बर्खास्त न करने का। और बेंच ने कहने से गुरेज भी नहीं किया कि यदि आपने इस्तीफा ना दिया होता तो हम आपको बहाल कर सकते थे भले ही आप ट्रस्ट वोट हार भी जाते तो! निर्णय का पोस्टमार्टम सरीखा खूब विश्लेषण हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो हर नेता, हर पत्रकार और हर सामाजिक कार्यकर्ता/एक्टिविस्ट संवैधानिक बेंच की न्यायमूर्तियों से भी ज्यादा नॉलेज रखता हो, तभी तो निर्णय के ग्रे एरिया की बात की जा रही है। और पॉलिटिकल क्लास से तो जब भी कोई कहता है निर्णय स्वागत योग्य है, न्यायालय का खूब सम्मान है, दिखावा ही करता है। लेकिन पांच न्यायमूर्तियों की संवैधानिक पीठ के फैसले पर एक सवाल तो जरूर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, महाराष्ट्र में सब गलत हुआ, फिर भी शिंदे सरकार क्यों चलती रहेगी? क्यों ना कहें इस गलत में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल रहा क्योंकि कोर्ट देख रहा था?

आज कहते हैं फ्लोर टेस्ट बुलाना इल्लीगल था, नए व्हिप की नियुक्ति गलत थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार क्यों किया था? बेचारे उद्धव जी दो-दो बार शरणागत हुए थे गुहार लगाते हुए! कुल मिलाकर इससे ज्यादा और क्या गलत हो सकता है कि एक गलत सरकार जनता पर शासन कर रही है? कम से कम शीर्ष न्यायालय वर्तमान सरकार का निलंबन करते हुए पुनः चुनाव कराए जाने का आदेश तो दे ही सकता था?

निर्णय पर दोनों ही पक्ष गदगद हैं, एक हार में भी नैतिक जीत का झुनझुना बजा रहा है और दूसरा लोकतंत्र की जीत बता रहा है। जबकि निर्णय सिर्फ और सिर्फ एकेडेमिक ही है क्योंकि प्रथम तो स्पीकर डिसक्वॉलिफिकेशन पर निर्णय टालेगा चूंकि सालभर ही तो टालना है और दूजे सात जजों की संवैधानिक बेंच बने, तब तक शिंदे सरकार बड़े आराम से टर्म पूरा कर ही लेगी। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं बाय डिफॉल्ट सरकार के लिए डिफंक्ट ऑर्डर! सो स्पष्ट हुआ निर्णय बतौर नजीर आगे काम जरूर आएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों से उद्धव गुट इसलिए खुश है कि उसे जनता को यह समझाना आसान होगा कि किस तरह महाविकास अघाड़ी सरकार को अवैध तरीके से गिराया गया। हां पता नहीं क्यों उद्धव जी के लिए पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी खूब गदगद थे, बावजूद इस तथ्य के कि भले ही शीर्ष न्यायालय ने उनके तमाम आर्ग्युमेंट्स से सहमति जता दी कि राज्यापाल ने गलत किया, स्पीकर ने गलत किया लेकिन उनकी उद्धव सरकार को बहाल करने की मुख्य प्रेयर को ही ठुकरा दिया। दरअसल सिंघवी अब वकील कम पॉलिटिशियन ज्यादा हैं।

● **बिन्दु माथुर**

जितने जिम्मेदार राज्यपाल हैं... उतने ही सुप्रीम कोर्ट के जज भी!

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार और उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है और ऐसी तमाम बातें की हैं जो भले ही सरकार न बन पाई हो लेकिन उद्धव को राहत देती हुई नजर आ रही हैं। पांच जजों की संविधान पीठ ने सारा ठीकरा तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोशियारी के सिर फोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का फैसला गलत था, और अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता, तो उन्हें राहत दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उद्धव सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, और फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था, इसलिए उनके इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकते। सवाल ये है कि तब अगर उद्धव की सरकार गिरी तो क्या इसके एकमात्र जिम्मेदार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ही थे? जवाब है नहीं। मामले में दोषी सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं।

लड़ाई का अंजाम क्या होगा?

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ने सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि दोनों के बीच कोई समस्या नहीं है, लगभग उतनी ही बार, जितनी बार उन्होंने एक-दूसरे को निशाना बनाया है। पिछले इतिहास को खंगाला जाए तो 200 सदस्यीय सदन में 21 सीटों पर सिमट जाने के बाद से पार्टी को विधानसभा की जीत तक ले जाने के बाद, दिसंबर 2018 के चुनावों के बाद पायलट को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गहलोत गांधी परिवार के विश्वास को अपने पक्ष में कैसे झुकाने में कामयाब रहे, इसके बारे में कई कहानियां हैं, जिनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं की जा सकी है। लेकिन जब से गहलोत के डिप्टी के रूप में पायलट ने शपथ ली, उसके एक साल बाद तक, उन्होंने राज्य की राजनीति में खुद को कभी भी कम महत्वपूर्ण नहीं माना और अपने सार्वजनिक बयानों से सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राजभवन में जब गहलोत के मंत्रिमंडल ने शपथ ली तो परंपरा से हटकर मंच पर पायलट के लिए भी एक कुर्सी रखी गई। आमतौर पर केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री ही इस स्थान पर बैठते हैं। गहलोत और पायलट दोनों ने कई मौकों पर एक-दूसरे का नाम लिए बिना एक-दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां की हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पार्टी सभी 25 सीटें हार गई। पायलट ने कहा कि अकेले जोधपुर में ज्यादा समय बिताने के बजाय यदि मुख्यमंत्री पूरे राज्य में प्रचार करते तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। अन्य सभी अवसरों पर, जब गहलोत जोर देने के लिए कुछ कहते हैं कि राज्य के लोग और पार्टी के सभी विधायक उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जैसे कि इसे रगड़ने के लिए, पायलट समान रूप से प्रतिकार करते हैं।

पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जयपुर के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली में फोटो-ऑप को कौन भूल सकता है जब पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने दोनों नेताओं को एक-दूसरे को गले लगाया था? हाल ही में, कोटा के एक सरकारी अस्पताल में 100 से अधिक शिशुओं की मृत्यु के बाद, पायलट ने अपनी ही सरकार को गिराने में कोई समय नहीं गंवाया, यह कहते हुए कि सरकार को संकट से निपटने में अधिक मानवीय होना चाहिए था, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के उस बयान का जिक्र था जिसमें उन्होंने मौतों की बात कही थी, होता है। पायलट, जो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के कोटा जाने के एक दिन बाद अस्पताल गए थे, को अपने तत्काल प्रेसर के साथ राष्ट्रीय टीवी पर प्राइमटाइम एयर-टाइम मिला।

गहलोत-पायलट में सुलह के फॉर्मूले

वैसे सुलह के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन तीनों में पेंच हैं। कांग्रेस हाईकमान के पास पहला फॉर्मूला सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का है। राहुल गांधी के किए वादे को पूरा करते हुए पायलट को चुनावी साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर विवाद को शांत किया जा सकता है। हालांकि, सितंबर की घटना के बाद गहलोत से मुख्यमंत्री कुर्सी छिनना आसान नहीं है। गहलोत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और किसी सूरत में उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। चूंकि अधिकांश विधायक भी गहलोत के साथ खड़े हैं। ऐसे में हाईकमान मुख्यमंत्री पद पायलट को देने की बात कर राजस्थान में और किरकिरी नहीं करवाना चाहेगा। सचिन पायलट को साथ रखने के लिए हाईकमान के पास दूसरा बड़ा विकल्प पायलट के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने का हो सकता है। ऐसी स्थिति में हाईकमान सचिन पायलट को यह कहकर साध सकता है कि आने वाला वक्त आपका है। हालांकि, इस ऑप्शन में भी कई पेंच हैं। अगर हाईकमान पायलट के नाम को आगे करती है, तो गहलोत के लिए राजनीतिक रास्ता बंद हो जाएगा। गहलोत ऐसी स्थिति कभी नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ पायलट गुट भी सरकार के एंटी इनकंबेंसी से डरा हुआ है। कांग्रेस हाईकमान के पास दूसरा ऑप्शन गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का है। हालांकि, इसकी संभावनाएं कम हैं। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। इसके अलावा गहलोत को अगर कांग्रेस आगे करती है तो गुर्जर समेत कई जातियों के वोट खिसक जाएंगे। 2018 के चुनाव में भाजपा की परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया था। राज्य में 30-40 सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है।

ऐसा नहीं कि कांग्रेस आलाकमान को इस सास-बहु की लड़ाई को लेकर पता नहीं है पर हर बार विवाद निपटाने के बाद दोबारा गाड़ी पटरी से उतर जाती है। चुनावी साल में कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रिश्ते सुधारने की आखिरी कवायद कर रही है। अगर दोनों गुटों में बात नहीं बनती है तो हाईकमान चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि, मीटिंग से पहले सुखजिंदर रंधावा ने सब कुछ सही होने की उम्मीद जताई है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी बातचीत करेंगे।

पायलट मीटिंग में मुख्यमंत्री बदलने की अपनी पुरानी मांग दोहरा सकते हैं। हाल ही में पायलट ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी थीं, जिस पर गहलोत ने तंज कसा था। पायलट-गहलोत का विवाद 30 महीने पुराना है और इसे सुलझाने में कांग्रेस के 2 महासचिवों की कुर्सी चली गई। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल है कि खरगे के पास अब क्या विकल्प हैं, जिस पर पायलट और गहलोत दोनों मान जाए? अगर खरगे की इस मैराथन मीटिंग में भी बात नहीं बनी तो सचिन पायलट क्या करेंगे? वैसे देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस के विवाद में पायलट की दलीलें मजबूत हैं, जबकि अशोक गहलोत के पास संख्याबल है। गहलोत के पास मजबूत संख्याबल होने की वजह से हाईकमान भी स्वतंत्र फैसला नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी भी दोनों को पार्टी की संपत्ति बताकर विवाद से पल्ला झाड़ चुके हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

चुनावी अभियान का श्रीगणेश

अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में अब सालभर से कम समय बचा है। इसको लेकर जहां विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत चुनौती पेश करने के लिए एकजुट होने का मंत्र तलाश रहे हैं लेकिन अब तक विपक्षी एकता कोई सियासी शक्ल नहीं ले पाई है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने अपने चुनावी अभियान का श्रीगणेश कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा ने पूरे देश में हर लोकसभा सीट के स्तर पर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके लिए मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का जिम्मा सभी भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा गया है।

गत दिनों देशभर के भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री एवं एक केंद्रीय मंत्री ने मीडिया संवाद के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। हर राज्य में प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराते नजर आए। इस अभियान के जरिए भाजपा और उसके कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर जनता के सामने मोदी सरकार के 9 सालों के कामों की रिपोर्ट पेश करेंगे। उप्र में यह शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया संवाद के जरिए की है।

लखनऊ में हरदीप सिंह पुरी ने बीते 9 सालों में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं वैश्विक स्तर पर किए गए कामों का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं। कोरोनाकाल के दौरान हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, उज्जवला योजना आदि का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कैसे 2014 तक 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे लेकिन 2016 में उज्जवला योजना शुरू होने के बाद आज देशभर में 31 करोड़ 50 लाख गैस कनेक्शन हो गए हैं। इसी तरह मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश में एयरपोर्ट की संख्या जितनी थी उससे दोगुनी हो गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोदी सरकार के प्रयासों से उप्र में हुए बदलावों का आंकड़ा पेश किया। योगी ने कहा कि मोदी जी के प्रयासों का सर्वाधिक लाभ उप्र को मिला है। चाहे वह आवास योजना हो, स्वच्छता योजना हो, किसान निधि हो या फिर आयुष्मान योजना। मोदी सरकार के प्रयास से उप्र सरकार ने कई मोर्चों पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। योगी ने कहा कि उप्र में केंद्र सरकार के सहयोग से एयरपोर्ट, एम्स, मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी श्रृंखला तैयार हो चुकी है। एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे का जाल बन चुका है। उप्र जैसे लैंड लॉक्ड प्रदेश में वॉटर वे की संभावना तलाश कर बनारस से हल्दिया के बीच गंगा के जरिए परिवहन की शुरुआत की गई। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सशक्त हुई है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हुई है। अब कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है।

दरअसल, विपक्ष की तरफ से एकजुट होने के प्रयास को देखते हुए भाजपा अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में जुटे हुए हैं, उसने भी नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ाई है। नीतीश कुमार फिलहाल खुद को पीएम पद की दावेदारी से अलग कर सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की हिमायत कर रहे हैं। नीतीश कुमार की कोशिश परवान चढ़ी तो निश्चित रूप से मोदी और भाजपा के समक्ष चुनौती बढ़ेगी। हालांकि अभी विपक्षी एकता कोई सियासी शक्ल नहीं ले पाई है, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय क्षत्रप दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहा है, लेकिन मोदी को हराने के नाम पर अपने निजी स्वार्थ को दरकिनार कर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के बैनर तले लड़ने को तैयार हो गए तो भाजपा की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। हिमाचल के बाद कर्नाटक में पार्टी की हार के बाद भाजपा पहले ही बैकफुट पर है। लोकसभा चुनाव से पहले उसे राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी उतरना है।

भाजपा राजस्थान और मप्र में अपने लिए संभावना देख रही है, वहीं छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना में उसे कड़ी टक्कर मिलने का अंदेशा है। लिहाजा इन राज्यों में लोकसभा चुनाव में हो सकने वाले नुकसान की आंशिक भरपाई की तैयारी भाजपा सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले उप्र से करने की रणनीति बना रही है। उप्र में नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में लोकप्रिय चेहरा मौजूद है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाय चुनाव में मिली शानदार सफलता से भी भाजपा गदगद है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

80 सीटों पर मंत्रियों की रैली

इस कड़ी में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा लोकसभा स्तर पर एक केंद्रीय मंत्री की रैली करने जा रही है। उप्र की सभी 80 लोकसभा सीटों पर एक-एक केंद्रीय मंत्री की रैली होगी। इसका खाका तैयार किया जा चुका है। इसी तरह विधानसभा स्तर पर भी प्रदेश के मंत्रियों का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाजपा की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी एवं सरकार द्वारा जनहित में किए गए कामों की रिपोर्ट पहुंचाना है। यह कार्यक्रम लोकसभा से लेकर बूथ स्तर तक आयोजित किया जाना है। हालांकि 2024 के आम चुनाव के लिए भाजपा अकेले मोदी सरकार की उपलब्धियों के भरोसे ही नहीं बैठी है। गठबंधन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। उप्र में विधानसभा चुनाव से पहले अलग होने वाले सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाने की तैयारी हो चुकी है। गत दिनों विधान परिषद की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में इसकी झलक देखने को मिली। सपा से गठबंधन करके विधायक जिताने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने विधानपरिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को सरकार में शामिल कर गठबंधन का खाका खींच लिया जाएगा।

नीतीश पर विश्वास नहीं

क्या 2024 के आम चुनावों में मोदी विरोधी मुहिम की अगुवाई नीतीश कुमार को मिलने में पेच फंसने लगा है? मोदी के खिलाफ विपक्षी गोलबंदी की अगुवाई को लेकर क्या गतिरोध पैदा हो गए हैं? क्या कांग्रेस विपक्षी गोलबंदी में खुद की अगुवाई का संदेश देने लगी है? ऐसे कई सवालों की वजह बना है 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी बैठक का टल जाना। जिस तरह नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी इस रैली को लेकर उत्साहित थे, उससे यही लगता था कि इस रैली के बाद विपक्ष मौजूदा केंद्रीय सत्ता के खिलाफ गोलबंद होगा, जिस तरह 49 साल पहले पटना में ही हुई रैली के बाद तत्कालीन इंदिरा सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू हुई थी। यह भी अनुमान लगाया जा रहा था कि इसके बाद अपने धवल राजनीतिक दामन के चलते नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी मुहिम के स्वाभाविक नेता के तौर पर उभरेंगे। लेकिन बैठक का टलना बताता है कि विपक्षी खेमे में सब कुछ वैसे नहीं चल रहा है, जैसा नीतीश के उत्साही समर्थक सोच रहे थे।

दरअसल कांग्रेस इस बैठक से किनारा करने लगी थी। पहले की व्यस्तता के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, वहीं कांग्रेस के गैर संवैधानिक प्रमुख राहुल गांधी के बारे में पता ही है कि अपनी अमेरिका यात्रा के चलते बैठक में वे शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इस बैठक में शामिल न होने के लिए अपनी किसी व्यस्तता का बहाना बना चुके हैं। ऐसे में बैठक को टलना ही था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ने कुछ वैसे ही शिखा बांध ली है, जैसे उनके ही मगध के प्राचीन कालीन राजनीतिज्ञ चाणक्य ने तत्कालीन मगध सम्राट नंद के खिलाफ बांध ली थी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पहले तक ऐसा लग रहा था कि मोदी के खिलाफ आक्रामक अभियान में नीतीश की अगुवाई को कुछ किंतु-परंतु के बाद विपक्षी खेमा स्वीकार कर लेगा। लेकिन 13 मई को आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों ने स्थितियां बदल दी हैं। हार-दर-हार हलकान रही कांग्रेस को मिली बड़ी जीत ने उसकी सोच को बदल दिया है। इसमें दो राय नहीं कि अब भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस ही है, लेकिन अतीत की हारों से वह मोदी विरोधी गोलबंदी की अगुवाई से हिचक रही थी। लेकिन कर्नाटक ने उसके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लौटा दिया है। ऐसे में भला वह क्यों स्वीकार करने लगी कि किसी छोटे से दल का नेता उसकी अगुवाई करे?

ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहले नहीं चाहती थी कि विपक्ष का नेतृत्व वही करे। उसकी इस मंशा को ममता बनर्जी भांप रही थीं। वैसे भी ममता पूर्व कांग्रेसी हैं और वे कांग्रेस के मानस को ठीक से समझती हैं। इसीलिए उन्होंने ही नीतीश कुमार को पटना में बैठक कराने का सुझाव दिया था। बहाना बना था 1974 का बिहार आंदोलन, तब बिहार से ही इंदिरा विरोधी रणभेरी फूंकी गई थी। ममता को लगता था कि पटना की बैठक के बाद नीतीश की अगुवाई पर परोक्ष मुहर लग जाएगी और इस बहाने कांग्रेस पर दबाव भी बनेगा कि जिन राज्यों में स्थानीय दल ताकतवर हैं, वहां कांग्रेस उनकी मदद करे। ममता को लगता था कि अगर कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व रखेगी तो मोदी विरोधी चुनावी संग्राम में वह ताकतवर क्षेत्रीय दलों के राज्यों में भी अपने ढंग से गठबंधन थोपने की कोशिश करेगी। इससे स्थानीय दलों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।

लगता है कि कांग्रेस ममता की इस रणनीति को भी भांप गई और उसने पटना बैठक में शामिल न होने के लिए बहानों की फेहरिस्त पेश कर दी। इसलिए नीतीश का त्यागी दांव भी काम नहीं आ रहा है। दो महीने पहले नीतीश के सिपहसालार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने अपनी अध्यक्षता में जनता दल (यू) की कार्यकारिणी का गठन किया था, लेकिन तब पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार केसी त्यागी को कोई जगह नहीं मिली थी। ऐसा नहीं हो सकता कि त्यागी की रूखसती बिना नीतीश की मर्जी के हुई होगी। नीतीश भी जनता दल (यू) के वैसे ही आलाकमान हैं जैसे वंशवादी दलों का आलाकमान होता है। जनता दल (यू) में भी अध्यक्ष की हैसियत नीतीश के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मोदी विरोधी अभियान छेड़ने के बाद उन्हीं केसी त्यागी की उपयोगिता नीतीश कुमार को समझ आने लगी।

नीतीश को उम्मीद है कि विपक्षी लामबंदी में केसी त्यागी के राजनीतिक रिश्ते सहयोगी हो सकते हैं। वैसे विपक्ष के दिग्गजों में भी कांग्रेस के साथ दिखने में कर्नाटक चुनावों के बाद हिचक दिख रही है। हिचक की वजह है मुस्लिम वोट बैंक। कर्नाटक में समूचा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ ही चला गया। मुस्लिम वोटरों के बारे में मान्यता है कि चाहे वह कोलकाता हो या दिल्ली का या बनारस का, कासरगोड का हो या कहीं और का, वह तकरीबन एक ही तरह से सोचता है। कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस का मुस्लिम वोटरों ने एकमुश्त समर्थन किया है, उससे कई भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल सशंकित हैं।

● **विनोद बक्सरी**

1987 के विपक्षी अभियानों की याद

नीतीश की कोशिशों से 1987 के विपक्षी अभियानों की याद आना स्वाभाविक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोफोर्स दलाली के आरोपों से जूझ रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में अरूण नेहरू, रामधन, आरिफ मोहम्मद खान और सतपाल मलिक ने कांग्रेस से अलग राह अपना ली थी। तब नीतीश कुमार, शरद यादव के आदमी माने जाते थे और उन दिनों शरद के राजनीतिक बॉस देवीलाल का हरियाणा की सत्ता पर कब्जा था। तब उन्होंने राजीव विरोधी परिवर्तन रथ चला रखा था। उन दिनों आंध्रप्रदेश के नेता नंदमुरि तारक रामाराव ने तेलुगूदेशम पार्टी के बैनर तले यात्रा निकाल रखी थी। 1987 में समूचे विपक्ष को एक होने का मौका इलाहाबाद उपचुनाव से मिला था, जिसमें राजीव के कभी सहयोगी रहे वीपी सिंह कांग्रेस छोड़कर उतरे थे और कांग्रेस के उम्मीदवार और उप्र सरकार के मंत्री सुनील शास्त्री को हरा दिया था। शास्त्री बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसी एकता होने के आसार तभी दिखने लगे थे, जब बेंगलुरू में सिद्धारमैया सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। 20 मई को हुए सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी को बुलावा नहीं मिला। जिस ममता बनर्जी को मिला, उन्होंने खुद जाने की बजाय अपनी सांसद काकोली दस्तीदार को भेज दिया था। विपक्षी राजनीति के कद्दावर चेहरे शरद पवार भी नहीं थे। चंद्रशेखर राव को भी निमंत्रण नहीं था। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को कांग्रेस से बुलावा मिलना ही नहीं था। विपक्षी राजनीति के एक और अहम चेहरे नवीन पटनायक भी वहां नहीं पहुंचे। जाहिर है कि विपक्षी एकता का प्रबंध होने के पहले ही हिचकोलों में फंसता नजर आया।

फौज के दम पर शुरु, फौज के दर पर खत्म

पाकिस्तान की राजनीति में फौज के दम पर कदम रखने वाले इमरान खान अब उसी के सबसे बड़े घोषित दुश्मन बन चुके हैं। अब जानना सिर्फ इतना है कि आर्मी का दबाव झेलकर भी इमरान खान अपना अस्तित्व बचा पाते हैं या उनकी भी गति वही होनी है जो एमक्यूएम के नेता अल्ताफ हुसैन की हुई। कभी सिंध की राजनीति पर दबदबा रखने वाले अल्ताफ आज लंदन में निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं।

2002 में नेशनल एसेंबली की मात्र एक सीट जीतने वाली इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ 2011 तक एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई तो इसके पीछे पाकिस्तानी फौज ही थी। पाकिस्तान के मशहूर टेलीविजन एंकर नदीम मलिक ने अपने एक प्रोग्राम में यह दावा किया था कि तहरीक-ए-इंसाफ के रूप में पाकिस्तान में एक तीसरी पार्टी को लाने का मॉडल जनरल कियानी का था। वे पीएमएल (एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी द्वारा बारी-बारी से सरकार बनाने के तरीके से खुश नहीं थे। जनरल कियानी ने ही इमरान खान को 2011 अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में लाहौर में एक बड़ा जलसा करने के लिए मनाया और फौज ने इस जलसे को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लाहौर के इस जलसे में एक लाख से ज्यादा लोग आए और इसी जलसे में इमरान ने पाकिस्तान में एक नई क्रांति लाने का ऐलान किया था। जलसे में आई भीड़ को देखकर पाकिस्तान आर्मी को इमरान के रूप में एक नया विकल्प नजर आने लगा और आर्मी इमरान को आगे बढ़ाने में जुट गई। अब आर्मी के सामने एक ही समस्या थी कि इमरान की पार्टी को खड़ा कैसे किया जाए। तब इसकी जिम्मेदारी ली जनरल बाजवा ने।

2018 का चुनाव नजदीक था। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी। पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती थी कि पीएमएल (एन) की सरकार आए। जनरल बाजवा एक तरह से नवाज शरीफ से दुश्मनी पर उतर आए थे। शरीफ पाकिस्तान के आर्थिक व विदेशी मामलों में आर्मी का दखल खत्म करने पर उतारू थे। पाकिस्तानी आर्मी नवाज शरीफ द्वारा भारत से रिश्ते सुधारने के प्रयास के भी खिलाफ थी। पीएमएल (एन) की सरकार के दौर में ही पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा 1999 में मार्शल लॉ लगाने के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जनरल बाजवा किसी भी कीमत पर नवाज को पाकिस्तान की राजनीति से बाहर करने पर आमादा हो गए।

पाकिस्तान की आर्मी ने ही न्यायपालिका के जरिए नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले फैसले करवाए। जनरल बाजवा ने ही 2018 से पहले पीएनएल (एन) से लोगों को तोड़कर इमरान खान की पार्टी में ज्वाइन कराया। उस समय पाकिस्तान के सबसे बड़ी चीनी मिल के मालिक जहांगीर तरीन के हवाई जहाज का इस्तेमाल इस काम के लिए खूब किया गया। उन्हें इमरान का एटीएम तक कहा गया।

2018 के चुनाव में आर्मी के तमाम हस्तक्षेप के बावजूद इमरान खान को बहुमत नहीं मिला तो फिर जनरल बाजवा ने सरकार के लिए जरूरी नंबर का भी इंतजाम किया। तमाम छोटी पार्टियों को इमरान खान के इत्तेहादी बनने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन आर्मी के साथ इमरान खान का यह हनीमून पीरियड बहुत लंबा नहीं चल पाया। दो साल होते-होते टकराव शुरू हो गए। टकराव की मुख्य बजह बना बाजवा की इमरान सरकार पर टोटल कंट्रोल रखने की ख्वाहिश। वित्त व विदेश मामलों पर जनरल बाजवा ने पहले ही कब्जा कर रखा था, धीरे-धीरे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप बढ़ता गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आर्मी और पुलिस की कार्रवाई को भी इमरान खान की जानकारी से दूर रखा गया। इस बीच पाकिस्तान की आर्थिक हालत और खराब हो गई और इमरान खान को आईएमएफ के पास जाना पड़ा। एक तो इमरान खान प्रधानमंत्री के रूप में बुरी तरह फेल हो रहे थे और दूसरे पीएमएल (एन) और पीपुल्स पार्टी ने हाथ मिलाकर देश में सरकार विरोधी मोर्चा बना लिया था, जिसे पीडीएम का नाम दिया गया। इस पीडीएम ने इमरान खान को कम, पाकिस्तानी आर्मी और जनरल बाजवा को ज्यादा निशाना बनाया। फिर पंजाब में भ्रष्टाचार और खुद इमरान की बेगम की उसमें संलिप्त होने की खबरें आने लगी तो आर्मी के सामने खुद को बचाने का सवाल खड़ा होने लगा।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

आर्मी ने झाड़ लिया पल्ला

इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में फेल होने लगे तो आर्मी ने उनसे पल्ला झाड़ने का मन बना लिया। अक्टूबर 2021 में जब फिरकापरस्त तंजीम तहरीक-ए-लब्बैक ने कोहराम मचाया और इमरान खान की सरकार उस पर काबू करने में पूरी तरह विफल हुई तो फिर जनरल बाजवा ने सीधे हस्तक्षेप किया और इमरान खान को विश्वास में लिए बिना एक करार कर लिया, जिसका विवरण आज भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। यहीं से इमरान खान के प्रति जनरल बाजवा का मोहभंग हुआ और वे पीएमएल (एन) की ओर फिर से देखने लगे। इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि जनरल बाजवा ने मार्च 2022 के पहले ही शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए एक डील कर ली थी। जिसके तहत पीडीएम बाजवा को एक और साल के लिए सेवा विस्तार देगी और उन्हीं की देखरेख में 2023 में चुनाव कराया जाएगा। इस डील की खबर मिलने के बाद खुद इमरान खान अपनी ओर से उससे बेहतर डील लेकर गए और पाकिस्तान के सदर आरिफ अल्वी के यहां गुप्त मुलाकात कर सेवा विस्तार का ऑफर भी दे दिया। लेकिन उनकी बात सिरे नहीं चढ़ी। इमरान खान सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए जनरल बाजवा के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनकी चिंता नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर थी। वरीयता के आधार पर जिनके आर्मी चीफ बनने की संभावना सबसे ज्यादा थी, उन्हीं से इमरान खान को खतरा था। यानी वह वर्तमान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ओहदा संभालने से रोकना चाहते थे। कारण एक ही था कि उन्हें डर था कि मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद उनकी राजनीति आसान नहीं होगी, क्योंकि आसिम मुनीर के साथ उनकी निजी दुश्मनी पहले ही हो गई थी जब वह आईएसआई चीफ थे। वे इमरान के करप्शन के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इमरान ने वीटो लगाकर आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटवाया था। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए इमरान खान ने कई ओछे हथकंडे भी अपनाए। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने मुनीर और उनके परिवार के लोगों के बारे में पूरी जानकारी भी निकलवाई थी।

चीन ने बढ़ाई चिंता

चीन का भारतीय सीमा के निकट ढांचागत विकास बहुत तेजी से हो रहा है। वैसे तो चीन भारत की सीमा पर 50 के दशक से ही ढांचागत निर्माण कर रहा है, परंतु इस बीच इस कार्य में अभूतपूर्व तेजी आई है। अरूणाचल से लेकर पश्चिम लद्दाख तक जो ढांचागत विकास चीन कर रहा है वह चिंताजनक है। कुछ ढांचागत निर्माण जो विवादास्पद हैं वे हैं- लद्दाख में पैंगाग त्सो झील पर एक नए पुल का निर्माण, तिब्बत में नई हवाई पट्टियों का निर्माण, अरूणाचल में सील्ड सड़कों का निर्माण, वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट नए गांवों का बसाया जाना, नियंत्रण रेखा के समानांतर सड़कों का निर्माण इत्यादि। पैंगाग झील पर पुल चीन की सीमा से भारत में प्रवेश को अत्यंत सुगम बना देगा, और यही भारत की चिंता है। इस पुल के निर्माण का भारत ने कठोर विरोध किया है। किंतु, जैसा कि चीन की आदत है, चीन इन सबसे प्रभावित नहीं हुआ है और निर्माण कार्य बहुत तेजी से कर रहा है।

भारत-चीन के मध्य संसार की सबसे लंबी विवादित सीमा का प्रबंधन भारत और चीन दोनों के लिए अस्मिता के प्रश्न से जुड़ा है। भारत चीन (तिब्बत) के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ चलती है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत सैद्धांतिक रूप से मानता है कि यह सीमा तिब्बत के साथ है जिस पर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। भारत इस क्षेत्र को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से अधिक कुछ नहीं मानता।

भारत और चीन के बीच 3,488 किमी सीमा की राज्य-वार लंबाई निम्नानुसार है- जम्मू और कश्मीर 1597 किमी, हिमाचल प्रदेश 200 किमी, उत्तराखंड 345, सिक्किम 220 और अरुणाचल प्रदेश 1126 किमी। सीमा पूरी तरह से सीमांकित नहीं है और वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने और पुष्टि करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई वाले दुरूह पहाड़ हैं और जनसंख्या कम है, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कठिन काम है। भारत की पूर्ववर्ती सरकारों ने जानबूझकर भारतीय क्षेत्र में ढांचागत विकास नहीं किया। वो चीन से इस तरह खौफ खाते थे कि उन्हें लगता था कि अगर सीमा पर सड़कें, पुल और टनल बन गई तो चीन हमारे भीतर तक घुस आएगा। इस फोबिया की भरपाई वर्तमान सरकार कर रही है।

मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने भारत-चीन सीमा पर रणनीतिक महत्व की 73 सड़कों के निर्माण का निर्णय किया है। इन 73 सड़कों में से, 804.93 किमी लंबाई वाली 27 सड़कों का निर्माण गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन विभाग) द्वारा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में 1937 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इन 27 सड़कों के निर्माण का कार्य बीआरओ (15 सड़कें), सीपीडब्ल्यूडी (8 सड़कें), एनपीसीसी (2 सड़कें) और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (2 सड़कें) को सौंपा गया है। 27 सड़कों में से 8 सड़कों का काम पूरा हो चुका है। 2 सड़क को रक्षा मंत्रालय द्वारा जीएस रोड में परिवर्तित किया गया। अन्य सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस क्षेत्र की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल की है। आईटीबीपी ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अग्रिम सीमा चौकियों (बीओपी) की स्थापना की है। इस सीमा पर आईटीबीपी द्वारा कुल 173 बीओपी स्थापित किए गए हैं, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर) में 35, मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) में 71, पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश) में 67 हैं।

पैंगोंग झील लगभग 135 किमी लंबी है। इसका दो तिहाई हिस्सा चीन और लगभग एक तिहाई भारत के पास है। परंतु चीन द्वारा अपने तरफ पूर्व निर्मित पुल के साथ एक और पुल के निर्माण की रिपोर्ट आ रही है। पुराना पुल 1960 के दशक से चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में है। यहां यह बात स्मरणीय है कि चीन ने भारत का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जिसे अक्साई चिन कहते हैं, पहले ही अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसके अतिरिक्त लगभग 5300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जिसे ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट कहते हैं और जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान ने चीन को एक समझौते के तहत हस्तांतरित कर दिया है। यह असल में भारत का वैधानिक क्षेत्र है। चीन ने इस हिस्से को अपने खोतन राज्य में सम्मिलित कर दिया है। इसी क्षेत्र से होकर काशगर के लिए तिब्बत और खोतन को जोड़ने वाला राजमार्ग जाता है। चीन द्वारा अनियंत्रित इंफ्रा निर्माण पर हालांकि भारत कह रहा है कि हमने अपने क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है और न ही हमने अनुचित चीनी दावे या ऐसी निर्माण गतिविधियों को स्वीकार किया है। लेकिन भारत की ओर से किए जाने वाले ऐसे विरोध प्रतीकात्मक ही होते हैं जिसका चीन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।

● **कुमार विनोद**

एलएसी पर बुनियादी ढांचे का निर्माण

पैगोंग लेक पर नया पुल (जो झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारों के बीच 130 किलोमीटर की दूरी को कम करता है) क्षेत्र में भारत के सामरिक लाभ को नकारने के प्रयास का हिस्सा है। हालांकि भारत ने, खासतौर पर मोदी सरकार के आने के बाद, बेहतर सामरिक, संचालनात्मक तैनाती में सहायता के लिए बहुत सारे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। अभी कुछ दिन पूर्व ही संपन्न क्वाड बैठक में समग्र सुरक्षा चर्चा के हिस्से के रूप में पैगोंग लेक पर पुल के विवाद पर चर्चा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका से बने चार देशों के क्वाड के नेताओं की बैठक गत दिनों टोक्यो में हुई थी। समूह का लक्ष्य क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता का मुकाबला करना है। लेकिन क्वाड के मंच से इस पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं की गई। क्वाड में शामिल चार देशों में से भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी अचिन्हित सीमा दुनिया की सबसे लंबी सीमा है जिसे चीन निरंतर सीमा विवाद में परिवर्तित करता जा रहा है। 2020 में हिंसक टकराव में दोनों ओर के सैनिक मारे गए थे। उसके बाद सैन्य तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 15 दौर की बातचीत के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी भी सीमा पर हजारों सैनिक तैनात हैं। दुनिया के दो बड़े परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच यह तनाव गंभीर चिंता का विषय है।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

लिव-इन रिलेशनशिप का बुरा अंजाम

प्रेम, जिस शब्द में एक रूहानी एहसास है, जो दो लोगों को एक-दूसरे को समझने का पहला जरिया होता है लेकिन पिछले कुछ समय से देशभर में सामने आ रही कई घटनाओं ने इस परिभाषा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इसके अलावा बर्बरता, वहशीपन और इंसानियत को शर्मसार कर देने की सारी मर्यादाएं टूट रही हैं। एक के बाद एक ऐसे हत्या के मामले सामने आ रहे हैं जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कोई प्रेम करने वाला इंसान अपनी ही प्रेमिका के साथ यह सलूक कर सकता है? कल तक हमेशा साथ रहने की कसमें खाने वाला प्रेमी निसृंशता से अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है।

पिछले साल दिल्ली के श्रृद्धा हत्याकांड के बाद शुरू हुआ यह सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत दिनों मुंबई से एक मामला सामने आया है जिसमें मुंबई में एक शख्स ने अपनी लिव-इन-पार्टनर की हत्या कर पेड़ काटने वाले कटर से शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। आरोप है कि वो शव के साथ ही घर पर तीन-चार दिन से रह रहा था। पड़ोसियों को जब बदबू आई तो पुलिस को खबर की गई। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।

सरस्वती हत्याकांड़- महाराष्ट्र के मुंबई में दिल्ली जैसा हत्याकांड सामने आया है। मुंबई में एक 56 साल के व्यक्ति मनोज साने ने 32 साल की युवती सरस्वती की हत्या कर दी। बता दें कि लंबे समय से दोनों लिव-इन में रह रहे थे। पहले व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या की और फिर शव को चेनशॉ (पेड़ काटने वाली मशीन) से कई टुकड़ों में काट दिया। जानकारी के अनुसार बदबू नहीं आए इसलिए वह शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला करता था। साथ ही उसने महिला के शव के टुकड़ों को मिक्सर में भी पीसा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 8 जून 2023 को सामने आई है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से अतीत के अन्य सभी हत्याकांड को याद दिला दिया है। इस खबर में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे लिव-इन रिलेशनशिप में रहे प्रेमी-प्रेमिकाओं की जिनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के ही प्यार ने की। जिसमें कई मशहूर चर्चित हत्याकांड ने लोगों में गुस्सा भर दिया था। जिस तरह से इन लोगों ने लड़कियों के साथ बर्बरता की वो एक साधारण इंसान कभी करने की सोच भी नहीं सकता।

गौरी श्रीवास्तव हत्याकांड- उप्र की राजधानी लखनऊ में 2 फरवरी 2015 में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया था। जहां एक तरफा प्यार में पड़े एक लड़के ने एक परिवार के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया था। लखनऊ के अमीनाबाद में रहने वाली 19 साल की लॉ स्टूडेंट गौरी श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी। गौरी अपनी हत्या के एक दिन पहले अपने घर से निकली थी उसके बाद वह गायब हो गई। जिसके बाद पुलिस को उसके शव के टुकड़े बरामद हुए थे। आरोपी ने गौरी की हत्या कर आरी मशीन से उसके शव के 17 टुकड़े किए थे। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गौरी की हत्या हिमांशु प्रजापति नाम के लड़के ने की थी। इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया था।

निक्की यादव हत्याकांड- निक्की यादव की हत्या 14 फरवरी साल 2023 को दिल्ली में की गई थी। 14 फरवरी एक ऐसा दिन जब हर व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति को अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन निक्की की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। निक्की की हत्या साहिल गहलोत (24) ने दिल्ली में स्थित निगमबोध घाट श्मशान की पार्किंग में की थी। 23 साल की निक्की यादव का शव वेलेंटाइन-डे यानी 14 फरवरी को उसके प्रेमी साहिल गहलोत के परिवार के एक रेस्तरां में फ्रिज के अंदर मिला था। निक्की और साहिल लंबे समय से लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। हत्या के बाद साहिल ने निक्की की लाश को फ्रिज में रखा था और बाद में उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं खबरों की मानें तो इस कत्ल की साजिश में साहिल के रिश्तेदार, दोस्त और एक पुलिसवाला भी शामिल था।

मेघा थोरवी हत्याकांड- मेघा थोरवी की हत्या महाराष्ट्र नालासोपारा में 11 फरवरी 2023 को की गई थी। मेघा थोरवी की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर हार्दिक शाह ने की थी। हार्दिक ने मेघा की हत्या तौलिए से गला घोंटकर की थी जिसके बाद मेघा के शव को बेड बॉक्स में छिपा दिया था। बता दें कि मेघा (37) पेशे से नर्स थी, लेकिन हार्दिक बेरोजगार था। उसका खर्च मेघा को ही उठाना पड़ता था। इसे लेकर दोनों के बीच काफी झगड़े होते रहते थे। हालांकि आरोपी मुंबई से राजस्थान भागने की फिराक में था लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

अंकिता भंडारी हत्याकांड- अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गंगा-भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट थीं, जिसकी हत्या पुलकित आर्य ने की थी। पुलकित ने अंकिता को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया था। वहीं, मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अंकिता का यौन उत्पीड़न किया था। इसके साथ ही आरोपी ने अन्य लोगों से भी अंकिता का यौन उत्पीड़न करवाया था। वहीं, आरोपी साहिल ने अंकिता पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सेवा देने का भी दबाव बनाया था। अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर 2022 को की गई थी।

श्रद्धा वालकर हत्याकांड- महाराष्ट्र की रहने वाली 27 वर्षीय श्रद्धा वालकर की दिल्ली के महरौली में उसके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला (28) ने कथित तौर पर 18 मई 2022 को गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर छतरपुर के जंगल सहित अलग-अलग जगहों पर फेंक दिए थे। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में आफताब द्वारा की गई हैवानियत ने लोगों को सन्न कर दिया था। बता दें कि श्रद्धा और आफताब लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी आफताब को गिरफ्तार कर लिया था। आफताब की श्रद्धा से मुलाकात एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। एक निश्चित समय के बाद, वे मुंबई में एक ही कॉल सेंटर में काम करने लगे और एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए। अलग-अलग धर्मों के होने के कारण दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था।

रिबिका पहाड़िया हत्याकांड- झारखंड के साहिबगंज में दिल्ली जैसा ही मामला देखने को मिला था। यहां 25 साल के दिलदार अंसारी ने रिबिका पहाड़िया के 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। हत्या के बाद आरोपी दिलदार ने रिबिका के शव के टुकड़े इलेक्ट्रिक कटर से किए थे। कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए थे, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिए थे। जिसे कुत्ते नोंच-नोंच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्तों को इंसान का मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ था।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

अतुलिता बल धामं

भगवान हनुमान अनंत शक्ति, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। पूरे देश के मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अक्सर गदा के साथ, या भक्ति मुद्रा में भगवान राम के सामने झुकते हुए देखा जाता है। बजरंगबली भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। भारत में, भगवान हनुमान सबसे प्रसिद्ध देवता हैं और उन्हें अदम्य शक्ति के स्तंभ के रूप में पूजा जाता है। जबकि सभी भक्त चिरंजीवी भगवान हनुमान की पूजा और आराधना करते हैं, वे कुश्ती लड़ने वालों और पहलवानों के पसंदीदा देवता भी हैं। मंगलवार को, असंख्य भक्त शक्ति और समृद्धि के लिए उनके मंदिरों में आते हैं। माना जाता है कि बजरंग बली, अपनी ताकत और पराक्रम के साथ एक भक्त को जीवन में सभी बुराइयों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम्
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।।

भगवान हनुमान की शक्ति, वीरता और पराक्रम के किस्से रामायण के भव्य महाकाव्य, और महाभारत और अग्नि पुराण के धार्मिक ग्रंथों में भी बहुतायत में पाए जा सकते हैं। जबकि भगवान हनुमान की कहानियां उन दिव्य ग्रंथों में पाई जाती हैं जिनकी सदियों से पूजा की जाती रही है, उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में भी प्रार्थना की जाती है जो भक्तों को कलियुग में पाई जाने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से हनुमानजी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान हासिल है।

इसके अलावा, चूंकि हनुमान जी के पास ताकत है जिसे मापा नहीं जा सकता है, इसलिए हनुमान जी को अतुलिता बल धामं कहा जाता है, जिसका अर्थ है अथाह शक्ति। उन्हें एक पर्वत के रूप में बड़ा होने के लिए विस्तार करने की क्षमता के साथ वर्णित किया गया है, या एक मक्खी के रूप में छोटा होने का अनुबंध किया गया है।

संक्षेप में, शास्त्रों में भगवान हनुमान को एक पर्वत के रूप में विशाल और एक विशाल मीनार के रूप में लंबा बताया गया है। उनका रंग पीला, पिघला हुआ सोना जैसा चमकता है। उनका चेहरा सबसे चमकीले माणिक से अधिक चमकीला है, और पूंछ अनिश्चित लंबाई तक फैली हुई है। दूर चट्टान पर खड़े होकर वह तेज गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ते हैं। वह हवा में कूदने के बाद बादलों के बीच तेज गति से उड़ते हैं, जिससे नीचे समुद्र की लहरें छिटकती हैं।

रामायण में आगे कहा गया है कि बंदरों का मुखिया एक आदर्श प्राणी है। शास्त्रों के अध्ययन में, या शास्त्रों के अर्थ को समझने और समझाने में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। जब बजरंग बली सीता माता के ठिकाने का पता लगाने के लिए लंका में थे, तो उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया था। वह सीता माता को भगवान राम का संदेश देने में सफल रहे, और एक अंगूठी जो भगवान राम ने उन्हें दी थी, उससे माता सीता को यह समझाने में मदद मिली कि वह वास्तव में भगवान राम के दूत हैं। हालांकि, भगवान राम को सीता माता का समाचार देने के बाद, राक्षस राजा रावण के बंधक बन गए। सभी राक्षस मजबूत रस्सियों में बंधे हनुमान को उन्हें रावण के दरबार में ले गए और उनकी पूंछ में आग लगा दी। तभी हनुमान जी ने उन्हें बांधने वाली सभी रस्सियों को तोड़ दिया और अपनी पूंछ से लंका में चारों तरफ आग लगा दी।

रावण के खिलाफ युद्ध के बाद अयोध्या लौटने पर, प्रभु श्रीराम ने कहा कि भगवान हनुमान अमर रहेंगे, और जब भी कोई श्रीराम को याद करेगा, तो वह हनुमान को भी याद करेगा। हनुमान जी इस प्रकार चिरंजीवी हैं, जिसका अर्थ है अमर, और जब भी कोई भक्त श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करता है, तो उसे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी।

लोककथाओं के अनुसार, हनुमान जी वो भगवान हैं जिन्होंने भगवान राम को सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में मदद की थी। भगवान हनुमान की पूजा पूरे भारत में और दुनिया भर में कई जगहों पर बहुत श्रद्धा के साथ की जाती है। उनकी छवियों और मूर्तियों को कई रूपों में पाया जा सकता है, और ज्यादातर मामलों में, उन्हें एक सिर, दो भुजाओं, एक मजबूत मानव शरीर और एक बंदर के चेहरे और एक लंबी पूंछ के साथ देखा जाता है। हालांकि, हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान के रूप में भी पूजा जाता है और उनके रूप का अपना महत्व है। पंचमुखी पांच मुखी है और पंचमुखी हनुमान के रूप में, हनुमान जी के पांच चेहरे हैं, जिनमें से प्रत्येक पांच भगवान विष्णु के पांच सबसे महत्वपूर्ण अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि श्री हनुमान पूर्व का सामना करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यह मन की शुद्धता और सफलता प्रदान करता है, और नरसिंह दक्षिण की ओर मुंह करके एक भक्त को जीत और निडरता का आशीर्वाद देता है। जब हनुमान जी गरुड़ के रूप में पश्चिम की ओर मुख करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यह काले जादू और सभी नकारात्मकता के प्रभावों को नकारता है। इसी तरह, जब पंचमुखी हनुमानजी वराह के रूप में उत्तर की ओर मुंह करते हैं, तो उपासकों को धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हयग्रीव के रूप में, जब श्री हनुमान का मुख आकाश की ओर होता है, तो उपासक को संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त होती है।

भगवान हनुमान की प्रशंसा का प्रिय पाठ हनुमान चालीसा है। हनुमान जी पर आधारित हनुमान चालीसा, सबसे अधिक जप और सबसे प्रिय भक्ति प्रार्थना है। यह प्रभु हनुमान की भगवान राम के प्रति भक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा गया है। एक लोकप्रिय धारणा है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से दिन-प्रतिदिन की समस्याओं में हनुमानजी के दिव्य हस्तक्षेप का आव्हान होता है और भक्तों को मन की शांति मिलती है। लाखों हनुमानजी के भक्त शपथ लेते हैं और इस प्रार्थना ने बच्चों और बड़ों के लिए चरित्र और एक धर्मी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है!

● **ओम**

सच्ची राजनीति

पार्टी हाईकमान के सामने जाते हुए पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की टांगें बुरी तरह कांप रही थीं।

हाईकमान ने सवाल दागा, प्रदेश में लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं व भरपूर संसाधनों के बावजूद हम चुनाव हार गए। हमें तो तुम्हारी बिरादरी के भी वोट नहीं मिले। ऐसा क्यों?

क्यूंकि हम जाति और धर्म के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे जबकि विपक्षी नेताओं ने आम जनता से सीधे जुड़े मुद्दों महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी पर बात की।

अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर मेज पर रखते हुए उसने आगे कहा, मुझे खेद है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। प्रस्तुत है मेरा इस्तीफा।

तो अब क्या करोगे?

अब सच्ची राजनीति करूंगा।

– राजकुमार कांदु

कटु वाणी

क्या हुआ?

लक्ष्मी आई है।

खाक लक्ष्मी आई है। तीसरी बार भी लड़की ही। और, सासू मां ने अनीता को वहीं अस्पताल में ही कोसना शुरू कर दिया।

शोरशराबा सुनकर अनीता का ऑपरेशन करके उसके बच्चे की डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर बाहर आई और सासू मां पर गुर्राते हुए बोली- मां जी! क्या आप नहीं जानतीं, कि बच्चे को पहले नौ माह पेट में रखना, फिर जन्म देना, वह भी ऑपरेशन से, कितना कठिन होता है? आपने पोते की चाहत में अपनी बहू को तीसरी बार खतरे में डाल दिया। आज का ऑपरेशन तो बहुत ही जटिल था, और बड़ी मुश्किल से अनीता की जान बची है। वैसे तो हर बार ही बच्चे को जन्म देना मां के लिए पुनर्जन्म होता है, पर आप यह समझिए कि आज तो आपकी बहू मौत के दरवाजे से ही वापस लौटी है। और-आप संतोष का

अनुभव करने की जगह उसे कोस रही हैं। लानत है आप पर। इतने विषैले बोल इतनी कटु वाणी, आखिर बहू का दोष ही क्या है? उसने एक बेटी को जन्म दिया है, तो बेटी-बेटे से किसी भी तरह से कम है क्या? मां जी अपनी कटुवाणी और रुग्ण मानसिकता का त्याग कर दीजिए, नहीं तो आगे जाकर आप बिलकुल अकेली रह जाएंगी। इस पर सासू मां निरुत्तरित थीं।

– प्रो (डॉ.) शरद नारायण खरे

याद बहुत आता है

मां-बाबुल बचपन घर-आंगन कितना तरसाता है
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

बचपन बीता खेल कूद कर जिस आंगन में मेरा,
यादों में वह बसा हुआ है परछाई सा मेरा,
घने वृक्ष की सुखद छांव मन भूल नहीं पाता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

इमली की शीतल छाया में सिकड़ी खेल सुहाना।
ऊंच-नीच और छुपन-छुपाई उछल कूद कर गाना।
रंग-रंगीला सा वह बचपन तन-मन रंग जाता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

आंगन में चहकें गौरैया उनके संग फुदकना।
रंग रंगीली प्यारी-प्यारी तितली खूब पकड़ना।
कोयल के संग खूब कुहूकना मन को सरसाता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

गिलहरी की चिड़क-चिड़क गइया का रंभा बुलाना।
सावन में डालों पर झूले पेंग बढ़ा मुस्काना।
गिल्ली-डंडा लट्टू-लत्ती अब भी मन भाता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

गोधूलि में भर-भर पानी आंगन द्वार छिड़कना।
माटी की सोंधी खुशबू से आंगन द्वार महकना,
मस्त हवाओं का हर झोंका मन को महकाता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

लेट चारपाई पर सुंदर आसमान को तकना।
झुंड परिंदों के अनुशासित वापस घर तक उड़ना।
उनकी चहकन और चहकना मन को चहकाता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

लूडो, कैरम, कोट पीस दुपहर में छम्मा-छम्मा।
हम बच्चों के साथ खेलती मेरी प्यारी अम्मा।
कुल्फी और फालूदा का दिन है रह-रह ललचाता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है
संध्या दीप आरती का स्वर नई चेतना जगना,
बस्ता बैग उठाकर अपना कुछ देरी फिर पढ़ना।
संध्या पूजन अर्चन का संगीत याद आता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

कुल्फी और फालूदा खाना, गर्मी में था भाता।
मां तेरी वह दूध जलेबी से अब भी है नाता।
लाड़-लड़ाना डाट-डपटना कितना तरसाता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

जुगनू की वो न्यारी चमचम अब न कहीं है दिखती,
कहां गए वह जुगनू प्यारे किसकी है यह गलती,
बंद दुपट्टे में जुगनू जब उजियारा लाता है।
मुझको वह बचपन का आंगन याद बहुत आता है।

– मंजूषा श्रीवास्तव 'मृदुल'

भारत का फिर टूटा सपना

इंग्लैंड में एक बार फिर भारतीय टीम का विश्व विजेता बनने का सपना टूट गया। द ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 209 रनों से हराते हुए पहली बार टेस्ट में विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके साथ ही वह पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने वनडे, टी-20 और टेस्ट यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की। भारत ने आखिरी दिन 280 रन बनाए थे और उसके 7 विकेट बचे थे, लेकिन विराट कोहली और जडेजा एक ही ओवर में बोलैंड के शिकार बने और इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का सपना चकनाचूर होते देर नहीं लगी। पिछली बार भारत को न्यूजीलैंड के हाथों इंग्लैंड में ही हार मिली थी।

ऐतिहासिक टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 164 रन बनाए थे। विराट कोहली 44 रन बनाकर, जबकि अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत को 280 रनों की जरूरत थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 444 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। आखिरी दिन समय भरपूर था और भारत के पास 7 विकेट थे तो एक उम्मीद थी कि विराट कोहली और रहाणे पूर्व कप्तान और पूर्व उपकप्तान की जोड़ी कुछ करिश्मा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौथी पारी में रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन 43 रनों पर आउट हो गए। उनसे पहले शुभमन गिल एक विवादास्पद फैसले का शिकार बने। उनके खाते में 18 रन रहे, जबकि पुजारा एक खराब शॉट खेलकर 27 रनों पर चलते बने। इस तरह 3 विकेट गिरे थे। भारत का 5वें दिन का पहला विकेट विराट कोहली के रूप में गिरा। वह 49 रनों के स्कोर पर बोलैंड की बाहर जाती गेंद पर बल्ला अड़ा बैठे और सेकंड स्लिप में स्टीव स्मिथ ने हवा में गोता लगाते हुए कैच लपक लिया। इसी ओवर में बोलैंड ने बल्लेबाजी हुनर की वजह से अश्विन पर वरीयता प्राप्त रविंद्र जडेजा को शून्य के स्कोर पर आउट कर दिया।

बोलैंड के बाद स्टार्क ने मोर्चा संभाला तो अजिंक्य रहाणे को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कराते हुए भारत की रही सही उम्मीदों को भी तार-तार कर दिया। वह 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शार्दुल ठाकुर बिना खाता खोले नाथन लायन के शिकार बने तो उमेश यादव एक रन बनाकर स्टार्क की गेंद पर कैरी के हाथों लपके गए। इसके बाद श्रीकर भरत (23) और मोहम्मद सिराज को नाथन लायन को आउट करते हुए ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बना दिया। भारत की दूसरी पारी 234 रनों पर सिमट गई। इस हार के बाद भारतीय टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैच के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी टीम को तैयारी के लिए 20-25 दिन का समय चाहिए था। ऐसे में वह किसको दोष देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी टीम के बाकी खिलाड़ी और वह खुद आईपीएल खेलने में व्यस्त थे। रोहित शर्मा यह बयान देकर खुद ही जाल में फंस चुके हैं। डब्ल्यूटीसी फाइनल से 20-25 दिन पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी आईपीएल खेलने में व्यस्त थे। टीम के ज्यादातर खिलाड़ी मैच से सिर्फ छह-सात दिन पहले लंदन पहुंचे थे। वहीं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर खिलाड़ियों ने आईपीएल छोड़ टेस्ट फाइनल की तैयारी शुरू कर दी थी।

आईपीएल 2023 से पहले रोहित ने वर्कलोड मैनेजमेंट और लीग को लेकर बयान दिया था। उस वक्त टीम इंडिया अपने घर में ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से वनडे सीरीज हारी थी। ऐसे में कई पूर्व क्रिकेटर्स का कहना था कि वर्ल्ड कप के लिए तय खिलाड़ियों को आईपीएल जैसे टूर्नामेंट से आराम लेना चाहिए, ताकि वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसे अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए तरोताजा रह सकें। हालांकि, भारतीय कप्तान रोहित ने इसके विपरीत बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि कोई खिलाड़ी वर्कलोड मैनेज करने के लिए आईपीएल से दूर होगा। रोहित ने कहा- सभी खिलाड़ियों को काफी अनुभव है। इसलिए उन्हें अपने शरीर की देखभाल खुद करनी होगी और अगर उन्हें लगता है कि यह नहीं हो पा रहा है, तो वे हमेशा इसके बारे में बात कर सकते हैं और आईपीएल में एक या दो गेम में ब्रेक ले सकते हैं। हालांकि, मुझे संदेह है (अगर) कि ऐसा होगा लेकिन...। इसके बाद रोहित चुप हो गए थे। 31 मार्च से लेकर 28 मई (29 मई को रिजर्व डे पर नतीजा आया) तक लगभग दो महीने आईपीएल चला और चेतेश्वर पुजारा को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ियों ने लीग में हिस्सा लिया, जबकि उन्हें पता था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी के लिए उन्हें एक हफ्ते से भी कम समय मिलेगा।

● आशीष नेमा

रोहित ने फ्रेंचाइजी को दिए थे संकेत

रोहित ने आईपीएल शुरू होने से पहले कहा था कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों को संकेत दिए हैं। रोहित ने कहा- यह सब अब फ्रेंचाइजी पर निर्भर है। फ्रेंचाइजी अब उन्हें (खिलाड़ियों को) अपनाती हैं, इसलिए हमने टीमों को कुछ संकेत दिए हैं। हालांकि, अंतिम फैसला फ्रेंचाइजी पर निर्भर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खिलाड़ियों को अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। अब जब टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गई है तो रोहित का कहना है कि उनकी टीम को 20-25 दिन तैयारी के लिए चाहिए था। इस साल प्लेऑफ में गुजरात, चेन्नई, लखनऊ और मुंबई की टीम पहुंची थी। रोहित की टीम मुंबई जहां 26 मई को गुजरात से क्वालिफायर-2 में हारकर बाहर हुई थी। वहीं, कोलकाता की टीम 20 मई को लीग राउंड का आखिरी मैच खेली थी। इसके बाद उमेश और शार्दुल लंदन पहुंच गए थे। वहीं, कोहली की बैंगलोर ने 21 मई को आखिरी मैच खेला था। इसके बावजूद कोहली और सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से 10 दिन पहले ही इंग्लैंड पहुंच पाए। गुजरात और चेन्नई के खिलाड़ी तो 29 मई को आईपीएल फाइनल खेल रहे थे। ज्यादातर खिलाड़ी टेस्ट फाइनल से एक हफ्ते पहले इंग्लैंड पहुंचे।

जब अनिल कपूर की मूंछों को देख डायरेक्टर ने किया था कमेंट, दिल पे दिल लगी बात, रच दिया इतिहास

बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया यानी अनिल कपूर 66 साल की उम्र में भी बेहतरीन रोल्स के जरिए लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। अनिल कपूर ने 40 साल पहले 1983 में वो सात दिन से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

अभिनेता अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर और भाई बोनी कपूर नामी-गिरामी फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। हालांकि, अनिल के लिए बॉलीवुड का सफर आसान नहीं रहा है। शुरुआत में उन्हें मनमोहन देसाई जैसे बड़े डायरेक्टर ने सिर्फ मूंछों की वजह से नकार दिया था। अनिल कपूर ने इसका जिक्र एक बार अनुपम खेर के टीवी शो द अनुपम खेर शो में किया था। उस शो में अनिल कपूर ने कहा था कि एक बार डायरेक्टर मनमोहन देसाई साहब ने उनसे कहा था कि मूंछों वाला एक्टर कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस शो में उन्होंने खुलासा किया, मैं मनमोहन सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। अक्सर वह अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में बनाते थे।

जैकी को फिल्म मिलने पर हैरान थे अनिल कपूर

अनिल कपूर ने बताया, एक बार मनमोहन देसाई ने जैकी श्रॉफ को साइन किया तो मुझे बेहद अजीब लगा। जैकी को फिल्म में लेने पर अनिल कपूर बेहद हैरान हुए। अनिल कपूर ने कहा कि उन्हें मनमोहन देसाई ने कहा था कि तू एक्टर है, लेकिन स्टार नहीं बन सकता क्योंकि तेरी मूंछें हैं। यह बात अनिल कपूर ने अपने दिल पर ले ली। इसके बाद उनकी फिल्म ईश्वर हिट साबित हुई। तब मनमोहन देसाई ने खुद अनिल को ऑफिस बुलाया और बहुत तारीफ की। बाद में चलकर अनिल कपूर ने बॉलीवुड करियर में एक से बढ़कर फिल्में दीं।

जब वाकई में सुपरस्टार को भिखारी समझ बैठीं जया

संजीव कुमार और जया बच्चन 1970-80 के दौर में सुपरस्टार रहे हैं। दोनों में काफी गहरी दोस्ती रही हैं। दोनों ने एक साथ कई क्लासिकल और सदाबहार फिल्में दी हैं जो आज भी सिने प्रेमियों की पसंद है। दोनों ने अगल-अलग फिल्मों में अपने किरदार से दर्शकों का मनोरंजन किया। संजीव और जया से जुड़ा एक रोचक किस्सा करीब 49 पुराना है। जब संजीव संग जया बच्चन फिल्म नया दिन नई रात की शूटिंग कर रही थीं। फिल्म के एक सीन में संजीव को ऐसे भिखारी का रोल करना था जिसे कोढ़ था। उस भिखारी के रोल में संजीव कुमार ने इतना उम्दा मेकअप किया था कि सेट पर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए कि वह संजीव कुमार ही हैं। इसके बाद जया को सोते हुए देख उन्होंने सेट पर जाकर उनसे भीख मांगना शुरू कर दिया। फिर जया बच्चन ने सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए कह दिया। सिक्योरिटी भिखारी बने संजीव को बाहर निकालने को आतुर हो गए। तभी संजीव ने अपनी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। संजीव की आवाज सुन कर सेट पर मौजूद हर कोई शॉक्ड रह गया। वहीं जया भी भौंचक्का रह गई और अपनी बात पर काफी शर्मिंदा हो गई। हालांकि बाद में उन्होंने संजीव से माफी मांगी और उनकी तारीफें भी कीं।

जब सनी देओल की वजह से धर्मेंद्र को लगा करोड़ों का चूना, डूबे 39 करोड़!

सनी देओल बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा कलाकारों में शामिल हैं जो पिछले चार दशकों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। सनी देओल ने बॉलीवुड डेब्यू साल 1983 में आई फिल्म 'बेताब' से किया था। पिछले 40 सालों में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को करोड़ों का मुनाफा हुआ है। हालांकि जब खुद साल 1999 में सनी देओल ने एक्टिंग के साथ ही साथ फिल्मों का निर्देशन करने का फैसला किया तो, देओल फैमिली को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था। बेटे सनी की एक जिद से धर्मेंद्र की लुटिया डूब गई थी। वह समय देओल परिवार के लिए बेहद खराब साबित हुआ था।

दरअसल, साल 1999 में सनी देओल अपने छोटे भाई बॉबी देओल के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। इस फिल्म का नाम लंदन था। इस फिल्म में बॉबी के साथ करिश्मा कपूर कास्ट की गई थीं। वहीं इस फिल्म का निर्देशन गुरिंदर चड्ढा कर रही थीं। हालांकि, सनी और गुरिंदर के बीच ऐसा विवाद हुआ कि वह गुरिंदर फिल्म से हटा कर खुद डायरेक्टर बन बैठे। जब इस फिल्म से गुरिंदर चड्ढा का पत्ता साफ हुआ तो, फिल्म की टाइटल के साथ ही इसकी लीड एक्ट्रेस भी बदल गई। सनी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म नाम लंदन से दिल्लगी कर दिया गया, वहीं करिश्मा की जगह उर्मिला मातोंडकर आ गई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म 60 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई थी। हालांकि बेहतरीन स्टारकास्ट होने के बाद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 21 करोड़ का कारोबार कर सकी। यानी सनी को इस फिल्म की वजह से कम के कम 39 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

आदमी रिपेयर सेंटर

हमारा मोबाइल महीने भर से रिपेयरिंग के लिए मोबाइल अस्पताल में भर्ती है। पानी चला जाने के चलते उसकी चार्जिंग होना बंद हो गया था। अंधा, गूंगा, बहरा हो गया है मोबाइल। रिपेयरिंग सेंटर वालों ने बताया कि चार्जिंग होने लगी, रोशनी भी आ गई लेकिन आवाज अभी नदारद है। मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा।

हमने कहा- बदल दो। बताया गया कि रिपेयरिंग के पहले आधे पैसे जमा करवाने होंगे। हमें लगा कि मोबाइल न हुआ आईसीयू में भर्ती आदमी हो गया। ऑपरेशन तभी होगा जब एडवांस पैसा जमा करोगे। अस्पताल का डर होता होगा कि आदमी ठीक होकर फुट लिया तो पैसे डूब जाएंगे। लेकिन मोबाइल के तो पैर नहीं है। रिपेयरिंग चार्ज से कई गुने ज्यादा का मोबाइल जमा है लेकिन आधा पैसा एडवांस में चाहिए।

खैर, गए। मोबाइल देखा। कमर में कागज बंधा था, पट्टी की तरह। आन किया तो सब डाटा, फोटो दिखे। लेकिन आवाज गोल। मोबाइल बेचारा न बोल पा रहा था न सुन पा रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था हमें यहां से ले चलो। हमने उसको प्यार से सहलाते हुए दिलासा दिया- ले चलेंगे बेटा, बस जरा ठीक हो जाओ। ये तो हुई मोबाइल की बात। जो पार्ट खराब हुआ बदल दिया गया। फिर से टनाटन चलने लगेगा। बड़ी बात नहीं कल को आदमी की रिपेयरिंग भी इसी तरह होने लगे। आदमियों के भी रिपेयर सेंटर खुल जाएं।

आदमी रिपेयर सेंटर में हर अंग को बदलने की सुविधा होगी। आदमी मोटा हो गया लेकिन टांगें पतली हैं तो टांगें बदल जाएंगी। सांस की तकलीफ है, फेफड़े नए डाल देंगे। नजर कमजोर है, नई आंख लगवा लो। चेहरे पर दाग हैं, स्किन बदलवा लो। कोई महिला अपने बच्चे को ले जाएगी और कहेगी- भाई साहब बेटे को चीजें जल्दी याद नहीं होती। इसकी मेमोरी चिप बदल दो।

पिता लोग अपनी बेटियों को जमा कराएंगे- इसके दिमाग से प्यार का भूत इरेज कर दो। खानदान की इज्जत का सवाल है। मुकदमों में फंसे लोग अपने खिलाफ गवाह की मेमोरी चिप में अपने हिसाब से यादें ठेल देंगे। बच जाएंगे।

कोई आदमी अपनी औरत के चेहरे की स्किन चमकदार करवाने के भर्ती कराएगा और बाद में फोन करके उसकी आवाज भी थोड़ा धीमे कर देना। चिल्लाती बहुत है। पैसे की चिंता न करो। मैं दे दूंगा।

कोई औरत अपने आदमी को लेकर आएगी- इनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही। फेफड़े बदल दो। अलग से कहेगी- भाई साहब इनकी मेमोरी फाइल से इनकी प्रेमिका का नाम डिलीट कर दो। जब देखो तब उसी को पढ़ते रहते हैं। कोई नेता सैकडों लोगों को लिए आएगा और कहेगा- इनके दिमाग में हमारी पार्टी की विचारधारा और हमारे नेता की जयकार फीड कर दो। चुनाव आने वाले हैं। फिर तो स्कीम भी चलेंगी। पुराना आदमी लाओ, नया ले जाओ। ऑफर सीमित। भुगतान किस्तों में।

एक्सीडेंट में बहुत टूट-फूट हो गई तो नया शरीर मिल जाएगा अस्पताल में। आदमियों की कास्टिंग, फोरजिंग मौजूद होंगे अस्पतालों में। आदमी के हिसाब से शरीर की मशीनिंग हो जाएगी। मेमोरी और दीगर चीजें चिप में कॉपी करके फिट कर दी जाएंगी। पता चला रिपेयर होने के बाद आदमी के स्वभाव में कोई बदलाव आया तो परिवार वाले कहेंगे- जब से रिपेयर होकर आए हैं तबसे चिड़चिड़े हो गए हैं। पहले शांत रहते थे! या फिर यह कि- रिपेयर होने के बाद सुधर गए हैं। सारे खुराफाती वायरस निकल गए!

कभी-कभी कुछ बवाल भी हो शायद। पता चला कि डॉक्टर ने तमाम हिंदू आदमियों के दिमाग में कुरान डाउनलोड कर दीं। मुसलमान लोगों के दिमाग में गीता के श्लोक जमा हो गए। पता चला कोई मार्क्सवादी आदमी रिपेयर होकर आया तो उसके दिमाग से दास कैपिटल गायब है और उसकी जगह एक के बदले चार फ्री तथा ऑफर सीमित जल्दी करें की तमाम स्कीमें भरी हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था के हिमायती के दिमाग में लाइसेंसी जमाने की योजनाएं कब्जा किए हैं।

सरकारों को भी सुविधा होगी। नई सरकार के आने पर राज्यपाल बदलने नहीं पड़ेंगे। केवल पुरानी पार्टी की चिप निकालकर अपनी पार्टी की चिप लगवा देंगे। अफसरों के तबादलों की जगह उनकी चिपों के तबादले होंगे। सब लोग नई सरकार के मसौदे के हिसाब से काम करने लगेंगे। सरकारों को सहूलियत होगी कि वे अपने हिसाब से मीडिया और बुद्धिजीवियों के दिमाग में अपने हिसाब से चिपें फिट करवा लेंगे। देश चाहे बर्बाद हो रहा हो लेकिन वे देश को बताते रहेंगे- देश का विकास हो रहा है। सबके अच्छे दिन आ रहे हैं।

हम भी क्या-क्या फालतू सोचने लगे हैं आजकल। लगता है दिमाग खराब हो रहा है। रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी।

● **अनूप शुक्ल**

PRESENTING

Our new corporate identity

JKcement

A SOLID LEGACY OF TRUST

The trunk spreads wide
The branches reach high
Spurring us on
To reach for the sky.
'Y' for our founding father
Late Shri Yadupati Singhania ji

Energy and sustainability
Define our Abundance Tree.
Green is our vision
Grey, our foundation
Blue is the limitless sky of opportunities
That inspires our transition.

JK Cement Ltd.
Registered Office : Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh. Tel : 0512 2371478-81.
Corporate Office : Padam Tower, 19, DDA Community Centre, Okhla, Phase - 1
New Delhi - 110020. Tel.: 011 - 49220000

www.jkcement.com

एन सी एल
NCL

UNSTOPPABLE ENERGY.....

Milestones

- Highest Coal Production 131.17 MT
- Dispatched all time highest offtake of 133.51 MT
- Highest OBR of 462.10 MCuM

Northern Coalfields Limited

A Miniratna Company

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Singrauli (M.P). 486889

/northerncoalfields @NCL_SINGRAULI /northerncoalfields